

# राजस्थान सुजस



50 जिलों और  
10 संभाग का हमारा  
**राजस्थान**



  
75<sup>वें</sup> स्वतंत्रता दिवस  
की  
शुभकामनाएं





# तीज की सवारी



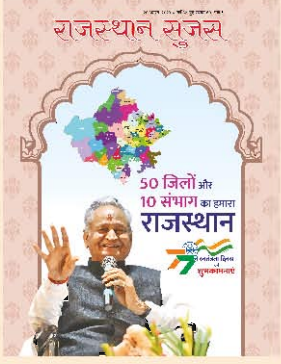
जयपुर में दो दिवसीय तीज फेस्टिवल के पहले दिन 19 अगस्त को चांदी की पालकी में सोलह शृंगार से सुशोभित तीज की सवारी निकली। तीज को ऊंट, घोड़े और बैलों के साथ एक रथ और पालकी में ढोल बजाते हुए लाया गया। दूसरे दिन बूढ़ी तीज की सवारी निकली। तीज की सवारी के आगे प्रदेशभर से आए प्रसिद्ध लोक कलाकारों ने कालबेलिया नृत्य, गैर नृत्य, बहुरूपिया, मशक वादन, कठपुतली नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य आदि की प्रस्तुतियां दीं।

आलेख और छाया : राजेंद्र शर्मा





# सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान का मासिक



प्रधान संपादक  
पुरुषोत्तम शर्मा

संपादक  
अलका सक्सेना

सह-संपादक  
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

उप-संपादक  
सम्पत राम चान्दोलिया  
आशाराम खटीक

सहायक संपादक  
महेश पारीक

आवरण छाया  
पदम सैनी

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग  
प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, जयपुर

संपर्क  
संपादक

राजस्थान सुजस (मासिक)  
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग  
सचिवालय, जयपुर-302005  
मो. 98292-71189, 94136-24352

e-mail  
editor@sujas@gmail.com  
publication.dipr@rajasthan.gov.in  
Website  
www.dipr.rajasthan.gov.in



वर्ष : 32 अंक 08

इस अंक में

अगस्त, 2023

## राजस्थान मिशन 2030

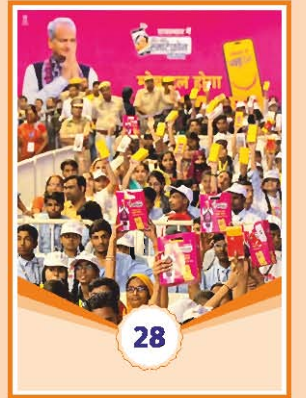


## फोटो फीचर

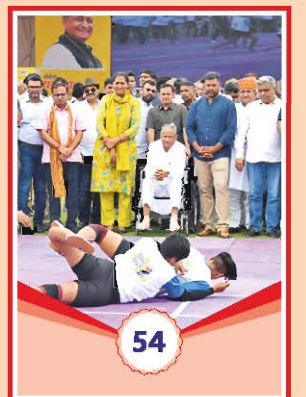


लोक जीवन	02
संपादकीय	04
लाभार्थी संवाद	08
जिलों और संभागों का पुनर्गठन	10
राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी	12
आजादी के परवानों की रचनाएं	16
स्वतंत्रता सेनानी स्मृति कक्ष	19
राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएं	20
जोधपुर : स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाएं	22
सैनिक कल्याण	24
सीपीएम भारत क्षेत्र सम्मेलन	26
अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना	32
विधायक आवास परियोजना	34
सखी सम्मेलन	36
लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना	37
डायल फ्यूचर	38
गिंग कर्मकार विधेयक	39
मृत शरीर का सम्मान विधेयक	40
सामयिकी	41
Tribal Development In Rajasthan	49
आदिवासी कल्याण	50
सद्भावना दिवस	56
रक्षाबंधन	58
धरोहर	59
तब और अब	60

## इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना



## ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक



राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें।

कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editor@sujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।



## सार्वकालिक मार्गदर्शक हैं स्वतंत्रता सेनानियों के विचार

77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हमने लहराते तिरंगे के नीचे खड़े होकर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद किया। स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्र नागरिक के रूप में हम कितने भाग्यशाली हैं। आजादी दिलाने के साथ स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसे अनेक सिद्धांत और आदर्श प्रस्तुत किए जिन्हें अपनाकर हम समाज और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अभियान में आत्मशक्ति, साहस, संघर्ष, सत्याग्रह, अहिंसा, आपसी तालमेल और सभ्यता को मानवीय समाज के विकास में नया महत्व प्रदान किया। उनके ये सिद्धांत व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को उन्नति की दिशा देते हैं और शासन, प्रशासन में मार्गदर्शन करते हैं।

विकेंद्रीकरण महात्मा गांधी का एक प्रमुख सिद्धांत है। मौजूदा समय के कल्याणकारी राज्य में प्रशासन की भूमिका का अत्यधिक विस्तार हुआ है और वर्तमान जरूरतों व आमजन की सहूलियतों को ध्यान में रखकर प्रशासन को गढ़ा और ढाला जा रहा है। प्रशासन के विकेंद्रीकरण की इन जरूरतों को ध्यान में रखकर राजस्थान में नए जिलों और संभागों का गठन किया गया है। राजस्थान में अब 50 जिले और 10 संभाग होने से प्रशासनिक इकाइयों की क्षमताएं बढ़ेंगी और आमजन के कार्य नजदीक ही सुगमता से हो सकेंगे।

कल्याणकारी राज्य की भूमिका को अहमियत देते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य में लगभग एक करोड़ चार लाख से अधिक परिवारों को हर माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण किया जा रहा है। राज्य में महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच और जुड़ाव को सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत चरणबद्ध रूप से चिरंजीवी परिवारों की लगभग एक करोड़ पैंतीस लाख से अधिक महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देने की योजना का शुभारंभ किया गया है। इससे वे स्वयं योजनाओं से लाभान्वित होने के साथ अन्य महिलाओं को जागरूक कर समाज सेवा भी कर सकेंगी। प्रदेश अब राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी एक्ट के साथ हर परिवार की न्यूनतम आय तय करने और गिंग वर्कर्स वेल्फेयर एक्ट व फंड बनाने वाला भी एकमात्र राज्य बन गया है। खेल प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी आलंपिक खेल-2023 आयोजित किए जा रहे हैं जिनके 7 खेलों में लगभग 60 लाख खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इन खेलों से भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे।

स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ प्रदेश के विकास के विभिन्न आयामों को समेटे राजस्थान सुजस का अगस्त, 2023 का अंक प्रस्तुत है।

(पुरुषोत्तम शर्मा)

प्रधान संपादक



# राजस्थान मिशन 2030



**मु**ख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस-2023 के अवसर पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्यस्तरीय समारोह को संबोधित किया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अमर शहीदों को नमन किया और प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। उनके उद्बोधन के प्रमुख अंश इस प्रकार हैं:

## 2030 तक प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना है

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रहनुमाई में अहिंसा के पथ पर आगे बढ़कर देश ने अपना मजबूत लोकतंत्र कायम रखा है। अब इसकी रक्षा करना हम सभी की बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान के अनुरूप राज्य सरकार प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक समानता को बढ़ावा देने और आमजन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार नीति-निर्देशक तत्वों की पालना करते हुए कार्य कर रही है। राज्य की जनहितैषी योजनाओं से हर व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। महंगाई से प्रदेशवासियों को आजादी मिली है। अब राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश को देश का अग्रणी और सर्वोत्तम राज्य बनाना है। इसमें समाज के सभी वर्गों का योगदान बेहद जरूरी है।

## आज उत्साह का दिन, कल होगा उम्मीदों से भरा

इस बार का स्वाधीनता दिवस राजस्थान के लिए एक नई उम्मीद वाला दिन है। हम सभी 17 नए जिलों के निर्माण के साथ 50 जिलों के राज्य के रूप में यह पावन दिवस मना रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल

दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। इसमें लगभग 60 लाख खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भविष्य में अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ी तैयार होंगे।

## देश में राजस्थान है आगे

सामाजिक सुरक्षा के लिए राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बन गया है। प्रदेश अब राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी एक्ट के साथ हर परिवार की न्यूनतम आय तय करने, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट व फंड बनाने और ओपीएस पुनः लागू करने वाला भी एकमात्र राज्य बन गया है। महंगाई राहत कैंपों की अभिनव पहल से प्रदेशवासियों को 10 योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित हुआ है। कैंपों में लगभग 1.95 करोड़ परिवारों में से 1.82 करोड़ परिवार पंजीकरण करा चुके हैं।

## आपका टैक्स, आपको समर्पित

कुशल वित्तीय प्रबंधन से जनहितैषी बजट घोषणाएं लागू की गईं। राज्य सरकार आमजन के टैक्स को उन्हीं के हितों में समर्पित कर रही है। कोविड काल में भी चिकित्सा व्यवस्था में कमी नहीं रखी गई, जिससे प्रदेश कोविड प्रबंधन में मॉडल साबित हुआ। राज्य सरकार ट्रस्टी के रूप में प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी बनाने के लिए संकल्पित है।

## हमारी योजनाओं की पूरे देश में सराहना

हमारी योजनाओं की पूरे देश में सराहना हो रही है। इनमें स्वास्थ्य का





अधिकार, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान योजना, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून (महात्मा गांधी नरेगा और इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन रोजगार की गारंटी), लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम हजार रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिए जाने की सराहना हो रही है।

साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक करने पर उम्रकैद की सजा के प्रावधान करने, 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरी एवं निजी क्षेत्र में लाखों अवसर प्रदान करने, उड़ान योजना में प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन देने, इंदिरा रसोई योजना में 8 रुपए में भोजन, गोशालाओं को 9 और नंदीशालाओं को 12 माह अनुदान देने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने, लंपी रोग में मृत गौवंश पर 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने, कामधेनु बीमा योजना लाने, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में स्मार्टफोन दिए जाने, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में 500 बच्चों को प्रतिवर्ष विदेश में पढ़ने का अवसर प्रदान करने पर देशवासी राजस्थान की सराहना कर रहे हैं।

### किसानों, पशुपालकों को धन्यवाद और बधाई

मुख्यमंत्री ने किसानों को अनाज, तिलहन, दलहन, चना, बाजरा, सरसों उत्पादन और पशुपालकों को दूध एवं ऊन उत्पादन में राज्य को देश में प्रथम बनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने देश में पहली बार स्वास्थ्य का अधिकार लागू कराने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान योजना के लिए चिकित्सकों और मेडिकल फ्रेटर्निटी को, केंद्र सरकार के प्रशासनिक

सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की रेटिंग में राजस्थान को देश में जनसमस्या निराकरण में सबसे आगे लाने के लिए राज्य कार्मिकों को, मजबूत आधारभूत संरचनाओं के लिए इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और मजदूरों को धन्यवाद दिया।

### महिलाओं का मान-सम्मान हमारी जिम्मेदारी

बालिकाओं एवं महिलाओं का मान-सम्मान बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए उनसे छेड़छाड़, दुर्व्यवहार करने वाले मनचलों का पुलिस थानों में हिस्ट्रीशीटर की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा। उन्हें सरकारी नौकरियों से वंचित करने के लिए नियमों में बदलाव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वितों के जीवन में आए बदलाव के बारे में भी अपने विचार साझा किए।

### राज्य हित में बड़ी घोषणाएं

1. जयपुर के रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत ईसरदा बांध से भरा जाएगा। इस पर 1 हजार 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे आंधी, जमवारामगढ़, आमेर, जालसू, गोविंदगढ़, शाहपुरा, विराटनगर, पावटा, कोटपूतली, थानागाजी एवं बानसूर के लिए पेयजल योजना बनाई जा सकेगी।
2. 13 जिलों के लिए महत्वपूर्ण ईआरसीपी की डीपीआर में वंचित रहे बांधों को जोड़ेंगे। इससे दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर एवं अलवर के 53 बांधों को ईआरसीपी से जोड़कर भरा जाएगा। इससे ईआरसीपी परियोजना की लागत 1 हजार 665 करोड़ रुपए बढ़ेगी





और 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) परिवारों के साथ-साथ जिन नॉन-एनएफएसए परिवारों को कोविड में आर्थिक सहायता मिली थी, उन्हें भी अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निःशुल्क राशन किट उपलब्ध कराए जाएंगे।
4. चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में सड़क दुर्घटना में घायलों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को 5 हजार रुपए एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है। अब यह राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपए की गई है।
5. इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में प्रथम चरण में 40 लाख बालिकाओं व महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। अगले चरण में करीब 1 करोड़ स्मार्टफोन देने की गारंटी के लिए 20 अगस्त से गारंटी कार्ड दिए जाएंगे। इन्हें दिखाकर महिलाएं स्मार्टफोन निःशुल्क ले सकेंगी।
6. कांस्टेबल से लेकर पुलिस महानिदेशक स्तर तक सभी पुलिसकर्मियों को राजस्थान पुलिस के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने का विशेष “राजस्थान पुलिस पंचसती मेडल” दिया जाएगा।
7. पुलिस विभाग में अभी कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था परीक्षा के माध्यम से की जाती है। अब बदलाव कर इन पदों तक की पदोन्नति समयबद्ध डीपीसी के माध्यम से होगी।

#### योजनाबद्ध तरीके से स्थापित किए आयाम

मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में पिछले साढ़े 4 वर्षों में 342 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 30 संस्कृत विद्यालय खोले गए हैं। 1,779 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया गया। राज्य में 2,500 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 5 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वर्तमान सरकार में 309 नवीन महाविद्यालय, जिनमें से 132 महिला महाविद्यालय खोले गए हैं। साथ ही, 51 कृषि, 6 आयुर्वेद, 12 मेडिकल, 26 नर्सिंग, 21 नवीन शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय खोले गए हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में 1,674 नवीन उप स्वास्थ्य, 353 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 65 उप जिला अस्पताल, 27 जिला अस्पताल तथा 13 सैटेलाइट अस्पताल खोले गए। साथ ही, 277 पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया। राज्य में 11,700 बेड्स की क्षमता बढ़ी है। साथ ही, 1,000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर, 82 ब्लॉक आयुष अस्पताल, 225 ब्लॉक होम्योपैथी औषधालय तथा 101 नवीन यूनानी चिकित्सालय भी खोले गए हैं।

राज्य के लगभग 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत न्यूनतम 1 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। इस पर प्रतिवर्ष 38 हजार करोड़ रुपए से अधिक का व्यय हो रहा है। पालनहार योजना में 6.87 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश की गोशालाओं को अब तक 2 हजार 882 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है।

प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए 17 नवीन जिले, 72 नवीन नगरपालिकाएं, 85 तहसील, 125 उप तहसील, 1 हजार 131 पटवार मंडल तथा 1 हजार 284 राजस्व ग्राम का सृजन किया गया है। साथ ही, प्रदेश में 11 नवीन एडीएम तथा 35 एसडीएम कार्यालय खोले गए हैं। •



# लाभार्थी संवाद

प्रदेशवासियों के सुख-दुःख में  
भागीदार बनकर कार्य कर रही  
राज्य सरकार



**आ**मजन के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन सरकारों की जिम्मेदारी है। राजस्थान सरकार प्रदेशवासियों के सुख-दुःख में भागीदार बनकर अनेक अभूतपूर्व कार्य कर रही है। महंगाई से प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर के साथ ही महंगाई से राहत देने वाली 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 27 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के 36.76 लाख लाभार्थियों के खातों में 155.92 करोड़ रुपये के लाभ का हस्तांतरण किया। इसमें अप्रैल माह के डीबीटी के लाभ से शेष रहे 1.72 लाख उपभोक्ताओं को 7.32 करोड़ रुपये के साथ ही मई माह के 16 लाख 71 हजार उपभोक्ताओं को 70 करोड़ 86 लाख रुपये एवं जून माह के 18 लाख 33 हजार उपभोक्ताओं को 77 करोड़ 73 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए। इस प्रकार कुल 36 लाख 76 हजार उपभोक्ताओं को 155 करोड़ 92 लाख रुपये ट्रांसफर किए। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के पंजीकृत

**अलका सक्सेना**  
अतिरिक्त निदेशक, जनसंपर्क

उपभोक्ताओं को लाभ हस्तांतरण का यह दूसरा चरण है। इससे पहले 5 जून को मुख्यमंत्री ने लगभग 14 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं के खातों में करीब 60 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई थी।

## जनकल्याण का संकल्प हो रहा साकार

राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर में महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से 10 योजनाओं के लाभ की गारंटी दी जा रही है, जिनमें से 8 योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को 2,000 यूनिट प्रतिमाह फ्री बिजली,





महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार तथा कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में न्यूनतम 1,000 रुपए पेंशन प्रतिमाह, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना गारंटी के तहत 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को निःशुल्क फूड पैकेट का वितरण 15 अगस्त, 2023 से प्रारंभ हुआ। इसके अलावा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना भी शीघ्र लागू होगी।

### न्यूनतम आय की गारंटी का कानून बनाने वाला पहला राज्य

राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां कानून बनाकर न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान की गई है। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ एकल नारी, विधवा, बुजुर्ग एवं निशक्तजनों को पेंशन दी जा रही है। न्यूनतम पेंशन की राशि 1 हजार रुपए कर दी गई है। राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। पालनहार योजना के अंतर्गत करीब 6 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना उनके जीवन को सही दिशा देने में मददगार साबित हो रही है। •



## महंगाई से मिली राहत

- मई एवं जून की सब्सिडी का पैसा खाते में आ गया है। एकल नारी के तौर पर मिल रही मेरी पेंशन भी बढ़कर अब 1000 रुपए हो गई है। सरकार की मदद से बच्चों को पढ़ाने में सुविधा हो गई है।

श्रीमती पप्पन शर्मा, बूंदी

- 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने से बहुत खुशी हुई। राज्य सरकार की योजनाओं से सभी महिलाएं खुश हैं। रोडवेज में किराया आधा करने से भी बहुत फायदा हुआ है।

श्रीमती सुनीता, चित्तौड़गढ़

- पालनहार योजना में मिल रही सहायता राशि बढ़कर 1,500 रुपए हो गई। 125 दिन के रोजगार के साथ ही अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे बहुत खुश हूँ। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाऊंगी।

श्रीमती पवन कुमारी, धौलपुर

- गैस सिलेंडर सस्ता होने से हमारी चिंता दूर हो गई। खाते में पैसे आ गए हैं। राज्य सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं।

श्रीमती मंजू देवी, जैसलमेर

- महंगाई राहत कैम्प में मुझे 7 योजनाओं का लाभ मिला। 500 रुपए में गैस सिलेंडर सहित अन्य योजनाओं के लाभ से संबल मिला है।

श्रीमती चांद कंवर, दूदू

- परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। पहले गैस सिलेंडर खत्म होने से पूर्व ही चिंता सताने लग जाती थी। लेकिन अब 1150 की बजाय 500 रुपए में ही सिलेंडर मिलने से राहत मिली है।

श्रीमती सीमा भांबी, जयपुर



# तरक्की की राह हुई अब और आसान



## 50 जिलों और 10 संभाग का हुआ हमारा राजस्थान



**7** अगस्त, 2023 की ऐतिहासिक सुबह जब भास्कर की रश्मियां धीरे-धीरे पूर्णता को प्राप्त कर रही थी, उसी समय राजस्थान की राजधानी जयपुर में वैदिक मंत्रोच्चार और हवन की आहुतियों के बीच राजस्थान एक नया आकार और नया स्वरूप ग्रहण कर रहा था। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बिड़ला सभागार में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में जब राज्य के नवसृजित जिलों की शिला पट्टिकाओं का अनावरण किया तो मानो करोड़ों प्रदेशवासियों के बरसों पुराने सपनों को पंख लग गए।

स्थापना दिवस समारोह में अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपूतली-बहरोड़, बालोतरा, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, जयपुर ग्रामीण, नीम का थाना, डीग, फलौदी, डीडवाना-कुचामन, जोधपुर ग्रामीण, सलूंबर, दूदू, केकड़ी, सांचौर तथा शाहपुरा जिलों के साथ ही बांसवाड़ा, सीकर और पाली संभाग की स्थापना हुई। इस तरह 33 जिलों और 7 संभागों वाला हमारा राजस्थान 50 जिलों और 10 संभागों वाला प्रदेश हो गया।

नए जिलों और संभागों के सृजन से राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का विकेंद्रीकरण होगा, उनकी क्षमताएं बढ़ेंगी और कानून व्यवस्था अधिक मजबूत होगी। आमजन के प्रशासनिक कार्य अब नजदीक ही सुगमता से होंगे। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जनभावनाओं में घुली यह राजस्थान की एक नई सकारात्मक शुरुआत है। राज्य सरकार ने 'हर घर न्याय, हर घर खुशहाली' की संकल्पना के साथ लगभग 1,500 राजस्व गांव, 125 उप तहसील, 85 तहसील, 35 एसडीएम और 13 एडीएम कार्यालय का गठन किया है। इससे आमजन को प्रशासनिक तथा न्यायिक कार्यों में सुगमता होगी। लंबित राजस्व मामलों का भी समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा।

**सुधाकर सोनी**

सहायक जनसंपर्क अधिकारी

### इसलिए जरूरत थी नए जिलों की

वर्ष 1956 में 2 करोड़ की जनसंख्या पर राज्य में 26 जिले थे। उसके बाद से अब तक 67 साल में प्रदेश की आबादी तो 3 गुना बढ़ गई लेकिन नए जिले सात ही बने। ऐसी स्थिति में लोगों को अपने कार्य के लिए दूर-दराज के गांवों से जिला मुख्यालयों तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। इसके अलावा जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल विस्तृत होने से प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने कार्यों के निष्पादन में भी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता था। इस तरह जनहित एवं विकास कार्यों में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता था। ऐसे में राज्य में नए जिलों के गठन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नए जिलों के गठन के संबंध में सुझाव देने के लिए 21 मार्च, 2022 को सेवानिवृत्त आईएएस श्री रामलुभाया की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नए जिलों और संभागों के गठन का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने इस समिति का कार्यकाल 6 माह बढ़ा दिया, ताकि भविष्य में आमजन की न्यायोचित मांगों का परीक्षण कर पूरा किया जा सके।

### नए जिलों का गठन

सीकर एवं झुंझुनूं जिलों का पुनर्गठन कर नीमकाथाना नया जिला बनाया गया तथा जालौर जिले का पुनर्गठन होने से सांचौर जिला अस्तित्व में आया। अजमेर, पाली एवं भीलवाड़ा जिले के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप ब्यावर जिला





बना। अजमेर एवं टोंक जिलों में से केकड़ी नया जिला बना। नागौर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला डीडवाना-कुचामन गठित किया गया। सवाई माधोपुर एवं करौली जिलों का पुनर्गठन कर गंगापुर सिटी को आकार दिया गया। जोधपुर जिले का पुनर्गठन कर फलोदी और जोधपुर ग्रामीण जिले बनाए गए। इसके साथ ही जयपुर जिले के पुनर्गठन से दूदू तथा जयपुर ग्रामीण जिले बने। जयपुर एवं अलवर जिलों का पुनर्गठन कर कोटपूतली-बहरोड़ नया जिला बनाया गया। अलवर जिले का पुनर्गठन कर खैरथल-तिजारा नया जिला बनाया गया। उदयपुर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला सलूबर बनाया गया। भीलवाड़ा जिले का पुनर्गठन कर नया जिला शाहपुरा सृजित किया गया। बाड़मेर जिले का पुनर्गठन कर बालोतरा नया जिला बना। भरतपुर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला डीग गठित किया गया। श्रीगंगानगर एवं बीकानेर जिलों का पुनर्गठन कर अनूपगढ़ नया जिला बनाया गया। क्षेत्रफल के हिसाब से अब जैसलमेर सबसे बड़ा और दूदू सबसे छोटा जिला होगा।

### संभागों का स्वरूप भी बदला

नए बदलाव के फलस्वरूप संभागों की संख्या और स्वरूप में भी बदलाव आया है। सीकर, पाली और बांसवाड़ा नए संभाग बनने से अब राज्य में संभागों की संख्या सात से बढ़कर दस हो गई है। जिलों की संख्या के लिहाज से जयपुर और अजमेर संभाग सात-सात जिलों के साथ सबसे बड़े और बांसवाड़ा तीन जिलों के साथ राज्य का सबसे छोटा संभाग बन गया है। जयपुर संभाग में जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपूतली-बहरोड़, दौसा, खैरथल-तिजारा एवं अलवर जिले को शामिल किया गया है, जबकि अजमेर संभाग में अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना-कुचामन एवं शाहपुरा जिलों को जगह

दी गई है। सीकर, झुंझुनूं, नीमकाथाना और चूरू जिले अब नवगठित सीकर संभाग का हिस्सा होंगे। नए संभाग पाली में पाली, जालौर, सांचौर एवं सिरोही को शामिल किया गया है, वहीं बांसवाड़ा संभाग में बांसवाड़ा, इंगरपुर तथा प्रतापगढ़ जिले शामिल हैं। बीकानेर संभाग में बीकानेर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिले शामिल हैं। भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी के साथ ही सवाई माधोपुर जिले को जगह दी गई है। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ को शामिल किया गया है। जोधपुर संभाग में जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर एवं बालोतरा जिले आ गए हैं। इसके अतिरिक्त उदयपुर संभाग में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूबर जिलों को शामिल किया गया है।

### नवसृजित जिलों में तेज गति से कार्य शुरू

नए जिलों और संभागों में प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। इनमें संभागीय आयुक्तों, जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षकों सहित आला अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। सरकार का विशेष फोकस इन जिलों और संभागों पर है। इन जिलों में तत्काल जिला स्तरीय अधिकारी एवं स्टाफ नियुक्त किए जा रहे हैं ताकि आमजन के कार्य सुगमता से हो सकें। विभिन्न विभागों में नए पदों का सृजन किया जा रहा है तथा जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्वतंत्रता दिवस पर नवसृजित जिलों में भव्य समारोहों का आयोजन किया गया। समारोहों में पुलिस बैंड की प्रस्तुति, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का समावेश किया गया। कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, लोक कलाकारों एवं आमजन ने भारी उत्साह के साथ शिरकत की। ●



# राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी



आज हम जिस स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं और जो स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं वह बहुत संघर्ष और त्याग के बाद मिला है। जब देश अंग्रेजों की गुलामी का दंश झेल रहा था उस दौर में कुछ ऐसे लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना बहुत कुछ या सब कुछ खोकर भी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से योगदान दिया था। आजादी की इस लड़ाई में राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों का भी सक्रिय योगदान रहा है। यहां की धरती ने कई स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया है जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोकर भी आजादी प्राप्त करने की जिजीविषा को जिंदा रखकर यथासंभव योगदान दिया जिनमें से कुछ आज भी हमारे बीच हैं।



## 95 वर्ष की आयु में भी युवाओं जैसा जब्बा

श्री कालिदास स्वामी

नवनिर्मित नीम का थाना जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र के कर्मठ और जुझारू श्री कालिदास स्वामी का नाम इस क्षेत्र के उन चुनिंदा स्वतंत्रता सेनानियों में शुमार है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। श्री कालिदास स्वामी ने हमेशा सादा जीवन तथा उच्च विचार वाले सिद्धांत को अपने जीवन में उतारकर उसी के अनुरूप जीवन जिया। इन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रभाकर, काव्य तीर्थ तक की शिक्षा भी ग्रहण की। एक सामान्य किसान परिवार में परवरिश होने के बावजूद इन्होंने अपने ज्ञान तथा प्रतिभा को इस कदर पल्लवित किया कि धीरे-धीरे इनकी पहचान एक बुद्धिजीवी तथा समाजसेवक के रूप हो गई।

श्री कालिदास स्वामी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के साथ-साथ सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से भी समाज के साथ जुड़े रहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विद्यार्थी जीवन में ये प्रजामंडल तथा चरखा संघ के साथ जुड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। स्वतंत्रता आंदोलन में इस प्रकार भाग लेने के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद सजा के रूप में इन्हें लगभग एक माह की कठोर कैद (19 मार्च 1946 से 13 अप्रैल 1946) का आदेश हुआ। जेल से रिहा होने के बाद भी इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में किसी न किसी रूप में अपना योगदान देना जारी रखा। आजादी के बाद इन्होंने शिक्षा के प्रचार-प्रसार को एक मिशन के रूप में लेकर अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से रींगस में एक हरिजन पाठशाला की शुरुआत की। इसी प्रकार इन्होंने 1958 में जैतूसर में ज्ञानोदय विद्यापीठ की स्थापना की।

साहित्य के प्रति अपने असीम लगाव के चलते इन्होंने शोषण नामक एकाकी नाटक, दादू चालीसा, दादू पंचधाम, दादूनामा, बालक बोध जैसी कई पुस्तकों की रचना कर साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। महिला सशक्तीकरण के अनेक कार्यों में इन्होंने सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई। साहित्यिक तथा सामाजिक योगदान के अतिरिक्त इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना सक्रिय योगदान दिया है।

जनता के बीच इनकी लोकप्रियता का यह आलम था कि दिसंबर, 1960 में पहली बार जैतूसर गांव के सरपंच के रूप में निर्वाचित होने के बाद 28 वर्षों तक इस पद पर आसीन रहे। रींगस नगरपालिका में मनोनीत पार्षद के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए देश के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 2012 में इन्हें सम्मानित किया।

इस आयु में भी इन्होंने सामाजिक कार्यों से मुंह नहीं मोड़ा है और मौजूदा समय में विभिन्न सामाजिक कार्यों से जुड़ी संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुड़े हैं।

(सहायक निदेशक, पूरण मल से हुई  
बातचीत पर आधारित)





## चोट के निशान आज भी उन दिनों की यादें ताजा करते हैं

श्री रामू सैनी

**दे** शभक्ति से ओतप्रोत सांगानेर के दादूदयाल नगर निवासी स्वतंत्रता सेनानी वैद्य श्री रामू सैनी से स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र करते ही उनका चेहरा चमक उठता है। श्री रामू सैनी बताते हैं कि मैं जब 16-17 साल का था तब मेरे चाचा कानजी सैनी मुझे स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में स्वतंत्रता सेनानियों की एक मीटिंग में ले गए। हमारे गांव खो नागोरियान से केवल मेरे चाचा ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। चाचा की लगन देखकर मैं भी उनके साथ हो लिया। हम दोनों अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में गुप्त रूप से भाग लेते थे। इस कारण हम अंग्रेजों की गिरफ्त में कभी नहीं आए। हम कई महीनों परिवार से दूर रहे। कभी रात को आते तो कभी सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर छोड़ना पड़ता था। ऐसे में सिर्फ रात को परिवार वालों से मिलकर सुबह अपने कपड़ों का झोला लिए हम बचते-

बचाते अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे। कई बार सभा और मीटिंगों के दौरान छापे में अंग्रेज हमें पकड़कर कलवाड़ा, खेजरोली, चौमूं से आगे इटावा भोपजी जैसे दूर जंगलों में छोड़ देते थे। वहां से आने के लिए हम भयानक जंगलों से होते हुए मीलों पैदल चलकर घर पहुंचते थे। तब इन जंगलों में शेर, चीते और जंगली सांपों की भरमार हुआ करती थी। ऐसे में जमींदारों के लोगों से बचकर भूखे-प्यासे भटकते हुए कई दिनों में वापस जयपुर पहुंचते थे। श्री रामू सैनी बताते हैं कि एक बार सभा करते हुए पकड़े जाने पर अंग्रेजों ने डंडों से मेरी पिटाई की, जिससे बाएं पैर की हड्डी में गंभीर चोट आई। कई दिनों तक पैदल नहीं चल सका। उस चोट के निशान आज भी उन दिनों की यादें ताजा करते हैं। कई आंदोलनों में भाग लिया आजादी की लड़ाई में उन्होंने श्री हीरालाल शास्त्री, श्री भोगीलाल पंड्या, श्री माणिक्य लाल वर्मा, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्री ओम दत्त शास्त्री तथा श्री रामचरण जोशी जैसे कई बड़े नेताओं के नेतृत्व में काम किया। उन्होंने 1942 के सत्याग्रह में भी भाग लिया। उसके बाद राष्ट्रकर्मी श्री भगवती प्रसाद गुप्ता के साथ महात्मा गांधी के अहमदाबाद स्थित आश्रम में भी गए। वह बताते हैं कि जब मैं गांधी जी से मिलने गांधी आश्रम गया तो वे काफी व्यस्त थे। व्यस्त होने के बावजूद स्वयं के लिए सूत कातते थे। गांधी जी बहुत तेज चलते थे, क्योंकि उनके पास समय की कमी होती थी। सारी चर्चाएं वह चलते-चलते ही कर लिया करते थे। उनका समय प्रबंधन देखकर मैं काफी प्रभावित हुआ।

(जनसंपर्क अधिकारी धर्मिता चौधरी से हुई  
बातचीत पर आधारित)



## जिस आजादी को हम बड़ी कीमत अदा करके लाए हैं उसे महफूज रखना

श्री उमराव सिंह

**चू** रू जिले के हमीरवास के रहने वाले श्री उमराव सिंह जब स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे तो यह नहीं जानते थे कि मौत क्या होती है। बस जज्बा था कि वतन आजाद हो और खुली हवा में सांस लें। फिर संगी साथी जो कर रहे थे, वही रास्ता इन्होंने भी पकड़ लिया।

उम्र के नौ दशक पार कर चुके श्री उमराव सिंह अब ज्यादा बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी आंखों में वही गर्व है, मानो कह रहे हों जिस आजादी को तुम भोग रहे हो, उसके लिए हमने बहुत सहा है। बड़ी कीमत अदा करके लाए हैं, इसे महफूज रखना।

उनकी इकलौती पुत्री श्रीमती राजकुमारी ने बताया कि इन्हें देश सेवा

करके गर्व होता है और हमें इन पर। करीब 14 साल के थे तभी वे आजादी के आंदोलन से जुड़ गए थे। एक अंग्रेज ने पकड़कर कहा था तू बच्चा है घर जाकर पढ़ाई पर ध्यान दे। तब इन्होंने कहा कि पहले देश को आजाद कराएंगे।

जब बड़े नेता जेल में थे, तब पीछे से कमान संभालने वालों में यह भी थे। रात दिन, नंगे पांव ही यह घूमा करते थे। कई बार भूखा रहना होता। पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। बीकानेर के महाराजा ने इन्हें पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्स भेजी तब यह रियासत छोड़ भूमिगत हो गए। चौधरी श्री कुंभाराम आर्य, अध्यापक श्री युधिष्ठिर इनके प्रेरणा स्रोत थे। वे इन्हें कहते तू हिम्मत वाला है, अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना है।

इनकी दादी ने अपने पांचों बेटों को फौज में भेज दिया था, जिनमें से दो स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनकी मां भी महिलाओं में जनजागृति फैलाती थी। आजादी के बाद इन्होंने फौज में रहकर देश सेवा की। नई पीढ़ी के साथ वह खुश रहते हैं, लेकिन प्रगति के शॉर्टकट फॉर्मूले इन्हें पसंद नहीं आते। कहते हैं, मेहनत करो, नींव मजबूत होगी तो आगे परेशानियां नहीं आएंगी।

(स्वतंत्र लेखिका वंदना सोनी से हुई  
बातचीत पर आधारित)





## हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के

श्री मनोहरलाल औदिच्य

**आ**जादी के महोत्सव की इस वेला में शतायु होने जा रहे उदयपुर के स्वतंत्रता सेनानी श्री मनोहरलाल औदिच्य से चर्चा हुई, तो तत्कालीन परिस्थितियां और आजादी के आंदोलन की घटनाएं मानो आंखों के सामने चित्रित सी हो गईं। स्वतंत्रता आंदोलन से उनका जुड़ाव तरुणाई में हुआ और एक बार आंदोलन से जुड़ने के बाद देश की आजादी ही मुख्य ध्येय बन गया। 99 वर्षीय औदिच्य आज भी जब उन दिनों को याद करते हैं तो उनका शरीर जोश से तन सा जाता है, आवाज में यकायक ललकार सा लहजा आ जाता है। वह बताते हैं मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन चलता था। कॉलेज आते-जाते समय प्रजामंडल के सर्वश्री मोहनलाल सुखाड़िया, भूरेलाल शैया, अंबालाल वैद्य, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंतराय मेहता आदि हमें रोककर आंदोलन से जुड़ने को कहते थे। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना रखा है, हम सूई भी हमारे देश में नहीं बना सकते, वह भी ब्रिटेन से आ रही है। हमारा क्राउन तक वे ले गए हैं। इस तरह हमारे जब्बे को जगाया और हम आंदोलन से जुड़ गए। रैलियां निकालते, नारे लगाते। 22 अगस्त 1942 को आधी रात पुलिस ने मुझे और कुछ साथियों को घर से गिरफ्तार कर लिया। जेल में मिट्टी की चबूतरी पर सोना पड़ता तथा कच्ची-पक्की रोटियां मिलतीं। उधर, युवाओं की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही नाथद्वारा, चित्तौड़, भीलवाड़ा से भी युवाओं की टीमें उदयपुर आ गईं और आंदोलन तेज हो गया। पुलिस ने एक-एक कर करीब 150 युवाओं को पकड़ लिया। साथ ही प्रजामंडल के नेताओं को भी

गिरफ्तार कर लिया गया। तत्कालीन महाराणा भूपालसिंह युवाओं के प्रति संवेदनशील थे, उन्होंने खाने के लिए पूड़ी-सब्जी की व्यवस्था कराई। चार सदस्यीय कमेटी बनाकर हम युवाओं को आंदोलन से दूर रहने की समझाइश के लिए भेजा। हमें आंदोलन नहीं करने की लिखित सहमति देने को कहा, लेकिन हमने नहीं दी। उधर, पूरे मेवाड़ में आंदोलन जोर पकड़ने लगा। इस पर 2 सितंबर, 1942 को युवा टीम को हिदायत देकर छोड़ दिया। जेल जाकर आने के कारण हमें कॉलेज से निकाल दिया गया। जैसे-तैसे पढ़ाई पूरी की और आंदोलन को भी गति देते रहे।

महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन उफान पर था। उधर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस अंग्रेजों से सशस्त्र लोहा लेने के लिए आजाद हिंद फौज खड़ी कर चुके थे। इससे घबराए अंग्रेज समझ चुके थे कि अब भारत को ज्यादा समय तक गुलाम नहीं रखा जा सकता, इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल के हथियार का आखिरी प्रहार करते हुए भारत-पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। 15 अगस्त, 1947 को देश आजाद हुआ। सुकून था कि इतनी कुर्बानियों के बाद भारत माता आजाद तो हुई, लेकिन विभाजन का घाव आज भी दिल में हरा है। आजादी की पहली सुबह और 75 साल दोनों देख पाना अपने आप में सुकूनदायक है। भारत को आजाद करने से पहले अंग्रेज भारत का बहुत शोषण कर चुके थे। 75-76 सालों में देश ने बहुत तरक्की है। कई मामलों में हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। आने वाले समय में भारत विश्व में सिरमौर बने यही सपना है। नई पीढ़ी को यह याद रखना चाहिए कि आज वे जिस आजाद देश में सांस ले रहे हैं उसे स्वतंत्र कराने के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी गई हैं। युवाओं को इतिहास पर गर्व करते हुए नए भारत के निर्माण में सहयोग करना चाहिए। आज अंग्रेज तो नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता जैसी चुनौतियों से लड़ने का वक्त है। आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हुए तथा अपना काम ईमानदारी से करते रहे तो भी देश की बहुत बड़ी सेवा होगी।

(सहायक जनसंपर्क अधिकारी, विनय सोमपुरा से हुई  
बातचीत पर आधारित)



## मातृभूमि के चरणों में बस अर्पण होने की अभिलाषा

श्री राधेश्याम भार्गव

**बा**रां जिले की छबड़ा तहसील के गांव बटावदापार, गोडिया मेहर के निवासी 86 साल के स्वतंत्रता सेनानी श्री राधेश्याम भार्गव से स्वतंत्रता संग्राम की बात करते ही उनका चेहरा चमक उठता है।

### 17 वर्ष की उम्र में ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हुए

भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं के भाषण और 15 अगस्त, 1947 को आजादी प्राप्त होने के साथ आने वाले बदलावों ने सन् 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए प्रेरणा देने का काम किया। मेरे मन में भी भारत के बचे हुए इलाकों को मुक्त कराने का संकल्प आया। उस समय मेरी उम्र मात्र 17 वर्ष थी और बारां संस्कृत विद्यालय में अध्ययन कर रहा था। तभी मेरे मिलने वाले साथियों ने गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने के लिए मुझे प्रेरित किया।

### गोवा मुक्ति आंदोलन के संघर्ष के दिन

11 अगस्त, 1955 को बारां से सर्वश्री धनराज लाल पटवा, मोहन बाल पटवा और नंदलाल गुप्ता के साथ दल में शामिल होकर कोटा से गोवा मुक्ति आंदोलन



के जत्थे में गोवा के लिए रवाना हुए। इस जत्थे के अध्यक्ष श्री स्वामी माथोदास एवं श्री आनंद सांडेकर थे। पूना में तिलक मुक्ति आंदोलन समिति के आह्वान पर 14 अगस्त को पूना एवं सामंतवाड़ी पहुंचकर गोवा की सीमा में समुद्री खाड़ी में स्टीमर से रात को लगभग 12 बजे पहुंचे। वहां के स्वयंसेवकों के साथ सुबह 6 बजे तुलजा कस्बे के सरकारी भवन पर ध्वजारोहण किया गया। सुरेंद्र, श्री नंदलाल गुप्ता और मैंने एक-दूसरे के सहयोग से इमारत पर चढ़कर पुर्तगाली झंडे को हटाकर तिरंगा ध्वज फहराया।

### कमांडर ने सैनिकों को सभी पर गोली चलाने का आदेश दिया

कोटा से गए सभी 39 साथियों के जत्थे ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त करने का नारा लगाया। इसी बीच पुर्तगाली सेना के कमांडर एवं सैनिकों ने आकर हमें घेर लिया एवं कमांडर ने सैनिकों को हम सभी पर गोली चलाने का आदेश दिया। शुरू के 2 फायर उन्होंने हवा में किए तथा तीसरा फायर जत्थे पर मशीनगन से किया गया जिसमें झालावाड़ जिले के रामगंज मंडी निवासी श्री पन्नलाल यादव गोली लगने से शहीद हो गए। हम सभी लोग भारत माता के नारे लगातार लगाते रहे। श्री पन्नलाल के शहीद होते ही कमांडर हम सभी जत्थे वालों को भी शूट करने का आदेश दे ही रहा था कि उसी समय संवाददाता ह्यूम आया और अनुचित रूप से जत्थे पर गोली चलाने पर एतराज प्रकट किया। इसके बाद कमांडर ने गोलीबारी बंद कर दी। हमारे जत्थे के लीडरों से टेपरिकॉर्डर पर बातचीत को टेप कर गोवा कमांडर ने जत्थे को अपने अधिकार में लेने एवं शहीद श्री पन्नलाल की लाश को जलाने का प्रयास किया जिसका हम सभी ने भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए विरोध किया। इसके

बावजूद कमांडर ने श्री पन्नलाल की लाश को अपने कब्जे में ले लिया।

### 38 लोगों को एक साथ कालकोठरी में किया बंद

हमारा 39 लोगों का जत्था ही गोवा सीमा में प्रवेश कर सका था। बाकी किसी को भी उन्होंने सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। हम शेष 38 लोगों को कमांडर ने कालकोठरी में बंद करने का आदेश दिया। कोठरी का क्षेत्रफल बहुत कम था। हम सभी 38 लोगों को लगभग एक घंटे बाद बाहर निकाला गया। घुटन की वजह से हम सभी लोग अचेतन अवस्था में थे। तभी हम पर डंडों और बंदूकों के बट से प्रहार किया गया और सभी को गाड़ी में भरकर सीमा की चौकी पर बरामदे में बिठा दिया।

रात को 1 बजे वायरलेस पर जत्थे को शूट करने का आदेश आया। उसी समय ह्यूम संवाददाता आया और जत्थे से पुर्तगालियों के व्यवहार के बारे में पूछा। सभी को पुर्तगाली सैनिकों ने प्रताड़ित करना बताया। ह्यूम ने कमांडर से बात की और शूट का आदेश निरस्त हो गया और सुबह होते ही हम सभी को भारत की सीमा में स्टीमर से छोड़ दिया। पठार से नीचे उतरते ही डंडों और बंदूक की बट से हम सभी को पीटा गया। सीढ़ियों पर कीलें लगी होने से हमारे पैरों में खून बहने लगा। इसके बाद भारतीय स्टीमर द्वारा हमें पूना लाया गया और एक अस्पताल में उपचार करवाया गया। इसके बाद 16 अगस्त, 1955 को पुनः बंबई होते हुए कोटा तथा बारां आए।

(सहायक जनसंपर्क अधिकारी मोहन लाल से हुई बातचीत पर आधारित)



## छोटी उम्र में वानर सेना का हिस्सा बन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े

श्री मनोहर लाल जैन

**1** जून, 1928 में चित्तौड़गढ़ के डूंगला क्षेत्र में जन्मे मनोहर लाल ने 12 साल की उम्र में खादी को अपनाकर देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा दिखा दिया था। कम उम्र में ही वे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ गए थे। वे बताते हैं कि उस समय खादी पहनना किसी अपराध जैसा था। सन् 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनाई गई वानर सेना में काम करना शुरू कर दिया था।

जब वे इस आंदोलन में जुड़े तब उम्र महज 14 साल की थी। श्री मनोहर जैन ने कम उम्र में ही भारत छोड़ो आंदोलन में पर्ची वितरण करने और आंदोलनकारियों को सूचना पहुंचाने का काम किया। जिन क्रांतिकारियों को जेल भेज दिया गया था उनके परिवार तक सूचनाएं पहुंचाते थे। इन्होंने ब्रांच

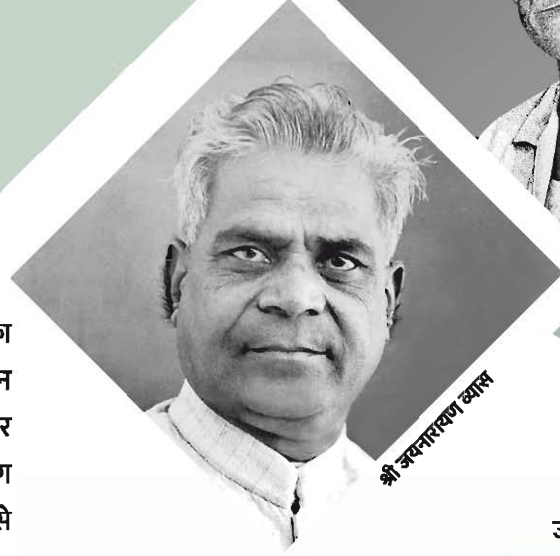
पोस्ट मास्टर का काम करते हुए एक क्रांतिकारी के रूप में भी देश को अपना सहयोग दिया। उसके बाद उन्होंने पिटीशन राइटर का काम किया।

1946 में स्वतंत्रता सेनानी श्री मोतीलाल तेजावत जब टोंक रियासत में आए तब उनका स्वागत एवं जन जागरण करके मेवाड़ प्रजामंडल स्थापित करने में सहयोग किया। टोंक के रियासती गांव में आजादी की चेतना जागरण करने का काम स्वर्गीय मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी सर्वश्री नंद कुमार त्रिवेदी, परसराम त्रिवेदी और माणिक्य लाल वर्मा के साथ मिलकर काम किया। उन्हें टोंक रियासत में कई प्रकार की यातनाएं मिलीं। आंदोलन में भाग लेने एवं यात्राओं के कारण व्यापार एवं शिक्षा से भी वंचित होना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद भी श्री नंदकुमार त्रिवेदी के नेतृत्व में आसावरा माताजी में धार्मिक स्थल पर पशु बलि निषेध आंदोलन में भाग लिया। अभी हाल में 9 अगस्त को राज्य सरकार के आदेश पर उन्हें सम्मानित किया गया। श्री मनोहर जैन 93 वर्ष के हैं। पिछले 5 साल से वे अपने बेटे के साथ उदयपुर में रहते हैं।

(सहायक निदेशक, टी.आर. कण्डारा से हुई बातचीत पर आधारित)



# आजादी के परवानों की ओजस्वी रचनाएं



श्री गणेशलाल व्यास

**भा**रतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोकजागरण से लेकर स्वातंत्र्य चेतना का ज्वार उमड़ाने में क्रांतिकारी साहित्य सृजन का अनुपम योगदान किसी से छिपा नहीं है। उस दौर में स्वाधीनता पाने की धुन हर ओर इस कदर सवार थी कि जो कुछ उपलब्ध साधन-संसाधन और सेवाएं थीं, उनका उपयोग देश को आजादी दिलाने में किया जा रहा था। हर कोई इस दृष्टि से जी-जान से जुटने में अपने आपको धन्य समझता था। ऐसे में लोक चेतना जागृत करने और स्वाधीनता की तड़प को साकार करते हुए देश को आजादी दिलाने का जज्बा हर तरफ स्वाधीनता आंदोलन को हवा दे रहा था।

ऐसे में कलमकारों ने देश को जगाने और प्रेरणा संचार करने का वह जबरदस्त काम किया जिससे समूचे भारतवर्ष में आजादी के परवानों के क्रांतिकारी भाषणों के साथ ही नाटकों, गीतों, नृत्यों, कविताओं और शायरियों से लेकर साहित्य की सभी विधाओं के रचनाकारों ने अपने सृजन के माध्यम से आजादी पाने के लक्ष्य को अभिव्यक्त किया और सशक्त माहौल बनाया।

इससे न केवल मारवाड़ और राजस्थान की रियासतें बल्कि पूरा देश उद्वेलित हुए बिना नहीं रह सका। इससे स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला बढ़ा और अपार जनसमूह उनके साथ सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावनाओं से आगे आया। इससे धीरे-धीरे देश भर में स्वतंत्रता संग्राम परवान पर आ गया। कोना-कोना स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विकल हो उठा और रचनाकारों ने हरेक विधा में शब्दों का करिश्मा दिखाते हुए भारत धरा का आसमान गुंजा दिया। आजादी के आंदोलन में मारवाड़ क्षेत्र का योगदान स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। यहां के सेनानियों ने आंदोलन की हरेक गतिविधि में भाग लेते हुए अपना जीवन खपा दिया।

इन सेनानियों ने जनता को जगाने और आंदोलन को सुदृढ़ करते हुए अंग्रेजों से टक्कर लेने के साथ ही राजा-महाराजाओं के विरुद्ध जमकर शब्दों के अस्त्र-शस्त्रों का प्रहार किया। सामंतवाद से लेकर पूंजीवादी शक्तियों और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हिंदी और मारवाड़ी में रचित इनके गीत और काव्यों ने खासी धूम मचाई। इनमें श्री जयनारायण व्यास, जनकवि श्री गणेशलाल व्यास 'उस्ताद' द्वारा रचित तराने आज भी याद किए जाते हैं।

**आकांक्षा पालावत**  
जनसंपर्क अधिकारी

राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समिति द्वारा प्रकाशित एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरजप्रकाश 'पापा' द्वारा लिखित पुस्तक "स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ (जोधपुर रियासत), मारवाड़ लोक परिषद का उद्भव और विकास" में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा रचित प्रमुख संदर्भ रचनाओं में आजादी के आंदोलन, सेनानियों की काव्य प्रतिभा, सृजन क्षमता और प्रभावी लोक जागरण में इनके जनचेतना साहित्य की अहम भूमिका को उजागर किया गया है।

जयनारायण व्यास की रचनाओं में सामंतशाही, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार के साथ ही आजादी के संघर्ष के लिए कठोर संकल्प झलकता है। मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान का आह्वान करती उनकी यह रचना 'मातृभूमि पर बलि होना' गुलामी की जंजीरों को तोड़ देने के लिए उनके अदम्य आत्मविश्वास और भविष्य के सुनहरी सूरज को संकेतित करती है:

मातृभूमि पर बलि होना

पांवों में हैं जंजीरें, हाथों में हथकड़ियां।

मातृभूमि पर बलि होने को देख रही चड़ियां॥

देख-देख मां दशा तुम्हारी मेरी आंखों से॥ टेर॥

मोती सदृश्य टपक पड़ती हैं आंसू की लड़ियां॥

मेरा रोना भी न सुहाया, अत्याचारी को।

इसीलिए चहुं ओर लगी हैं, लोहे की छड़ियां॥

पर न मातृभू चिंता करना, हूं सच्चा बेटा।

बंधा हुआ भी मैं तोहूंगा, तेरी ये कड़ियां॥



शूरवीर सत्याग्रहियों में जोश भरने के लिए उनके द्वारा मायड़ भाषा में रचित 'मत दूध लजाई जै' शीर्षक वाला संघर्ष गीत इन सत्याग्रहियों द्वारा जेल यात्रा और आंदोलन के दौरान अत्यधिक प्रचलित व लोकप्रिय रहा। इसमें वे मां के दूध की लाज रखने का आह्वान करते हुए सत्याग्रहियों से सपूतों की तरह जीने, मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर के लिए सदैव तत्पर रहने, घर-परिवार का मोह त्याग कर देश के लिए मर मिटने, डटकर संघर्ष करने और जीत कर लौटने की सीख देते हैं:

**मत दूध लजाई जै**

मत दूध लजाई जै, पाछो मत आईजे बेटा राइसूं  
सुण रे बेटा सांवता तूं सुण मायड़ री बात॥  
शूरवीर कुलधर्म की है लज्जा थारे हाथ॥ रे मत॥  
जो जायो सो जावसी कोई रिबरिब मरे कपूत  
करतब करता जो मरे वो सांचो शूर सपूत॥ रे मत॥  
जिण धरती रे धान सूं ओ परबल बण्यो शरीर  
आरा धरती पर दुखड़ो पड़ियो, वीर न छोड़े धीर॥ रे मत॥  
पाछो आई जै जीतने सरै तू या रहिजै रणखेत  
तू जा बेटा मैदान में अब तज दे घर रो हेत॥ रे मत॥  
बिसड़ नवोड़ी सुंदरी तू छोड़ ऐश आराम  
भूल भायला शहर का सब सुमरिण करले राम॥ रे मत॥  
विजयी बण घर आवसी तू ऊंचो राखे शीश  
शूरवीर सुण जावजे आ मायड़ री आशीष॥ रे मत॥

जन जागरण के लिए उन्होंने जिन लोक गीतों की रचना की, उनमें सम सामयिक कुरीतियों के निवारण, समाज सुधार, महिला उत्थान, भ्रष्टाचार उन्मूलन जैसे कई विषयों पर प्रभावोत्पादक सृजन का परिचय मिलता है। रिश्त और घूसखोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करता राग धमाल में लिखा और गाया उनका यह लोकगीत उन दिनों जन-जन की जुबां पर था:

रिश्त छोड़ दे - महाराजा जी री सख्त मनाई है।

रिश्त छोड़ दे॥

थाने मिले तनखा महावारी और तरक्की होवे रे  
म्हां पर कर्ज रोटियां खातिर टाबर रोवे रे...॥ रिश्त ॥  
थारो घर पक्को बणियोड़ो, चोखा थारा गाबा रे  
म्हारे टपरी री छपरी में दीखे आभो रे....॥ रिश्त ॥  
बरतन थारे गेणा थारे, म्हारी हांडी फूटोड़ी  
टाबर नागा राली फाटी, मचली टूटोड़ी॥ रिश्त ॥

श्री जयनारायण व्यास ने इस गीत के जरिये रिश्तखोरी को घृणित और निंदित बताया है। राज दरबारियों को राजधर्म के पालन की नसीहत देते हुए अमीर और गरीब के बीच बढ़ती जा रही खाई के लिए इन्हीं लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। वे ईमानदारी से जनता की सेवा का प्रण निभाने की नसीहत देते हैं।

सामंती और अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देता उनका ओजस्वी गीत शोषक दरबारियों पर वज्र प्रहार करता है। इसमें उन्होंने समसामयिक हालातों पर खरी-खरी कहने का साहस किया है। सत्ता की नश्वरता का स्मरण कराते हुए उन्होंने रियासतदारों को चेताया कि यह सत्ता नहीं रहने वाली। इस गीत में उन्होंने शोषित, पीड़ित और गरीबों की आह के भयंकर परिणामों को समझने की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट किया है कि यह दावानल अब उत्तरोत्तर और भी अधिक भयंकरता हुआ सब कुछ भस्म कर देगा जिसके बूते ये सामंती दरबारी शोषण, दमन और अत्याचारों में डूबे हुए हैं। स्वतंत्रता सेनानी गीतकार इन तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद आजादी को लेकर आशान्वित होते हुए कहता है कि प्रजा रहेगी लेकिन उनकी सत्ता नहीं रहने वाली। जुल्मों भरा इतिहास ही रहेगा केवल, जो उनके शोषण, अन्याय और अत्याचार की कहानियां सुना-सुना कर उन्हें लज्जित करता रहेगा:

भूखे की सूखी हड्डी से वज्र बनेगा महा भयंकर।

ऋषि दधीचि को ईर्ष्या होगी, नेत्र नया खोलेंगे शंकर॥  
अन्न विहीन उदर की आहें, दावानल सी भीषण बनकर॥  
भस्मीभूत कर देंगी उनको, जो दोनों का करते शोषण॥  
बाकी मत रख खूब सताले, खूब दिखाले अपना पशुबल।  
निर्बल का बल देख रहा है, तेरे कुकृत्यों को प्रतिपल॥  
जी भर आज सताले मुझको आज तुझे देता आजादी।  
तेरे इन कुकृत्यों में सोई, छुपकर तेरी ही बरबादी॥  
साहस हिम्मत तनिक नहीं है, शक्ति नहीं है और न वाणी।  
अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, निर्बल हूं, मैं पामर प्राणी॥  
पर है हृदय अधमरापन में और जलन है भीतर भारी।  
वह सुलगेगी वह फैलेगी जल जायेगी दुनिया सारी॥  
नव प्रकाश लख जाग उठेगी चामुंडा पकड़ेगी खप्पर।  
देख-देख लपटों की झपटें तांडव नृत्य करेंगे शंकर॥  
तोड़ हड्डियां चीर कलेजा बहा रुधिर अब जी को भरले।  
बीन—बीन लोहू हड्डी से रक्तपान कर मनको भर ले॥  
कल ही तुझ पर गाज गिरेगा तेरा सभी समाज गिरेगा।  
तख्त गिरेगा ताज गिरेगा महल गिरेगा राज गिरेगा॥  
नहीं रहेगी सत्ता तेरी, बस्ती तो आबाद रहेगी।  
जालिम तेरे सब जुलमों की उसमें केवल याद रहेगी॥



मनुष्य के समग्र जीवन दर्शन का सार प्रकट करता उनका गीत “यह तेरा संसार नहीं है” उन दिनों के संघर्ष का प्रभावी हिस्सा रहा। इसमें दार्शनिक अंदाजों के साथ गुलामी की जंजीरों से बंधे लोगों को परतंत्रता की बेड़ियों को काटकर आजादी पाने और खुली हवा में सांस लेने के लिए प्रेरित करते हुए विचारोत्तेजना के साथ बार-बार उत्प्रेरित किया गया है। इस गीत ने स्वाधीनता आंदोलन में प्रभावी माहौल बनाते हुए आमजन को झकझोरने में कहीं कोई कमी नहीं रखी:

यह तेरा संसार नहीं है  
मैंने अपने ही हाथों से अपनी चिता जलाई,  
देख-देख लपटें मैं हंसता तू क्यों रोता भाई॥  
यह तेरा संसार नहीं है।  
क्यों गंदे पिंजरे में डोले, साफ हवा के पंछी भोले;  
जो तुमसे यों मीठा बोले, उनका तुमसे प्यार नहीं है।  
यह तेरा संसार नहीं है।  
कैद हुआ मीठे फल खाकर, पंछी फंसा लोभ में आकर;  
अब क्यों उलझ रहा चिल्लाकर, बिना यत्न निस्तार नहीं है।  
यह तेरा संसार नहीं है।  
नित्य भाग्य डुलता है तेरा, सदा द्वार खुलता है तेरा;  
रोते बीता सांझ सबेरा, तेरे दुःख का पार नहीं है।  
यह तेरा संसार नहीं है।  
अपनों ने तुझको रोका, दुनिया ने है तुझको कोसा;  
तुझको अपनों पे न भरोसा, फिर भी तू बेकार नहीं है॥  
यह तेरा संसार नहीं है।  
भीतर बंधनमय जीवन है, बाहर शुद्ध वायु का वन है;  
निर्बल पंख भरोसा मन में, अंतर्द्वन्द्व अपार यही है॥  
यह तेरा संसार नहीं है।  
निर्बल मन को सबल बनाना, मुक्ति हेतु कुछ करो बहना;  
किसी तरह भाई छुट जाना, इस बंधन में सार नहीं है।  
यह तेरा संसार नहीं है।  
मैंने अपने हाथों से अपनी चिता जलाई  
देख-देख लपटें मैं हंसता, तू क्यों रोता भाई ॥

इसी तरह जनकवि के रूप में विख्यात श्री गणेशलाल व्यास ‘उस्ताद’ ने रियासती शोषण, बेकारी, अत्याचारों और उस समय की विषम परिस्थितियों के मद्देनजर गीत और ओजस्वी कविताओं से धूम मचा दी थी। उनकी रचनाएं उन दिनों किसानों की सभाओं और कवि सम्मेलनों में खूब सुनाई जाती थीं। ये रचनाएं स्वतंत्रता आंदोलन में लोक चेतना का ज्वार उमड़ा दिया करती थीं। जनकवि ने मानवी मन की विद्रुपताओं और दोहरे-तिहरे चरित्र पर करारा व्यंग्य किया है। इसमें जनकवि के दृढ़ संकल्प, प्रगाढ़ आत्मविश्वास और आजादी की

तीव्र चाह अभिव्यक्त होते हुए यह संदेश मुखरित करती है कि जनकवि की यह शाश्वत वाणी व्योम में गूंजती रहेगी, इसे कोई दबा नहीं सकता। अपनी ओजस्वी वाणी में उस्ताद कहते हैं:

आ जनकवि री जुगवाणी, आ कद न चुप रह जांगी  
कोई लाख जतन कर हारै वा समचै सांच सुणांगी ॥  
जन-जन रै पग बेड़ी ही जनता गाडर जैड़ी ही  
राजा रो जोर जमावण, अंगरेज फौज नेड़ी ही  
जद कठै दबी जरबां सू अब किण रे हाथ दबांगी  
आ जन कवि री वाणी आ कद न चुप रह जांगी  
गायक इक दिन मिट जासी, पण अड़ा गीत बंगासी  
जन-जन रै कंठा रमसी, पीढ़ी दर पीढ़ी गासी  
आ काया तो कवि री है, पण जनता री जुगबांगी  
आ जन कवि री जुगबांगी, आ कद न चुप रह जांगी ।  
कोई लाख जतन कर हारै, आ समचै सांच सुणांगी ॥

“माथा देणां पड़सी” गीत में उन्होंने उत्तेजक भावों के साथ युवाओं का आह्वान किया है। इसमें जनकवि ने मातृभूमि का कर्ज उतारने पर जोर देते हुए आजादी के संघर्ष में युवाओं की बड़ी और प्रभावी भूमिका की ओर इशारा करते हुए आगे आने का आह्वान किया है:

माथा देणा पड़सी  
मुलक नै मोट्यारों माथा देणां पड़सी  
देस नै हुसियारों माथा देणां पड़सी  
मुरधर रा मूघा मानवियां काज सरै सिर सूंघा करिया  
रणरा साज सजावौ मुलक रा मोट्यारों  
जुलम जोर री जड़ ने काटो, फूट झूठ री खाई पाटी  
हिलमिल हाक लगावौ मुलक रा मोट्यारों  
आवौ आपणो देस उबारौ भारत मां रौ भार उतारौ  
सिर दे नाक बचा कै  
मुलक नै मोट्यारों माथा देणां पड़सी॥

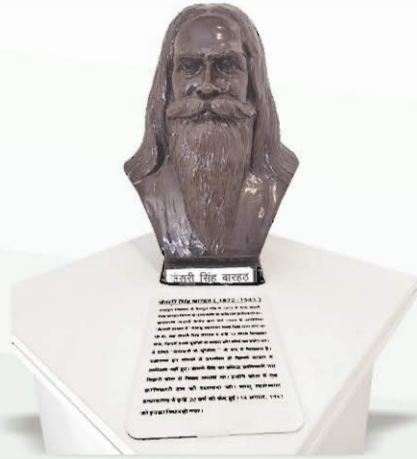
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान के निर्माण से लेकर आधुनिक राजस्थान तक के सफर में कई ज्ञात-अज्ञात महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और विकास पुरुषों की जीवनपर्यन्त सहभागिता ही वह प्रमुख कारक है जिसकी बदौलत हम स्वतंत्र भारत में रहते हुए जन-जन के विकास और राजस्थान के समग्र उत्थान की दिशा में नित नई पहचान कायम करते जा रहे हैं। स्वतंत्रता संघर्ष में मारवाड़ के योगदान का सदियों तक महिमागान होता रहकर पीढ़ियों तक प्रेरणा का संचरण करता रहेगा। •





## स्वतंत्रता सेनानियों की यादों को ताजा करता

# स्वतंत्रता सेनानी स्मृति कक्ष



**स्व**तंत्रता वह अनमोल धरोहर है, जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने लहू से सींचा है। स्वतंत्रता आंदोलन में मिले संस्कारों से देश की वर्तमान चुनौतियों का मुकाबला व भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया जा सकता है। ऐसी प्रेरणा देने का काम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की जानकारी देने वाली संस्थाएं कर रही हैं। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा संचालित सूचना केंद्र, जयपुर में स्थित स्वतंत्रता सेनानी स्मृति कक्ष देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की याद को तरौताजा कर देता है।

सूचना केंद्र के नए परिसर में स्थित स्वतंत्रता सेनानी स्मृति कक्ष में स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां और जीवन गाथा का विवरण प्रदर्शित किया गया है। यहां के स्वतंत्रता सेनानी स्मृति कक्ष व राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम कीर्ति स्तंभ का उद्घाटन 14 दिसंबर, 2002 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आयोजित उस कार्यक्रम में राज्य के अनेक स्वतंत्रता सेनानी भी उपस्थित हुए थे।

स्वतंत्रता सेनानी समिति कक्ष में स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद श्री मंगल पांडे, सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान, शहीद-ए-आजम श्री भगत सिंह, श्री राजगुरु, श्री सुखदेव, श्री चंद्रशेखर

**मोहित जैन**  
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

आजाद, सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले श्री खुदीराम बोस आदि विभिन्न क्रांतिकारियों की मूर्तियां प्रदर्शित हैं। इसके अलावा यहां राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों को जाना जा सकता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व स्वतंत्रता सेनानी श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री जयनारायण व्यास के साथ श्री माणिक्य लाल वर्मा, श्री विजय सिंह पथिक, श्री केसरी सिंह बारहठ, आदिवासी क्रांतिकारी श्री नानक भील, श्रीमती काली बाई, किसान आंदोलन के नेता श्री रूपाजी, श्री कृपाजी बेगू सहित कई क्रांतिकारियों की मूर्तियां मौजूद हैं। यह कक्ष व कीर्ति स्तंभ यहां आने वाले सैकड़ों छात्र-छात्राओं के आकर्षण का बिंदु बना हुआ है।

अब इन्हें आधुनिक गैलरी बनाकर नए सूचना केंद्र की सेकंड फ्लोर पर स्थापित किया गया है। ये मूर्तियां 1985 में एसएमएस स्टेडियम में लगी एक प्रदर्शनी में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पेवेलियन रणभेरी में प्रदर्शित की गई थीं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भी इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। ये मूर्तियां चित्रकार और मूर्तिकार श्री सुमैंद्र ने बनाई थीं। •



# राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएं

एक लंबे संघर्ष के बीच अनगिनत कुर्बानियों के बाद आया 15 अगस्त, 1947 का दिन बेहद खास और खूबसूरत था। सब की आंखों में एक अलग ही चमक थी। ये होना सबकी एक सपने जैसा ही लगा था। लगे भी क्यों नहीं, आखिर इतने वर्षों की कड़ी जद्दोजहद के बाद भारत तानाशाही, गुलामी और नफरत की पीछे छोड़ स्वाधीन बना था। इस सुनहरे दिन के साक्ष्य बने लोगों के पास गुलामी के दिनों की मुश्किलों और अंग्रेजों से संघर्ष में तरह-तरह की कुर्बानियां देने की अनगिनत कहानियां हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की गुलामी की जंजीरों से आजाद होने के उद्देश्य से शुरू किया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक अभूतपूर्व संघर्ष और अविस्मरणीय सफलता का प्रतीक है।

स्वाधीनता प्राप्ति के इस आयाम के बाद सबसे ज्यादा खिलखिलाते चेहरे थे भारतीय महिलाओं के, जिन्हें इस आजादी में नए स्वाब और एक अलग भविष्य दिखाई देने लगा था। स्वराज की इस लंबी और जटिल लड़ाई में भारतीय महिलाओं ने एक बड़े पैमाने पर भूमिका निभाई थी। उनके योगदान ने इस आंदोलन को आकार देने और भारत के लिए स्वतंत्रता हासिल करने के साथ ही उनके पैरों में बंधी बेट्टियों को तोड़ उन्हें हौसला भी प्रदान किया।

असल में भारत में राजनीति एवं आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति उनकी जनसंख्या के अनुपात में कम है, लेकिन भारत के प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक एवं पर्यावरणीय आंदोलनों में इनकी भूमिका अत्यधिक सराहनीय है।

अंजलिका पंवार  
सहायक जनसंपर्क अधिकारी



ऐनी मैसकरीन



ए.वी. कुट्टी मलुअम्मा



सुभद्रा जोशी

## क्षेत्रीय आंदोलन में महिलाएं

प्रांतीय स्तर पर केरल में ऐनी मैसकरीन और ए.वी. कुट्टी मलुअम्मा, मद्रास प्रेसीडेंसी में दुर्गा बाई देशमुख, उत्तर प्रदेश में रामेश्वरी नेहरू और बी अम्मन, दिल्ली में सत्यवती देवी और सुभद्रा जोशी और मुंबई में हंसा मेहता ने अपने क्षेत्र के आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई।

वर्ष 1915 में मौजूदा मणिपुर में जन्मी रानी गैदिनल्यू ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर करों का भुगतान करने से इंकार कर दिया। वह हेरका आंदोलन में शामिल हुई जो बाद में आजादी का एक प्रमुख आंदोलन बना। असम की कनकलता बरुआ ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था। वर्ष 1780 में रामनाथपुरम में जन्मी वेलु नचियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध में अपने पति के मारे जाने के बाद संघर्ष में प्रवेश किया और विजय प्राप्त की थी।

दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति ऐसी रही है कि इसमें

प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल काम है। इनमें से बहुत सारी महिलाओं ने प्रांतीय स्तर पर शुरुआत की और वे राष्ट्रीय केंद्रीय स्तर तक पहुंच गईं।

## राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी महिलाएं

उस समय के भारतवर्ष के रूढ़िवादी समाज की सोच को पीछे छोड़ आजादी के इस जनक्षोभ में महिलाओं ने कई प्रकार से हिस्सा लिया। मिसाल के तौर पर अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी जैसी महिलाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख नेता रहते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित किया है। भारतीय महिलाएं बड़े स्तर पर प्रदर्शनों और हड़तालों में शामिल हुई थीं और इन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विरोध के रूप में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया था। अगर हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं



रानी लक्ष्मीबाई



बेगम हजरत महल





सरोजिनी नायडू



विजयलक्ष्मी पंडित



कमलादेवी चट्टोपाध्याय



मृदुला साराभाई



कस्तूरबा गांधी



उषा मेहता

के नाम को याद करें तो इसकी सूची बहुत लंबी है। राष्ट्रीय स्तर पर सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कमलादेवी चट्टोपाध्याय और मृदुला साराभाई प्रमुख नाम हैं। रानी लक्ष्मीबाई को वर्ष 1857 में भारत की स्वतंत्रता के पहले युद्ध में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। कमलादेवी चट्टोपाध्याय जैसी महिलाओं ने राजनीतिक कैदियों और उनके परिवारों के लिए राहत प्रयासों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

आजाद हिंद फौज का हिस्सा रही कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसी महिलाओं ने भूमिगत आंदोलन में खास भूमिका निभाई थी। सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट जैसी महिलाएं महिला अधिकार आंदोलन की प्रमुख नेता थीं।

मैडम भीकाजी कामा ने स्वतंत्रता के लिए भारतीय लड़ाई के शुरुआती वर्षों में योगदान दिया और समाज में महिलाओं की भूमिका के लिए अभियान चलाया। वह 22 अगस्त, 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला बनीं।

### अहिंसक आंदोलन में महिलाएं

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ स्वदेशी आंदोलन से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। बीसवीं शताब्दी के आरंभिक दशक में महिला शिक्षा, महिला संगठनों के गठन और भारतीय राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने महिलाओं के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। भारत की आजादी की लड़ाई में महिलाओं की भागीदारी की कहानी एक दृढ़ विकल्प तैयार करने की कथा है।

महिलाओं का घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर सड़कों पर आना, उनका जेल जाना और विधायिका में उनका प्रवेश करना, इन सबने मिलकर जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें सशक्त बना दिया। कस्तूरबा गांधी ने नमक सत्याग्रह में

भाग लिया था। भारत के सबसे प्रमुख गांधीवादियों में से एक उषा मेहता महज आठ साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गई थीं। उन्होंने साहमन कमीशन के खिलाफ मार्च किया था। 14 अगस्त, 1942 को मेहता ने अपने सहयोगियों के साथ गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की।

अहिंसक आंदोलन ने महिलाओं को साथ लिया और भारत को आजादी दिलाई। इन्होंने न केवल महिलाओं को साथ लिया बल्कि उन्हें अपनी सक्रिय भागीदारी की सफलता के लिए आत्मनिर्भर होना भी सिखाया।

### क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाएं

साम्राज्य विरोधी आंदोलन में कई क्रांतिकारी संगठन भी सक्रिय थे। यद्यपि 1930 और 1940 के दशक में तीव्र गति से उभरते क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी की संभावना बहुत कम दिखाई दी थी, लेकिन बहुत सी महिलाएं भी क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुई थीं।

दुर्गा भाभी के नाम से मशहूर दुर्गावती देवी एक क्रांतिकारी थीं, जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल हुईं। वह नौजवान भारत सभा की सदस्या भी थीं। इन्होंने वर्ष 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी. सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर से भेष बदलकर भागने में मदद की थी। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सदस्य भगवती चरण वोहरा से शादी की और अन्य क्रांतिकारियों के साथ दिल्ली में एक बम फैक्ट्री का भी संचालन किया था।

कल्पना दत्ता 1931 में सूर्यसेन की रिपब्लिकन इंडियन आर्मी में शामिल हुईं। क्रांतिकारियों के लिए वह बम बनाती थीं और कूरियर एजेंट का काम करती थीं। प्रीतिलता वाडेकर, सुनीति चौहान आदि ने भी क्रांतिकारी आंदोलन में अहम योगदान दिया था। •



दुर्गावती देवी



कल्पना दत्ता



प्रीतिलता वाडेकर



# जोधपुर रियासत से स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान

**स**हायक संधियों के परिणामस्वरूप देशी रियासतें प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आने लगीं। 6 जनवरी, 1818 को जोधपुर रियासत ने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही तत्कालीन व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन प्रारंभ हुए। अब जमीदारों के साथ ब्रिटिश हुकूमत ने रियासतों की जनता पर अनेक करों, लाग बाग एवं राजस्व वसूली के माध्यम से शोषण में वृद्धि की। 20वीं सदी के आरंभिक काल में रियासती जनता में विरोध के स्वर मुखर होने लगे। मारवाड़ अंचल में भी राजनीतिक चेतना का विकास हुआ।

श्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ लोक परिषद ने उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए जन आंदोलन प्रारंभ किया। श्री जयनारायण व्यास चाहते थे कि जिस तरह शेखावाटी किसान आंदोलन में किशोरी देवी एवं अंजना देवी, मेवाड़ में नारायणी देवी और जयपुर में जानकी देवी और रतन शास्त्री द्वारा महिलाओं की स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई है उसी तरह मारवाड़ में भी महिलाओं को आंदोलनों में सक्रिय रूप से जुड़कर कार्य करना चाहिए।

मारवाड़ लोक परिषद ने निर्णय लिया कि म्यूनिसिपल समिति के चुनाव में परिषद महिलाओं के लिए निर्वाचन में भागीदारी के लिए उन्हें चुनाव में उम्मीदवार घोषित करेगी। जयनारायण व्यास के नेतृत्व में परिषद द्वारा 11 मई, 1942 को दूसरा सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना और सर डोनाल्ड को पदच्युत करने की मांग सरकार के समक्ष रखी।

## महिलाओं की सक्रिय भूमिका का आरंभिक चरण

श्री जयनारायण व्यास की मांगों की प्रतिक्रिया में तत्कालीन सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मई, 1942 के सत्याग्रह आंदोलन में लगभग 500 सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारी दी। सत्याग्रहियों में सिरे कौर बाईसा, राज कौर व्यास, सावित्री भाटी, शकुंतला त्रिवेदी, कृष्णा देवी शर्मा और गोरजा देवी प्रमुख महिलाएं थीं जिन्हें गिरफ्तार कर केंद्रीय कारागृह जोधपुर में रखा गया। जेल में सत्याग्रहियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया जिसकी राष्ट्रीय नेताओं

अभय सिंह  
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

द्वारा कड़ी आलोचना की गई। लोक परिषद प्रतिदिन जुलूस निकाल कर सक्रिय विरोध दर्शाती थी। जुलूस का पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण दमन किया जाता था। पुलिस कार्रवाई में सावित्री जोशी, कृष्णा देवी, रमादेवी और दुर्गा-देवी भी घायल हुईं।

सत्याग्रहियों ने 11 जून, 1942 को अत्याचारों के विरोध में भूख हड़ताल प्रारंभ की। इस भूख हड़ताल में बालमुकुंद बिस्सा की तबियत बिगड़ गई और 19 जून को शहीद हो गए। आंदोलनकारी बिस्सा का शव लेकर सोजती गेट पर प्रदर्शन करने लगे। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और तत्कालीन सिटी पुलिस अधीक्षक ने सावित्री देवी के साथ धक्का-मुक्की की। जोधपुर रियासत में यह पहली घटना थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने किसी महिला के साथ मारपीट की हो। इस घटना के बाद भीड़ उग्र हो गई। पुलिस ने महिलाओं को बुरी तरह से पीटा और गिरफ्तार कर लिया।

## ग्लाउसेस्टर के ड्यूक की यात्रा का विरोध

इन्हीं दिनों ग्लाउसेस्टर का ड्यूक जोधपुर की यात्रा पर आया। सत्याग्रहियों ने काले झंडे दिखाए और 11 महिलाओं के जत्थे केसरिया साड़ी पहन कर सत्याग्रह के लिए घंटाघर के निकट एकत्र हुए। महिमादेवी किंकर ने प्रतिबंधित पुस्तक 'उत्तरदायी शासन' पढ़कर सुनाई। केसरिया रंग का चुनाव गांधीवादी प्रतीकों के साथ राजपूताने के संघर्ष और राष्ट्रहित में सर्वस्व बलिदान की परंपरा का परिचायक था। सरकार द्वारा लोक परिषद की आर्थिक सहायता करने वाले सेठों के समक्ष परिषद की छवि को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। इसकी प्रतिक्रिया में महिलाओं ने सरकार द्वारा प्रतिबंधित साहित्य बांटकर जन भावनाओं को तत्कालीन सरकार के विरुद्ध उभार कर आंदोलन को सुदृढ़ किया। परिषद की लोकप्रियता के कारण जेल के कार्मिक सत्याग्रहियों के प्रति सहानुभूति रखने लगे थे जिसके कारण गुप्त पत्राचार और





गोरजादेवी जोशी



सावित्री देवी भाटी

प्रतिबंधित सामग्री का आदान-प्रदान सहजता से होने लगा। महिला सत्याग्रहियों का एक दल प्रतिदिन मारवाड़ के मुख्यमंत्री डीएम फील्ड और उप मुख्यमंत्री पंडित धर्मनारायण के दफ्तर जाकर प्रतिबंधित साहित्य की प्रतियां देता था। उप मुख्यमंत्री ने सत्याग्रहियों के सामने उन प्रतियों को फाड़ दिया और महिलाओं को थक्के मारकर वहां से निकाल दिया। महिलाओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और सावित्री भाटी ने चूड़ियां उतारकर उप मुख्यमंत्री को पहनने के लिए चुनौती दी। उन्हें वहां से बलपूर्वक निकाला गया, लेकिन परिषद के बढ़ते प्रभाव के कारण किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। महिला आंदोलनकारी समूह बनाकर सेंट्रल जेल जातीं और सत्याग्रहियों से मिलने का प्रयास करतीं। स्वीकृति नहीं मिलने पर सावित्री जोशी, पार्वती सोलंकी, राधा देवी जेलर एवं जेल अधीक्षक के दफ्तर में घुस कर नारे लगा कर मुलाकात का आग्रह करती थीं।

### भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका

8 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के साथ संपूर्ण देश में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात हो गया। गांधीजी के "करो या मरो" के आह्वान के साथ मारवाड़ में भी आंदोलन शुरू हो गया। 8 अगस्त को पांच महिलाओं ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ ब्रिटिश विरोधी उद्घोष के साथ प्रभात फेरी निकाली। शीघ्र ही अच्छी भीड़ जुट गई, पुलिस द्वारा दमन का प्रयास किया गया जिसके विरोध में स्त्रियां सड़क पर लेट गईं और उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। गिरदीकोट पर रमादेवी, कृष्णाकुमारी और दयावती ने आमसभा को संबोधित किया।

### दमन विरोधी दिवस

22 सितंबर, 1942 को गिरदीकोट की आमसभा में आर्य कन्या पाठशाला की प्रधानाध्यापिका ने उत्तरदायी शासन की मांग के समर्थन में ओजस्वी भाषण दिया। वहीं सूरजदेवी माथुर और सावित्री देवी ने प्रेरक गीतों के माध्यम से उत्तरदायी शासन की मांग रखी। 25 सितंबर को दमन विरोधी दिवस मनाया गया और विशाल जुलूस निकाला जिसका नेतृत्व हरिभाई किंकर, सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी ने किया।

### गोरजादेवी जोशी का योगदान

गोरजादेवी जोधपुर की पहली महिला थी जिसने 1942 के आंदोलन में अपनी परंपरागत पोशाक को त्यागकर खादी की साड़ी पहनी थी। उन्होंने तिरंगा लेकर जोधपुर की सड़कों पर सत्याग्रह किया। परिषद में गोरजादेवी की प्रेरणा

और नेतृत्व के बदौलत महिलाओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित हुई। प्रेरणापुंज व्यक्तित्व के कारण उन्हें 'बा' संबोधन दिया गया। वे अपने तीन पुत्रों के साथ लगभग 9 माह जेल में बंद रहीं। गोरजादेवी का पूरा परिवार राष्ट्रीय आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहा। 'बा' संबोधन से परिलक्षित होता है कि कस्तूरबा गांधी का प्रभाव जोधपुर में था। राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य कस्तूरबा गांधी कर रही थी वैसे ही कार्य स्थानीय स्तर पर गोरजादेवी द्वारा किया जा रहा था।

### राजकौर व्यास का योगदान

1902 में जोधपुर में राजकौर व्यास का जन्म हुआ। वह बाल्यकाल से ही समाज सुधार के कार्य से संलग्न रही। उन्होंने जयनारायण व्यास के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया जिसके परिणामस्वरूप उन पर राजद्रोह का अभियोग चला और उन्हें 6 माह की कठोर कारावास की सजा हुई। आंदोलन में भाग लेने से इनके पति शिवदास व्यास मुंशी को पदावनति का दंड मिला। राजकौर व्यास को अपनी 5 वर्षीय पुत्री सत्या को भी जेल में रखना पड़ा क्योंकि इनका पूरा परिवार उस समय जेल में था।

### फलीदी की महिलाओं की भूमिका

जोधपुर की तरह फलीदी भी आंदोलन का केंद्र बनकर उभरा। यहां युवा सत्याग्रही बालकृष्ण थानवी और हेमराज व्यास को राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया। गिरफ्तारी के विरोध में महिलाओं ने तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया। फलीदी जैसे छोटे कस्बे में महिलाओं द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष भूमिका निभाना आश्चर्यजनक था। प्रमुख सत्याग्रहियों में सुखीदेवी, गोदावरी देवी और जानकी देवी का नाम उल्लेखनीय है।

महिलाओं के योगदान के अनेक उदाहरण इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया जिसकी बदौलत आंदोलन से सशक्त महिला शक्ति की उजली तस्वीर ऐतिहासिक कालखंड में दर्ज है। मारवाड़ सहित संपूर्ण राजस्थान में अनेक महिला आंदोलनकारियों ने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। द्वितीय बम षड्यंत्र केस में सूरजप्रकाश 'पापा' को बहन कृष्णादेवी और मां राधा देवी ने साक्ष्यों को नष्ट कर सजा से बचाया। अचलेश्वर प्रसाद 'मामा' की पत्नी कृष्णा कुमारी शर्मा ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। इन घटनाओं को सम्मिलित रूप से देखें तो इन्हीं से भारतीय स्वतंत्रता की विशाल इमारत का निर्माण हुआ। महिलाओं ने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई को अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। •

# सैनिक कल्याण

## निर्णय, योजनाएं और उपलब्धियां

### महत्वपूर्ण बजट घोषणा वर्ष 2023-24

- राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल (वीरता) और तटरक्षक मेडल (वीरता) से अलंकृत सैनिकों को नकद राशि क्रमशः 6 लाख एवं 30 हजार एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि की एवज में 25 लाख रुपए नकद दिए जाने का प्रावधान।
- वर्ष 1962, 1965 एवं 1971 के युद्धों में सेना मेडल (वीरता) से अलंकृत शूरवीरों तथा उत्तम युद्ध सेवा मेडल एवं युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित सशस्त्र सेनाओं के शूरवीरों को देय सुविधाओं में चल रही विसंगतियां दूर करने की घोषणा।
- सीकर में सैनिक सदन एवं महिला कौशल विकास केंद्र का निर्माण।
- भीम (जिला राजसमंद) में नवीन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोला जाना।

ब्रिगेडियर वी.एस. राठौड़ (सेवानिवृत्त)  
निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग

**रा**जस्थान सरकार भारतीय सशस्त्र सेनाओं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए पूर्णतया संवेदनशील रही है। राज्य सरकार ने सैनिक समाज के कल्याणार्थ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अनेक नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और उन्हें बजट घोषणाओं के जरिये मूर्त रूप प्रदान किया गया है।

### कारगिल पैकेज के तहत देय राशि में वृद्धि

राज्य सरकार द्वारा 14 फरवरी, 2019 और इसके बाद सैनिक बलों एवं अर्द्धसैनिक बलों के शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों /स्थाई रूप से विकलांग सैनिकों के कल्याणार्थ पूर्व में जारी कारगिल पैकेज में देय राशि पच्चीस लाख रुपए को बढ़ाकर पचास लाख रुपए किया गया।

### वीरांगनाओं व शहीद सैनिकों के माता-पिता को देय सम्मान भत्ता राशि वृद्धि

1 अप्रैल, 1999 से पूर्व के शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं तथा अविवाहित शहीद सैनिकों के माता-पिता को प्रदान की जा रही सम्मान भत्ता राशि को 1,500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 5 हजार रुपए प्रतिमाह किया गया है।

### द्वितीय विश्वयुद्ध की पेंशन राशि में बढ़ोतरी

द्वितीय विश्वयुद्ध में भाग लेने वाले सैनिक जिन्हें किसी अन्य स्रोत से पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसे सैनिकों/वीरांगनाओं की मासिक पेंशन राशि को 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया गया है।

### भूमि के बदले नकद राशि में बढ़ोतरी

शौर्य पदक विजेताओं और शहीद के आश्रितों को भूमि आवंटन के संबंध में समान व्यवस्था करते हुए 1 अगस्त, 2019 से 25 बीघा भूमि या भूमि

की एवज में 25 लाख रुपए दिये जाने का प्रावधान किया गया। पूर्व में शौर्य पदक विजेताओं को भूमि के बदले 4 लाख रुपए दिए जाते थे।

### स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट

देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के सम्मान में उनकी आश्रित पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता या पिता के पक्ष में राज्य सरकार या निजी संस्था या व्यक्ति द्वारा आवंटित/हस्तांतरित आवासीय भूखंड/भवन के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में संपूर्ण छूट का प्रावधान किया गया।

### पूर्व सैनिक संविदाकर्मियों के पारिश्रमिक में वृद्धि

राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कॉरपोरेशन के माध्यम से नियोजित पूर्व सैनिकों को देय पारिश्रमिक में 45 प्रतिशत (1 अक्टूबर, 2019 से 10 प्रतिशत, 1 अप्रैल, 2022 से 20 प्रतिशत तथा 1 अप्रैल, 2023 से 15 प्रतिशत) की वृद्धि की गई है।

### भूमि आवंटन के संबंध में नवीन नियम

उपनिवेशन विभाग द्वारा सशस्त्र सेनाओं एवं पैरामिलिट्री फोर्स के शहीद एवं स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों को भूमि आवंटन के संबंध में नियम जारी किए गए हैं जिससे उनकी भूमि आवंटन संबंधी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। वर्ष 1986 से 1988 तथा वर्ष 1994 से 2006 के दौरान सेना, नौसेना एवं वायु सेवा मेडल (गैलेंट्री) से अलंकृत शूरवीरों को 25 बीघा भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है।

### नियोजन हेतु न्यूनतम प्राप्तांकों में अतिरिक्त छूट

राज्य सेवा में भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष छूट का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर 10 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है।





भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों पर नियोजन हेतु न्यूनतम प्राप्ताकों में 5 प्रतिशत छूट का प्रावधान था। इन पदों हेतु भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने पर न्यूनतम प्राप्ताकों में अतिरिक्त 5 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।

### शहीद सैनिकों के आश्रित माता-पिता को सावधि राशि में बढ़ोतरी

शहीद सैनिकों के आश्रित माता-पिता को सावधि के आधार पर प्रदान की जा रही 3 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।

### गैलेंट्री / विशिष्ट सेवा पदकों से अलंकृत सैनिकों को पारितोषिक

परम विशिष्ट सेवा मेडल धारक को दो लाख रुपए, अति विशिष्ट सेवा मेडल धारक को एक लाख रुपए, विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 75 हजार रुपए, सेना मेडल (विशिष्ट सेवा) धारक को 50 हजार रुपए तथा मेंशन इन-डिस्पेच धारकों को 25 हजार रुपए की सम्मान राशि का प्रावधान किया गया है।

### राजकीय सेवा में नियोजन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम

- 15 अगस्त, 1947 से लेकर 31 दिसंबर, 1971 के मध्य सशस्त्र सेनाओं के शहीद सैनिकों के कुटुंब के एक सदस्य को नियोजन का प्रावधान।
- 1 जनवरी, 1972 एवं इसके बाद शहीद एवं स्थायी विकलांग सैनिकों के परिवार के एक आश्रित को नियोजन का प्रावधान।
- 1 अप्रैल, 1999 एवं इसके बाद सर्विस के दौरान सशस्त्र सेनाओं के सैनिक की किसी घटना में मृत्यु (फिजिकल कैजुअलिटी)/ स्थायी रूप से निःशक्त (40 प्रतिशत या अधिक) होने पर एक आश्रित को नियोजन का प्रावधान। यह प्रावधान देश के किसी भी अन्य राज्य में नहीं है।
- 1 अप्रैल, 1999 एवं इसके बाद विभिन्न युद्धों एवं काउंटर इंसरजेंसी ऑपरेशनों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं भारतीय तटरक्षक बल (प्रथम बार नियोजन हेतु शामिल) के शहीद कार्मिकों के परिवार के एक आश्रित को नियोजन का प्रावधान।

### वीरांगना पहचान पत्र के अनुरूप शहीद के माता-पिता को सम्मान हेतु विशेष पहचान पत्र

प्रदेश के शहीदों की वीरांगनाओं को उचित सम्मान प्रदान करने तथा

उनके राजकीय कार्यों को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के लिए सैनिक कल्याण विभाग द्वारा जारी 'वीरांगना पहचान पत्र' के अनुरूप ही शहीद की माता को "वीर माता पहचान पत्र" तथा शहीद के पिता को "वीर पिता पहचान पत्र" जारी किए जाने की सहमति प्रदान की गई।

### अलंकृत सैनिकों को निःशुल्क भूखंड का आवंटन

परमवीर चक्र से शौर्य चक्र तक से अलंकृत सैनिकों को 220 वर्गमीटर तक के भूखंड का निःशुल्क आवंटन का प्रावधान किया गया है।

### सैनिक कल्याण भवन का निर्माण

सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं परिवारों को एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध कराने एवं उनकी समस्याओं के निराकरण को ध्यान में रखते हुए जयपुर में 20 करोड़ रुपए से सैनिक कल्याण भवन के निर्माण की घोषणा को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

सैनिक कल्याण भवन के लिए गोकुल नगर, कालवाड़ रोड़, जयपुर में 4 हजार वर्गमीटर भूमि आवंटित कर दी गई है। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा।

### भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के विशेष अवसर

भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करने के साथ-साथ प्रदेश के विकास में उनके अनुभव का लाभ लेने की दृष्टि से विभिन्न चयनित पदों पर सेवा नियमों में प्रावधान करते हुए लैटरल एंट्री से सरकारी सेवा में आने के अवसर प्रदान किए जाने के निर्णय को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए नियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही भूतपूर्व सैनिकों के नियोजन के संबंध में कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी।

### सैनिक कल्याण विभाग का ऑटोमेशन

सैनिक कल्याण विभाग के ऑटोमेशन (ऑनलाइन) हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। प्रथम चरण में निदेशालय, सैनिक कल्याण विभाग तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जयपुर के ऑटोमेशन (ऑनलाइन) का कार्य शीघ्र प्रारंभ करवा दिया जाएगा। •



# राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन

## राजस्थान ने पहली बार की इस सम्मेलन की मेजबानी



**डॉ. लौकेश चंद्र शर्मा**  
उपनिदेशक जनसंपर्क, राजस्थान विधानसभा

**रा**ष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन 21 से 22 अगस्त को उदयपुर में आयोजित किया गया। इसमें डिजिटल सशक्तीकरण, गुड गवर्नेंस की दिशा में जनप्रतिनिधियों के कौशल को अधिक बेहतर बनाने और वर्तमान युग की चुनौतियों में जनप्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से देश को मजबूत करने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका आदि विषयों पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन के दौरान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश सहित विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति और विधान परिषद उपसभापतियों ने भाग लिया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के मुख्यालय लंदन से अध्यक्ष एवं सचिव भी उदयपुर आए। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहा है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना 1911 में हुई थी एवं 1948 में इसका वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। वर्तमान में 180 से अधिक विधानमंडल इसके सदस्य हैं और भौगोलिक दृष्टि से यह 9 अलग-अलग क्षेत्रों में बंटा है। राजस्थान को इस सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर पहली बार मिला है।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा ने गत पांच वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इन वर्षों में 11 सेमिनार आयोजित की गईं, जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल सहित कई गण्यमान्य लोगों ने भाग लिया। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ के मुताबिक हमारे देश में गांव, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, जो विश्व में अनूठा उदाहरण है। जनप्रतिनिधियों को आमजन का रोल मॉडल बनना पड़ेगा।

**लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने में सीपीए का अमूर्तपूर्व योगदान** सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने बताया कि वर्ष 1911 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना हुई थी, तब इसमें 57 देश थे। इसके बाद निरंतर इसका विस्तार होता गया। इस संघ ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने में अमूर्तपूर्व योगदान दिया है। भारत का लोकतंत्र मजबूत है, यहां सदियों से लोकतंत्र की परंपरा रही है। यहां सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश में काफी विविधता विद्यमान है जिस वजह से हमारी चुनौती और बढ़ जाती है। कई विधानसभाओं ने पेपरलेस होने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और कई विधानसभा अपनी कार्यवाही को ऑनलाइन कर रही हैं जो अच्छा कदम है। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने विश्व में लोकतंत्र को मजबूत करने में सीपीए की भूमिका की सराहना की।







### योजनाओं में आईटी के उपयोग और इनोवेशन में अग्रणी राजस्थान

सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बताया कि सीपीए इंडिया लोकतांत्रिक प्रणाली की मजबूती के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर विचारों और नवाचारों से लोक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सम्मेलन के जरिए विशेषज्ञों के विचारों से जनप्रतिनिधियों का ज्ञानवर्द्धन होगा, जिससे हमारा लोकतंत्र और सुशासन अधिक मजबूत होगा। डिजिटल युग में लोकतंत्र की मजबूती, सुशासन और राष्ट्र-निर्माण में जनप्रतिनिधियों की भूमिका के लिए सम्मेलन उपयोगी साबित होगा। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा देश में कंप्यूटर इस्तेमाल को मिशन मोड पर लिए जाने से ही आज गुड गवर्नेंस सुनिश्चित हो सका है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आईटी का योजनाओं में सर्वश्रेष्ठ उपयोग और इनोवेशन करने में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बन गया है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने में आईटी की बड़ी भूमिका है। लगभग 80 हजार ई-मित्र केंद्रों से 550 से अधिक सेवाओं को आमजन तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गैस सिलेंडर सब्सिडी, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का सीधा लाभ (डीबीटी) भी आईटी से ही संभव हुआ है। राज्य में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए प्रदेश में इनोवेशन हब विकसित किया जा रहा है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी और गिग वर्कर्स कानून भी राज्य में आईटी से ही आगे बढ़ रहे हैं।

### राष्ट्रहित में उपयोगी साबित होगा प्रभावशाली सदन

सम्मेलन में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने बताया कि सीपीए का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना है। इसके माध्यम से

संसद प्रमुख तथा विभिन्न राज्यों की विधायिका के प्रमुख, जनप्रतिनिधिगण आदि मिलकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए मंथन करते हैं। कॉमन नीति बनाकर उस पर अमल करते हैं, इससे लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलती है। संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से हमने देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सदन पूरा चले और सदन प्रभावशाली होगा तो नीतियां बनेंगी और राष्ट्रहित में उपयोगी साबित होंगी।

### सभी को एक दूसरे की क्षमता संवर्धन का कार्य करना है

राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने बताया कि आज के युग में टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ा है। आज की दुनिया तकनीक से संचालित है। भारत के पास तेज गति से बढ़ने का अवसर है। तकनीक से ट्रांसपेरेंट प्रशासन बना है और भ्रष्टाचार कम हुआ है। आज देश में रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन हो रहे हैं। आईटीआर रिटर्न में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। हाल में जी20 सम्मेलन में भी डिजिटल इकोनॉमी पर चर्चा हुई है। हम सभी को चाहिए कि एक दूसरे के प्रयोगों से सीखें। हम सभी को एक दूसरे की क्षमता संवर्धन के लिए कार्य करना है।

### कॉफी टेबल बुक का विमोचन



समारोह में अतिथियों ने राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा द्वारा आयोजित किए गए विविध कार्यक्रमों और कार्यशालाओं पर आधारित कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के कार्यक्रमों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री का भी प्रदर्शन किया गया। •







## इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना महिलाओं के सशक्तीकरण का बड़ा माध्यम



**10** अगस्त, 2023 का दिन राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति एवं महिला सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक रहा, जब मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने एक और बजट घोषणा को पूरा करते हुए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर एवं लाभार्थी महिलाओं-छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान कर इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की।

महिला सशक्तीकरण में राजस्थान पूरे देश में सिरमौर बन रहा है। विकसित राजस्थान में महिला की अग्रणी भूमिका रहे, यह राज्य सरकार की मंशा है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना प्रदेश में एक नई क्रांति लेकर आई है। इससे आमजन को योजनाओं की जानकारी मिल रही है और उन्हें योजनाओं का पूरा लाभ मिल पा रहा है। महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का ऐतिहासिक कदम है।

निशुल्क स्मार्टफोन मिलने से महिलाओं को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके बेहतर परिणाम आगामी वर्षों में देखने को मिलेंगे। योजना के शुभारंभ के अवसर पर जयपुर के बिड़ला सभागार में समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में डिजिटल सखी हैंडबुक 'सीखो डिजिटल, सिखाओ डिजिटल' का विमोचन भी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से संबंधित लघु वीडियो फिल्म भी प्रदर्शित की गई। योजना के अंतर्गत चिरंजीवी परिवारों की 1.35

**डॉ. आशीष खंडेलवाल**  
सहायक निदेशक, जनसंपर्क

करोड़ महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं एवं छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाने की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। अब इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना आईटी क्षेत्र में क्रांति के साथ ही महिलाओं के सशक्तीकरण का बड़ा माध्यम बनेगी।

योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग हर महिला के हाथ में मोबाइल होगा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्मार्टफोन के लिए 6 हजार 800 रुपये लाभार्थियों को डीबीटी किए जा रहे हैं और शुरुआत में 20 जीबी डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब शिविरों में महिलाओं को बिना किसी परेशानी के ससम्मान स्मार्टफोन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। साथ ही, कैंप में उन्हें मोबाइल चलाने की जानकारी भी मिल रही है। लाभार्थियों को 3 साल तक निशुल्क इंटरनेट डेटा दिया जाएगा। योजना के दूसरे चरण में 80 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाने हैं।

**राज्य सरकार की अधिकांश गवर्नेंस आईटी आधारित**

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने देश में आईटी क्रांति का सपना देखा था, जो आज साकार हो रहा है। आज राज्य सरकार की अधिकांश गवर्नेंस आईटी आधारित हो रही है। प्रदेश में वर्तमान में 80 हजार से अधिक ई-मित्र





केन्द्रों के माध्यम से 600 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। आज राजस्थान आईटी के क्षेत्र में नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। राजीव गांधी दूरद्रष्टा एवं महिला सशक्तीकरण के पैरोकार थे। उनकी वजह से महिलाओं को पंचायतीराज संस्थाओं में आरक्षण का लाभ मिल पाया।

### ज्ञान ही शक्ति है

नॉलेज इज पावर की थीम पर यह योजना लाई गई है। स्मार्टफोन के माध्यम से महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच एवं जुड़ाव सुनिश्चित हो सकेगा। वे स्वयं लाभान्वित होने के साथ-साथ और महिलाओं को जागरूक कर सकेंगी।

### पहले चरण में लाभान्वित हो रही 40 लाख महिला लाभार्थी

योजना में पहले चरण में 40 लाख महिला लाभार्थियों को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) से अधिकृत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से स्मार्टफोन एवं सिम मय डेटा कनेक्टिविटी का वितरण किया जा रहा है। लाभार्थी शिविरों में अपने पसंद के स्मार्टफोन चुन रही हैं। इसके लिए लाभार्थियों को स्मार्टफोन व सिम के लिए 6,800 रुपए डीबीटी के माध्यम से ई-वॉलेट में जमा करवाए जा रहे हैं।

### प्रथम चरण में इन्हें मिल रहा स्मार्टफोन

1. सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राएं
2. उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएं
3. विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं
4. वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया
5. वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया

### योजना के उद्देश्य

यह योजना छात्राओं, विधवा एवं एकल नारी को सशक्त करने की राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है। इससे प्रदेश की महिलाओं में जागरूकता बढ़ेगी और वे अपने परिवार की समृद्धि और प्रगति में अधिक भागीदारी निभा पाएंगी। स्मार्टफोन की सहायता से दूर-दराज क्षेत्रों में पढ़ रही छात्राएं अपने परिवार से निरंतर संपर्क में रहने के साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकेंगी। लाभार्थी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगी। योजना से प्रदेश की महिलाओं को डिजिटल साक्षर किया जाएगा, जिससे वे समस्त योजनाओं का लाभ लेने के साथ बैंकिंग संबंधी कार्य स्वयं कर सकेंगी।

### वेबसाइट और टोल फ्री नंबर पर संपूर्ण जानकारी

योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन वितरण संबंधित जानकारी जनसूचना पोर्टल और टोल फ्री नंबर 181 पर ली जा सकती है। साथ ही, अपनी पात्रता की जांच जनसूचना पोर्टल और ई-मित्र प्लस मशीन के जरिए की जा सकती है। •







30-1-अगस्त, 2023 • राजस्थान सुजस



# 77 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की झलकियाँ

77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह में रंगा-रंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अनेक मनमोहक एवं आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।







## मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना कोई भूखा न सोए का संकल्प हो रहा साकार

**रा**ज्य सरकार आमजन को अधिक से अधिक राहत देने की मंशा के मद्देनजर फैसले कर रही है। इसी क्रम में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोट ने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत राज्य में लगभग एक करोड़ चार लाख से अधिक परिवारों को हर माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार कर आमजन को राहत देने का कार्य किया है। जनहित में लाई गई योजनाएं लोकतांत्रिक सरकार का आमजन के प्रति दायित्व हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के एनएफएसए परिवारों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए इस योजना की घोषणा इस वर्ष के बजट में की थी। राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष करीब 4 हजार 500 करोड़ रुपए व्यय करेगी। मुख्यमंत्री की इस संवेदनशील पहल से महंगाई के इस दौर में एक करोड़ से अधिक जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

### यह होगा निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट में

इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से जुड़े परिवारों को प्रतिमाह राशन की दुकान से अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलेगा। प्रदेश में कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में पाँस मशीन के माध्यम से वितरित किए जाने वाले इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट में एक-एक किलो चना दाल, चीनी व आयोडाइज्ड नमक, एक लीटर सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल, 100-100 ग्राम मिर्च पाउडर व धनिया पाउडर तथा 50 ग्राम हल्दी पाउडर निःशुल्क दिया जा रहा है।

दिनेश कुमार शर्मा  
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

### कोविड में आर्थिक सहायता प्राप्त परिवारों को भी मिलेगा राशन किट

कोविड के दौरान निराश्रित परिवारों का सर्वे कर लगभग 32 लाख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) एवं नॉन—एनएफएसए परिवारों को 5,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी। जिन नॉन—एनएफएसए परिवारों को कोविड में आर्थिक सहायता दी गई थी, उन्हें भी अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निःशुल्क राशन किट उपलब्ध करवाया जाएगा।







### राशन डीलरों का बढ़ा कमीशन

अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण पर राशन डीलरों को मिलने वाले कमीशन को 4 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति पैकेट कर दिया गया है। साथ ही, मुख्यमंत्री ने राज्य में राशन डीलरों को टेलिस्कोपिकरेट के आधार पर कमीशन देने एवं पॉस मशीन के पेटे राशन डीलर्स से कोई शुल्क नहीं लिए जाने की घोषणा की है।

### महंगाई से मिली राहत

राज्य सरकार ने अभिनव पहल करते हुए महंगाई राहत कैप लगाकर 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को दिया। 500 रुपये में

गैस सिलेंडर, 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, मनरेगा योजना में 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिवस के रोजगार एवं किसानों को 2,000 यूनिट तक प्रतिमाह निशुल्क बिजली जैसी योजनाओं से लोगों का जीवन सुगम हुआ है। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना से लगभग 1 करोड़ 4 लाख से अधिक घरों का बिजली बिल शून्य हो गया है। अब राज्य सरकार ने फ्यूल सरचार्ज भी समाप्त कर दिया है, जिस पर होने वाला 2,500 करोड़ रुपये का खर्च सरकार वहन करेगी। इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से राज्य सरकार जरूरतमंद लोगों को महज 8 रुपये में ससम्मान भोजन उपलब्ध करवा रही है। ●





# विधायक आवास परियोजना



हेतप्रकाश शर्मा  
सहायक निदेशक, जनसंपर्क

## जनप्रतिनिधियों को मिलेंगी बेहतर आवासीय सुविधाएं

**मु**ख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत 12 अगस्त को राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विधायक नगर (पश्चिम) में निर्मित विधायक आवास परियोजना का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधिवत रूप से परियोजना का उद्घाटन किया तथा लोकार्पण पट्टिका का अनावरण किया। विधायकों की आवास समस्या का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विधायक आवास परियोजना को मंजूरी दी थी। परियोजना में संपूर्ण फ्लैट्स पूर्ण सुविधाओं के साथ तैयार करवाये गए हैं। 444 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 160 आलीशान फ्लैट्स वाले इस प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड 23 माह में पूरा किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से जनप्रतिनिधियों एवं उनके परिवारों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर सकेंगे।

### सुरक्षा का विशेष ध्यान

छह बहुमंजिला टॉवर (जी+8) में 3,200 स्क्वायर फीट वाले कुल 160 फ्लैट्स में विधायकगणों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। पूरे परिसर के कॉमन एरिया (पार्किंग, ड्राइव-वे, बेसमेंट, लिफ्ट) में 80 से ज्यादा अत्याधुनिक और हाईरेंज के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

ऑटोमैटिक ब्रूम बैरियर, बैग स्कैनर और मुख्य द्वार पर अंडर व्हीकल







स्कैनर लगाया गया, जिसकी स्याय आई किसी गडबड़ी पर तुरंत सिस्टम को अलर्ट करेगी। सुरक्षा के मामले में सबसे खास 'इन्टूडर अलर्ट सिस्टम' है, जिससे कोई भी अवांछित व्यक्ति भवन में यदि बिना अनुमति के प्रवेश करेगा तो अलार्म बज जाएगा। इसके अलावा विधायकगण के लिए परिसर में डबल बेसमेंट में स्मार्ट पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें दोनों मंजिलों को मिलाकर 921 चौपाहिया वाहन-ईसीयू (इक्वेलेंट कार यूनिट) एक साथ पार्क किए जा सकेंगे।

#### प्रत्येक ब्लॉक में रिसेप्शन और गेस्ट रूम

परिसर के प्रत्येक ब्लॉक में विधायकगण से मिलने के लिए क्षेत्र से आने वाले आगंतुकों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन, वेटिंग लॉन्ज, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, पेंट्रिज, वॉशरूम, ड्राइवर डोरमेट्री कक्ष, लिफ्ट, सर्विस लिफ्ट और हर ब्लॉक्स पर 26 गेस्ट रूम (22 कमरे, 4 सुइट) भी बनाए गए हैं। इसके अलावा विधायकगण की सुविधा के लिए कॉफी हाउस, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, सैलून, शॉप्स भी बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त एलौपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

#### साज-सज्जा और सुविधाएं

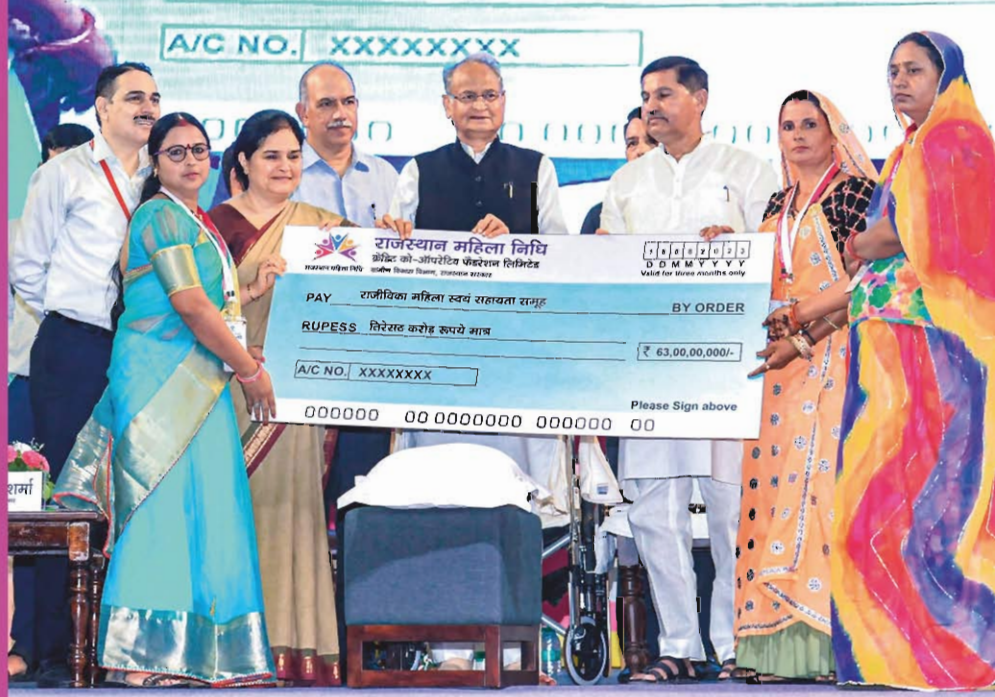
हर कमरे का इंटीरियर, कलर स्कीम्स, पर्दे, पेंटिंग्स, कारपेट, एंटिक और ओरनामेंटल ऑब्जेक्ट्स बहुत खूबसूरत रखे गए हैं। हर फ्लैट में लगाए गुणवत्तायुक्त और आकर्षक फर्नीचर, डबल बेड, सोफा, कुर्सियां, डाइनिंग टेबल, एलईडी, फ्रीज, एसी, पंखे, आरओ, मॉड्यूलर किचन, साज-सज्जा जैसी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है।

विधायकगण की फिटनेस को देखते हुए मंडल ने बेहतरीन व्यवस्थाएं की है। उन्हें ऊर्जावान और फिजिकली फिट बनाए रखने के लिए सेंट्रल पार्क, क्लब हाउस, स्वीमिंग पूल, जिम, योग-मेडिटेशन सेंटर, बिलियर्ड्स व टेबल टेनिस, इन्डोर गेम्स रखे गए हैं।

परिसर का 5 साल का रखा का रखरखाव भी मंडल द्वारा किया जाएगा उसके बाद इसका जिम्मा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दिया जाएगा। •



# सखी सम्मेलन



## राजीविका से जुड़कर महिलाएं निभा रही हैं विकास में अहम भूमिका

**रा**जीविका जैसे कार्यक्रमों से महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा अजमेर जिले से स्वयं सहायता समूहों की शुरुआत की गई। यह प्रयास इस वृहत रूप ले चुका है। राजीविका से जुड़कर महिलाएं विभिन्न प्रकार के उद्यमों एवं नवाचारों में भाग ले रही हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्हें अपनी क्षमताओं एवं संविधान प्रदत्त अधिकारों की पहचान हुई है। सहकारिता की भावना से कार्य करते हुए राजीविका समूहों से जुड़ी महिलाएं आज प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश में राजीविका के अंतर्गत 3.60 लाख समूहों का गठन कर लगभग 43 लाख महिलाओं को इनसे जोड़ा गया है। राज्य सरकार इन समूहों को 4 हजार 774 करोड़ का ऋण उपलब्ध करवा रही है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार का एक अहम प्रयास है।

जयपुर के जेईसीसी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिषद् (राजीविका) द्वारा आयोजित सखी सम्मेलन में प्रदेश भर से राजीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। साथ ही, बड़ी संख्या में महिलाएं वीसी के माध्यम से भी कार्यक्रम से जुड़ी। मुख्यमंत्री ने बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 381 करोड़ रुपए की ऋण राशि के चेक स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सौंपे। साथ ही, राजस्थान महिला निधि से दिए जाने वाले 63 करोड़ रुपए, आजीविका संवर्द्धन सहायता द्वारा दिए जाने वाले 160 करोड़ रुपए एवं जलग्रहण विकास कन्वर्जेन्स सहायता द्वारा दिए जाने वाले 98 करोड़ रुपए की राशि के चेक भी राजीविका से जुड़ी महिलाओं को प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को स्कूटी की चाबी सौंपी एवं सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित किया।

**रजनीश शर्मा**  
उपनिदेशक, जनसंपर्क

### मुख्यमंत्री ने किया विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समर्थ सखी योजना, इंदिरा रसोई योजना (ग्रामीण), एकीकृत खेती क्लस्टर (आईएफसी) कार्यक्रम एवं डिजिटल सखी योजना का शुभारंभ किया। डिजिटल सखी योजना के तहत महिलाओं को चरणबद्ध रूप से डिजिटल प्रशिक्षण दिया जाएगा। एकीकृत खेती क्लस्टर कार्यक्रम के द्वारा महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।

### मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं

- राजीविका कैडर से जुड़ी महिलाओं के मानदेय में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी।
- राजीविका से जुड़ी महिलाओं को कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में 1 हजार करोड़ रुपयों का ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा।
- राजीविका से जुड़ी महिलाएं 2.5 प्रतिशत की जगह शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर स्कूटी खरीद पाएंगी।
- सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई एवं निर्माण कार्य।
- इंदिरा रसोई योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 1,000 रसोइयों का संचालन एवं प्रबंधन राजीविका स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा।

महिलाओं को समान अवसर देने और उनकी उन्नति सुनिश्चित करने की सोच के साथ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2010 में राजीविका का शुभारंभ किया गया था। राजीविका समूहों के माध्यम से महिलाओं के जीवन में आर्थिक समृद्धि आई है। राजीविका स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं की आय में बढ़ोतरी हुई है, जिससे वे अपने परिवार का बेहतर पालन-पोषण कर पा रही हैं। •



# मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2023

## कला का सम्मान और कलाकारों को आर्थिक संबल

अमनदीप विभोई  
जनसंपर्क अधिकारी

श्री अशोक गहलोट ने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2023 का शुभारंभ किया। इस योजना में कलाकारों को वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, योजना के तहत लोक कलाकारों को प्रतिवर्ष 100 दिन विभिन्न राजकीय कार्यक्रमों में कला प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में 100 करोड़ का लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 3,000 लोक कलाकारों के खाते में 5-5 हजार रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए। साथ ही, लोक कलाकारों को वाद्य यंत्र एवं लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड भी प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2023 से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। साथ ही, योजना से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोक कलाकारों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोक कलाकारों की प्रतिभा से राज्य को वैश्विक पटल पर जाना जाता है। राज्य सरकार की इस ऐतिहासिक पहल से लोक कलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा राजकीय कार्यक्रमों में लोक कलाकारों को मिलने वाले मानदेय में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार की योजनाओं से आने वाली पीढ़ियों के लिए लोक कलाओं को सहेजा जा सकेगा। •

**रा**जस्थान का  
प्रत्येक अंचल

विशिष्ट कला एवं संस्कृति लिए

हुए है। प्रदेश के लोक कलाकारों ने

अपनी प्रतिभा के दम पर देश-विदेश में राज्य की एक अलग पहचान बनाई है। पूरे विश्व में प्रदेश के लोक कलाकारों को सराहा जा रहा है। लोक कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन के संचालन में अपना अहम योगदान दिया है। कला एवं संस्कृति समाज की अमूल्य धरोहर है। राज्य सरकार इनके संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में अपनी कला के माध्यम से आजीविका चलाने वाले कलाकारों की कला को सम्मान एवं उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए 11 अगस्त को मुख्यमंत्री





# डायल फ्यूचर

## मुनहरे भविष्य के द्वार पर दस्तक



**प्र**देश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नए शैक्षणिक सत्र के आगाज में राज्य के सभी सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूलों में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं के लिए स्ट्रीम और विषय चयन में मार्गदर्शन के लिए कॅरियर काउंसिलिंग की अनूठी पहल के तौर डायल फ्यूचर (भविष्य की राह) कार्यक्रम का संचालन किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस इनिशिएटिव के तहत 28 जून से 15 जुलाई तक सभी जिलों के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परामर्श कार्यक्रम संचालित किया।

शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला एवं शिक्षा राज्यमंत्री श्रीमती जाहिदा खान द्वारा इस कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद प्रदेशभर में 87 हजार 57 विद्यार्थियों की कॅरियर काउंसिलिंग की गई। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के जयपुर डिविजन में 2,228, अजमेर डिविजन में 9,382, जोधपुर डिविजन में 13,163, भरतपुर डिविजन में 2,296, पाली डिविजन में 6,574, चूरू डिविजन में 13,992, उदयपुर डिविजन में 24,436, बीकानेर डिविजन में 5,017 तथा कोटा डिविजन में 9,307 छात्र-छात्राओं को काउंसिलिंग से सीधा लाभ मिला।

स्कूलों और संभाग के स्तर पर गठित हेल्प डेस्क की गतिविधियों के समापन के बाद अब 21 जुलाई से राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (RSCERT), उदयपुर के स्तर पर एक राज्य स्तरीय हेल्पलाइन शुरू की गई है। इस पर प्रदेशभर के विद्यार्थी संपर्क कर कॅरियर परामर्श विशेषज्ञ से बात कर अपने भविष्य की राह चुन सकते हैं। इसके लिए आरएससीईआरटी की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कार्यक्रम की गतिविधियों का जायजा लेकर इसे सफल बनाने के लिए राज्य स्तर पर शासन सचिव श्री नवीन जैन द्वारा सतत मॉनिटरिंग की गई। वहीं संभाग, जिला और ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग के 348 कार्यालयों से संबंधित संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक),

**मनमोहन हर्ष**  
उप निदेशक, जनसंपर्क

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों ने अपने क्षेत्राधिकार में स्कूलों का दौरा कर गतिविधियों का निरीक्षण किया।

दसवीं कक्षा में पास होने के बाद विद्यार्थियों में अपनी रुचि, क्षमता और अभिवृत्ति के आधार पर कॅरियर गोल्स को ध्यान में रखते हुए उचित संकाय (विषय) के चयन की समझ विकसित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें विद्यार्थियों को परंपरागत रूप से संकाय चयन के स्थान पर कॅरियर विकल्पों के अनुसार विषय के चयन के लिए प्रेरित किया गया। डायल फ्यूचर और फ्यूचर स्टेप्स (भविष्य की राह) इनिशिएटिव के तहत राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों से एक-एक शिक्षक का पथ प्रदर्शक के रूप में चयन किया गया। इनके आमुखीकरण के लिए मॉड्यूल निर्माण, स्टेट रिसोर्स ग्रुप तैयार करने एवं हेल्प डेस्क स्थापित करने का कार्य आरएससीईआरटी, उदयपुर द्वारा संपादित किया गया। इसके अलावा जयपुर जौन (जयपुर एवं भरतपुर संभाग), कोटा जौन (कोटा एवं उदयपुर संभाग), जोधपुर जौन (जोधपुर एवं पाली संभाग) तथा बीकानेर जौन (बीकानेर, चूरू एवं अजमेर संभाग) में हेल्प डेस्क बनाकर विद्यार्थियों की सुविधा के लिए संभाग वार 5-5 मोबाइल नंबरों की सीरीज जारी गई। इन हेल्प डेस्क पर विभाग द्वारा कॅरियर काउंसिलिंग में दक्ष 5-5 अनुभवी शिक्षकों को नियोजित किया गया, जिन्होंने प्रोग्राम अवधि के दौरान 1,400 विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया। डायल फ्यूचर कार्यक्रम की गतिविधियों का बोशर भी तैयार करते हुए इसे सभी स्कूलों में डाइट के माध्यम से वितरित किया गया। •





गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए राजस्थान की अभिनव पहल

## राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक – 2023

**रा**ज्य सरकार ने ओला, स्विगी, उबर, जोमेटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गिग वर्कर्स के रूप में जुड़े लाखों युवाओं को सौगात दी है। इन गिग वर्कर्स के हितों का संरक्षण कर अब उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य विधानसभा ने 24 जुलाई को राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक – 2023 पारित किया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आजीविका अर्जित कर रहे लाखों गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है।

### राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड की स्थापना

राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक – 2023 के माध्यम से बनने वाले अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। साथ ही, राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि का गठन किया जाएगा।

यह बोर्ड प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा। साथ ही, पंजीकृत गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाओं को मॉनिटरिंग करने के साथ ही ऐसी योजनाओं के प्रशासन के लिए राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन योजनाओं के अनुसार फायदों तक गिग वर्कर्स की पहुंच हो और उनके कार्य करने की स्थिति बेहतर हो। यह बोर्ड गिग वर्कर्स के अधिकारों से संबंधित शिकायतों और अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन से संबंधित मामलों का समयबद्ध निवारण भी सुनिश्चित करेगा।

**अभिषेक जैन**

सहायक निदेशक, जनसंपर्क

गिग वर्कर्स के पंजीकरण के लिए एग्रीगेटर अधिनियम के लागू होने के 60 दिनों में गिग वर्कर्स का डेटा बेस राज्य सरकार को उपलब्ध कराएंगे। राज्य सरकार एग्रीगेटर्स का रजिस्टर अपने वेब पोर्टल पर प्रकाशित करेगी। इस अधिनियम से गिग वर्कर्स को राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा और उनकी शिकायतों पर उन्हें सुनवाई का अवसर प्राप्त होगा। गिग वर्कर्स का बोर्ड में प्रतिनिधित्व भी होगा जिससे वे उनके कल्याण के लिये लिए जाने वाले निर्णयों में भाग ले सकेंगे। अधिनियम के अंतर्गत गिग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाएगी जिसके समक्ष व्यक्तिशः अथवा ऑनलाइन माध्यम से याचिका प्रस्तुत की जा सकेंगी। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में कम कौशल वाले युवाओं के लिए गिग कार्य से रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं।

अर्थव्यवस्था और रोजगार में बड़े योगदान के बावजूद गिग वर्कर्स अभी तक श्रम कानूनों के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसे में उन्हें पारंपरिक कर्मचारियों की तरह संरक्षण नहीं मिल पाता है। इस अधिनियम से गिग वर्कर्स के हितों का संरक्षण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व शोषण से बचाने के लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाने तथा इसके अंतर्गत गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने 200 करोड़ की राशि से गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डवलपमेंट फंड के गठन की भी घोषणा की है। •





## मृत देह की गरिमा मुनिश्चित करेगा राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक -2023

**रा**जस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक -2023 मृत शरीरों की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए इनके धरना-प्रदर्शन में किए जाने वाले दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाएगा। इस विधेयक से लावारिस शवों की डीएनए एवं जेनेटिक प्रोफाइलिंग कर डाटा संरक्षित भी किया जाएगा ताकि भविष्य में उनकी पहचान हो सके। 20 जुलाई को विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। मृत शवों को रखकर धरना-प्रदर्शन की प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वर्ष 2014 से 2018 तक इस तरह की 82 एवं वर्ष 2019 से अब तक 306 घटनाएं हुई हैं। इससे पहले ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रूप से रोक लगाने के लिए विधिक प्रावधान नहीं था, इसीलिए यह विधेयक लाया गया। सजा व जुमनि का प्रावधान परिजन द्वारा मृत व्यक्ति का शव नहीं लेने की स्थिति में राजस्थान मृत शरीर का सम्मान, विधेयक -2023 में एक वर्ष तक की सजा व जुमनि का प्रावधान किया गया है। साथ ही, परिजन द्वारा धरना-प्रदर्शन में शव का उपयोग करने पर भी 2 वर्ष तक की सजा व जुमनि का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, परिजन से भिन्न अन्य व्यक्ति द्वारा शव का विरोध के लिए इस्तेमाल करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा एवं जुमनि से दंडित करने का प्रावधान किया गया है।

**युवराज श्रीमाल**  
जनसंपर्क अधिकारी

कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अंतिम संस्कार की शक्ति कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मृतक का अंतिम संस्कार 24 घंटे में कराने की शक्ति प्रदान की गई है। यह अवधि विशेष परिस्थितियों में बढ़ाई भी जा सकेगी। साथ ही, परिजन द्वारा शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की स्थिति में लोक प्राधिकारी द्वारा अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। सिविल रिट पिटीशन आश्रय अधिकार अभियान बनाम यूनिचन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने मृत शरीरों के शिष्टापूर्वक दफन या अंतिम संस्कार के निर्देश प्रदान किए थे।

इस निर्देशों की पालना में इस विधेयक में लावारिस शवों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करना और इन शवों की डीएनए प्रोफाइलिंग और डिजिटाइजेशन के माध्यम से आनुवंशिक जेनेटिक डाटा सूचना का संरक्षण और सूचना की गोपनीयता रखने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इससे लावारिस शवों का रिकॉर्ड संधारित हो सकेगा और उनकी भविष्य में पहचान भी हो सकेगी। •



स्वतंत्रता दिवस पर बना अनूठा विश्व रिकॉर्ड

## एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने किया संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन



देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान में सरकारी और गैर-सरकारी

स्कूलों के एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने महज 15 मिनट की समयावधि में एक साथ संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन करते हुए एक अनूठा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस विश्व रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के इंडिया एडिशन में दर्ज करते हुए राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग के नाम सर्टिफिकेट जारी किया गया है। आजादी के पर्व के मौके पर जब पूरा देश मातृभूमि का वंदन करते हुए जीवन में इसके लिए कुछ कर गुजरने के संकल्प को दोहराता है, ऐसे में राजस्थान के 78 हजार 422 स्कूलों में एक करोड़ 3 लाख 36 हजार 354 विद्यार्थियों के साथ-साथ 5 लाख 73 हजार 724 शिक्षक एवं कार्मिकों द्वारा 15 मिनट की अवधि में पूरे प्रदेश में एक साथ संविधान और मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का संकल्प लेकर विश्व कीर्तिमान बनाना देश और प्रदेश के इतिहास में एक नायाब नजीर है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करते हुए कई नवाचार किए जा रहे हैं, इसी के परिणामस्वरूप संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों के वाचन की इस गतिविधि से छठा विश्व कीर्तिमान राजस्थान के नाम दर्ज हुआ है। इससे पहले प्रदेश में कोरोना काल में जो बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह गए थे, उनके लिए लर्निंग गैप्स की पूर्ति के लिए राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स का संचालन किया गया। राज्य के कक्षा 3 से 8 तक के 65 हजार विद्यालयों के लगभग 45 लाख विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल्स की जांच के लिए 1.35 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने विश्व कीर्तिमान बनाया था। इसके बाद राजस्थान के सभी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 12 अगस्त, 2022 को प्रातः 10.15 बजे से 10.40 बजे तक एक साथ पांच देशभक्ति गीत गाएं। इसमें सभी जिलों में कक्षा 1 से 12 के एक करोड़ 12 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लेकर दूसरा विश्व कीर्तिमान बनाया।

अरुण कुमार जोशी  
अतिरिक्त निदेशक, जनसंपर्क

वर्ष 2022 में गांधी जयंती के अवसर पर राज्य में सामूहिक सर्वधर्म प्रार्थना सभा में राज्य के एक करोड़ 47 लाख से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी से तीसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान के स्कूलों में नो-बैग-डे के नवाचार के तहत पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती (19 नवंबर, 2022) पर शुरू की गई चेस इन स्कूल एक्टिविटी में एक साथ 38 लाख 21 हजार 9 विद्यार्थियों ने भाग लेकर चौथा विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं इस साल की शुरुआत में रोहट (पाली) में राज्य में 67 वर्ष बाद आयोजित राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जंबूरी में टेम्पेरी स्ट्रेडियम निर्माण का भी विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। ये सभी कीर्तिमान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान वाचन किया जाएगा। यह कार्यक्रम विद्यालयों में नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है। इसी दिशा में राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नागरिकों में संविधान के मूल्यों और मूल कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूकता लाने की सोच के साथ प्रदेश के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में इस आयोजन की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। सभी स्कूलों में 15 अगस्त को प्रातः 8.15 बजे से 8.30 बजे की समयावधि में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य अतिथियों और आम नागरिकों की उपस्थिति में संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन किया गया। इस प्रकार प्रदेश में 15 अगस्त को 78 हजार 422 स्कूलों में एक करोड़ 3



लाख 36 हजार 354 विद्यार्थियों तथा 5 लाख 73 हजार 724 शिक्षक एवं कार्मिकों द्वारा 15 मिनट की अवधि में पूरे प्रदेश में एक साथ संविधान और मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का संकल्प लेकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया।

### राज्य में 24,681 करोड़ रुपए निवेश के 7 प्रस्ताव मंजूर

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर विनिधान बोर्ड (बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट) की पांचवीं बैठक में राज्य में 24 हजार 681 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 7 परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज देने की मंजूरी दी है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की पांचवीं बैठक में मंजूर प्रस्तावों से 10 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गत साढ़े चार वर्षों में कई महत्वपूर्ण नीतियां एवं कार्यक्रम लागू किए हैं। राजस्थान में एमएसएमई नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिपस-2019), रिपस 2022, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी-2019, वन स्टॉप शॉप प्रणाली एवं सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्यमियों एवं निवेशकों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे प्रदेश में निवेश एवं रोजगार में वृद्धि हुई है।

बैठक में उद्यमों को पैकेज, रियायत, छूट तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में आए प्रस्तावों को बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई। अनुमोदित प्रस्तावों में प्रमुख रूप से सोलर सैल एवं मॉड्यूल्स, ऑटो कॉम्पोनेन्ट्स, जूस एवं डेयरी उत्पाद, सीमेंट क्षेत्रों से संबंधित हैं। वन स्टॉप शॉप प्रणाली के अंतर्गत निवेश प्रस्तावों को त्वरित स्वीकृति एवं अनुमति प्रदान करने के उद्देश्य से गठित इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं जबकि उद्योग मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं।

#### इन प्रस्तावों को दी मंजूरी:

1. कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना : सिरोही जिले के पिंडवाडा में।
2. हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना : चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार में।
3. वारी एनर्जीज लिमिटेड की परियोजना : जोधपुर जिले के कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र में।
4. जेएसडब्ल्यू रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की परियोजना : बाड़मेर में।
5. बैक्सी ग्रुप की परियोजना: ऑटो कॉम्पोनेन्ट्स : भिवाड़ी एवं नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में।



6. कंधारी ग्लोबल बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना : बूंदी जिले में।
7. श्री सीमेंट लिमिटेड की परियोजना : ब्यावर जिले के जैतारण में।

### राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड बैरवा, बेरवा जाति वर्ग की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा।

बोर्ड समाज के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करने, वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय करने, समाज के परंपरागत व्यवसाय को वर्तमान तौर-तरीकों से आगे बढ़ाने, रोजगार को बढ़ावा देने तथा समाज के शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन के संबंध में सुझाव देगा। साथ ही यह बोर्ड सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने सहित अन्य सुझाव भी राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्य (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य) होंगे। साथ ही, उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक स्तरीय अधिकारी बोर्ड में सचिव होंगे। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

### प्रदेश के 130 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खुलेंगे नवीन संकाय

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शैक्षिक उत्थान के लिए अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 130 विद्यालयों में नवीन संकाय खोलने और विद्यालयों को क्रमोन्नत किए जाने के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

श्री गहलोत की स्वीकृति से 29 विद्यालयों में विज्ञान संकाय, 48 में वाणिज्य संकाय, 2 में कला संकाय तथा 51 में कृषि संकाय खोले जाएंगे। नए संकायों के संचालन के लिए स्कूल व्याख्याता के 317 एवं प्रयोगशाला सहायक के 29 पद सृजित होंगे। इससे विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा के बाद अपनी रुचि के विषय नजदीक ही पढ़ने का अवसर मिलेगा।

### 240 राजकीय विद्यालय होंगे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विविध श्रेणी के 240 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में



गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। श्री गहलोट की स्वीकृति से प्राथमिक स्तर के 71, उच्च प्राथमिक स्तर के 88 एवं उच्च माध्यमिक स्तर के 81 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बदला जाएगा। इनमें 18 बालिका विद्यालय शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। साथ ही, जिन विद्यालयों में 200 से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, वहां भी प्राथमिकता से अंग्रेजी माध्यम विंग शुरू करने की घोषणा की गई थी। जयपुर के विद्याधर नगर स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यहां विद्यालय संचालन के लिए 28 नवीन पद भी सृजित किए जाएंगे। सृजित होने वाले पदों में व्याख्याता के 5, सहायक प्रशासनिक अधिकारी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 1-1, अध्यापक लेवल-1 के 9, अध्यापक लेवल-2 के 6, प्रयोगशाला सहायक के 2 तथा प्रयोगशाला परिचारक के 4 पद शामिल हैं।

### विधानसभा चुनाव में निशक्तजनों को मतदान के लिए मिलेगी ढील चेयर

राजस्थान विधानसभा चुनाव-2023 में निशक्तजन मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर ढील चेयर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोट ने 10 हजार 72 ढीलचेयर्स की खरीद के लिए 8.76 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। राज्य में निशक्तजन मतदाताओं की सुविधा के लिए वर्तमान में 10 हजार 734 ढील चेयर्स उपलब्ध हैं। अब 10 हजार 72 अतिरिक्त ढील चेयर्स की खरीद की जाएगी। इन्हें मतदान के बाद राजकीय चिकित्सालयों में रखा जाएगा, जिन्हें आगामी निर्वाचन में भी इस्तेमाल लिया जा सकेगा।

### कोरोना से अनाथ बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर मिलेगी सरकारी नौकरी

राज्य सरकार कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर अनुकंपात्मक नियुक्ति देगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोट ने इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के अनुसार अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर पे मैट्रिक्स एल-9 में नियुक्ति दी जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार वे अनाथ बालक/बालिकाएं नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे, जिनके जैविक अथवा दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च, 2023 अथवा इससे पूर्व हो चुकी हो। साथ ही, ऐसे अनाथ बालक/बालिका जिसके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी हो तथा दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 या उससे पूर्व हुई हो एवं अनाथ होने के समय जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, को भी नियुक्ति दी जा सकेगी। प्रस्ताव में अनाथ के माता-पिता की मृत्यु की अंतिम तिथि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना-2021 में प्रावधित 15 अक्टूबर,

2022 से विस्तारित करते हुए 31 मार्च, 2023 की गई है। मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा की थी।

### तारानगर के 10 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में होगा माइनरों का निर्माण

चुरू जिले के तारानगर क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए अब सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर के अंतर्गत 10 हजार 455 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में 135 करोड़ रुपए से माइनरों का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोट ने कार्यों के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोट के इस निर्णय से नहर के अंतर्गत धीरवास सब माइनर, देवगढ़ माइनर, डूंगरपुरा माइनर, मेहरासर माइनर, बिल्यू माइनर और तारानगर माइनर का निर्माण होगा। इससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

इससे धीरवास बड़ा, धीरवास छोटा, साहवा, दुलेरी, भनीण, डाबड़ी बड़ी, डाबड़ी छोटी, ढाणी मेघसर, ढाणी चारपान, ढाणी कुल्हरियान, कालवास, झाड़सर कांधलान, झाड़सर गंजिया, लूडणिया, देवगढ़, झाड़सर कांधलान, डूंगरपुरा, अमरासर, देवासर, मेहरासर उपाधियान, रातूसर, बिल्यूबास महियान, निमरासर, मेहरासर, तारानगर कस्बा, जिगसाना टिब्बा, जिगसाना ताल, जोरजीका बास, सेउवा, ओझरिया, मेहलाणा गांवों के ग्रामीण लाभान्वित होंगे।

### मिशन 2030 के लिए 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव लेगी राज्य सरकार

राज्य सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन कर जनकल्याणकारी योजनाओं से हर व्यक्ति को लाभान्वित किया है। अब राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए राज्य सरकार ने मिशन 2030 का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए मिशन 2030 की मुहिम चलाकर अर्थशास्त्रियों, लेखकों, पत्रकारों, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, बुद्धिजीवियों, खिलाड़ियों सहित एक करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव लिए जाएंगे। राज्य सरकार इन्हें समाहित कर मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। वर्ष 2018-19 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 9 लाख 11 हजार करोड़ रुपए थी। यह आज करीब 14.14 लाख करोड़ रुपए है। इसे वर्ष 2030 तक करीब ढाई गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रुपए ले जाने का लक्ष्य है।





## युवा बोर्ड अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को सौंपा नवीन युवा नीति का ड्राफ्ट

जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महापंचायत 'युवा संकल्प' में युवा बोर्ड के अध्यक्ष श्री सीताराम लांबा ने मुख्यमंत्री को नवीन युवा नीति का ड्राफ्ट सौंपा। राज्य की सशक्त युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने युवाओं के लिए एक समर्पित नीति बनाने का निर्णय लिया था। नवीन युवा नीति का ड्राफ्ट यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड (यूएनएफपीए) की तकनीकी सहायता से राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है। यह नीति सतत विकास लक्ष्यों और संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ संरेखित है। इसमें राजस्थान के युवाओं की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं को सम्मिलित किया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास के लिए स्वस्थ, कुशल, सामाजिक रूप से जिम्मेदार, नैतिक रूप से जागरूक, आर्थिक रूप से सशक्त एवं सक्रिय नागरिक बनाने के लिए उचित अवसर एवं सकारात्मक वातावरण प्रदान करना है। नीति में 18 विशेष समूह शामिल हैं : युवा लड़कियां, महिलाएं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय के युवा, शहरी मलिन बस्तियों के युवा, प्रवासी युवा, विकलांग युवा, जोखिम में युवा, मानव तस्करी और हिंसा से प्रभावित युवा, एलजीबीटीक्यूआईएयुवा आदि। नीति पांच प्राथमिक विषयों पर कार्य करेगी : 1. शिक्षा, 2. उद्यमिता एवं रोजगार, 3. स्वास्थ्य एवं खेल, 4. युवा नेतृत्व एवं विकास, 5. सामाजिक न्याय एवं जेंडर समानता।

## विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध घुमंतु वर्ग की छात्राएं अब 50 प्रतिशत अंक पर स्कूटी योजना में होंगी पात्र

राज्य सरकार ने विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध घुमंतु वर्ग की छात्राओं को स्कूटी प्राप्त करने के लिए पात्रता में राहत दी है। अब वे उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए पात्र होंगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने योजना के अंतर्गत ऐसी छात्राओं के प्राप्तांक सीमा में शिथिलता प्रदान कर प्राप्तांक में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अभी तक इन वर्गों की छात्राओं के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा में 60 प्रतिशत एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता थी। अब देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना की तर्ज पर इन वर्गों की छात्राओं के लिए 50 प्रतिशत अंक की पात्रता निर्धारित की गई है। योजना में अंतर्गत विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध घुमंतु वर्ग की विशेष योग्यजन छात्राओं के लिए 6 स्कूटी आरक्षित भी रखी जाएंगी।

## प्रदेश के 31 संस्कृत महाविद्यालयों में ध्यान कक्षा का होगा निर्माण

विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए 31 संस्कृत महाविद्यालयों में ध्यान कक्षा का निर्माण होगा। इसमें 4.65 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निर्माण के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। प्रत्येक ध्यान कक्षा का निर्माण 15 लाख रुपए की लागत से होगा। इनमें योग एवं ध्यान की नियमित कक्षाएं संचालित की जाएंगी।

### इन महाविद्यालयों में बनेंगे कक्षा:

- राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, चिराना, सीकर, गनोड़ा, दौसा, कोटा, अजमेर, कोटकासिम, मनोहरपुर और बोली।
- राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय महापुरा, चौथवाड़ी, तितरिया, कालाडेरा, श्रीमाधोपुर, सालासर, अलवर, तालाब गांव, नीमकाथाना, पीठ डूंगरपुर, सरमथुरा धौलपुर, चक, चौथ का बरवाड़ा, चेचट, कुंड गेट सांवर, नाथद्वारा और सैदपुरा भरतपुर

## राजस्थान पुलिस अकादमी में खुलेगा साइबर अपराध जांच केंद्र

प्रदेशवासियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने तथा साइबर अपराधों की जांच के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी में साइबर अपराध जांच केंद्र (Cyber Crime Investigation Centre) की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने केंद्र के लिए 11.73 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

यह केंद्र कानून प्रवर्तन एजेंसियों, साइबर सुरक्षा पेशेवरों, कानूनी विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और उद्योग प्रतिनिधियों जैसे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की राय लेगा। साथ ही, बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को अनुसंधान में दक्ष बनाएगा।

इसके अलावा अकादमी में स्थित स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का भी निर्माण होगा। यह 400 मीटर लंबाई और 8 लेन का होगा। इसके निर्माण में 7.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

## 9 जिलों में शुरू होंगे 10 अल्पसंख्यक छात्रावास

अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर भविष्य संवार सकेंगे। इनके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनूं, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर एवं उदयपुर जिले में छात्रावास संचालित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 9 जिलों में 10 छात्रावासों के संचालन और नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस स्वीकृति से उदयपुर में 100 और अन्य सभी जिलों के छात्रावासों की क्षमता 50-50 सीट की रखी गई है।



जैसलमेर में बालक एवं बालिका छात्रावास (कुल दो) एवं बीकानेर के खाजूवाला, बूंदी, सीकर में बालक छात्रावास तथा जालोर, झुंझुनूं, नागौर, सवाई माधोपुर और उदयपुर में बालिका छात्रावास संचालित होंगे। साथ ही, जैसलमेर, झुंझुनूं और जालोर बालिका छात्रावासों में महिला छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-द्वितीय और जैसलमेर के बालक छात्रावास में पुरुष छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-द्वितीय के एक-एक पदों का भी सृजन किया गया है।

### लक्ष्मणगढ़ में स्काउट आवासीय विद्यालय का बनेगा भवन

सीकर जिले के उपखंड लक्ष्मणगढ़ के गांव छोटी खुड़ी में प्रदेश का दूसरा राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विद्यालय भवन निर्माण के लिए 6.75 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है।

श्री गहलोत की स्वीकृति से कक्षा कक्षा, छात्रावास और 2/3 बीएचके कर्मचारी कक्षाओं का निर्माण होगा। विद्यालय संचालन के लिए 7 नवीन पदों का भी सृजन किया जा रहा है। इन पदों में प्रधानाध्यापक, वार्डन (द्वितीय श्रेणी अध्यापक), पीटीआई एवं कनिष्ठ सहायक का 1-1 पद तथा अध्यापक ग्रेड-2 के 3 पदों सहित कुल 7 पद शामिल हैं।

अभी विद्यालय अस्थायी भवन में संचालित है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रवेश लिए गए हैं। अब प्रतिवर्ष एक-एक कक्षा बढ़ाई जाएगी। आवासीय विद्यालय के जरिए विद्यार्थी स्कूल शिक्षा के साथ-साथ अनुशासन और मानवता के प्रति सेवा भावना का पाठ पढ़ पाएंगे।

### धौलपुर लिफ्ट परियोजना से मजबूत होगा सिंचाई तंत्र

राज्य सरकार प्रदेश में सिंचाई तंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए 177.04 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

श्री गहलोत के इस निर्णय से धौलपुर कम्प्यूनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के अंतर्गत धौलपुर, राजाखेड़ा एवं सेपऊ के 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। इससे लगभग 15 हजार किसान लाभान्वित होंगे।

इस परियोजना से धौलपुर जिले में जलस्तर में वृद्धि होगी। सिंचाई के लिए लंबे समय तक पर्याप्त जल मिलने से किसान वर्षभर खेती कर सकेंगे और उनकी आय भी बढ़ेगी।

### कुकड़ीपाड़ा टैक में सोलर आधारित सिंचाई परियोजना

बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दरोबड़िया के कुकड़ीपाड़ा टैक में सोलर आधारित सिंचाई परियोजना पर कार्य होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 6.80 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

### नेवटा बांध और कानोता बांध बनेगा ईको एडवेंचर टूरिज्म साइट

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के नेवटा और कानोता बांध को अब ईको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार इनमें विकास कार्यों पर 6.24 करोड़ रुपए व्यय करेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। जयपुर स्थित कानोता बांध पर लगभग 2.48 करोड़ रुपए की लागत से बर्ड वॉचिंग प्लेटफार्म, छतरी का निर्माण, 600 मीटर लंबी पैरापेट दीवार सहित विभिन्न प्रकार के निर्माण किए जाएंगे। नेवटा बांध पर लगभग 3.75 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे। यहां प्रवेश द्वार से बांध की तरफ जाने वाला मार्ग भी बनाया जाएगा।

### राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड का गठन

राज्य सरकार द्वारा तेली समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसके गठन का आदेश जारी कर दिया है। यह बोर्ड तेली समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए नवीन योजनाएं बनाकर तथा समस्याओं की पहचान कर राज्य सरकार को सुझाव प्रस्तुत करेगा। बोर्ड तेली घाणी के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता संवर्धन, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने, बोर्ड से संबंधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने, अन्य राज्यों के उपयोगी अनुभवों की जानकारी साझा करने तथा विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित बोर्ड से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की मॉनिटरिंग सहित अन्य कार्य करेगा। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्यों सहित कुल 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। साथ ही उद्योग, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, श्रम एवं रोजगार तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आदि विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि (संयुक्त निदेशक स्तर के विभागीय अधिकारी), कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी, राजस्थान स्वर्ण कला विकास बोर्ड सचिव इस बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। वहीं, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के संयुक्त निदेशक स्तरीय अधिकारी बोर्ड में सचिव के रूप में कार्य करेंगे। कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा।



## राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड गठन को मंजूरी

कुमावत जाति वर्ग की समस्याओं के समाधान तथा परंपरागत स्थापत्य कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोट ने बोर्ड गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य गैर सरकारी सदस्य होंगे। स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के शासन सचिव तथा उद्योग विभाग, श्रम विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आयुक्त इसमें सरकारी सदस्य होंगे। साथ ही, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक स्तर के अधिकारी बोर्ड में सचिव का कार्य करेंगे। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बोर्ड में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। बोर्ड के गठन का उद्देश्य कुमावत जाति वर्ग के लोगों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करना, कुमावत जाति वर्ग की सामाजिक बुराइयों/कुसूरियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने हेतु राज्य सरकार को अभिशंसा के साथ सुझाव देना, समाज के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं की विभिन्न विभागों से समन्वय कर सुझाव देना तथा परम्परागत व्यवसाय के वर्तमान तौर-तरीकों में बदलाव हेतु सुझाव देना है। साथ ही, शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नयन हेतु राज्य सरकार को सुझाव देना, परंपरागत स्थापत्य कला को बढ़ावे देने के संबंध में सुझाव देना तथा आर्थिक उन्नयन एवं रोजगार को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव का कार्य भी बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

## प्रदेश के 28 जिलों में खुलेंगे विवेकानंद यूथ हॉस्टल

प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब जिला मुख्यालयों में आवास की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 28 जिलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोट ने हॉस्टल निर्माण के लिए 78.18 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। विवेकानंद यूथ हॉस्टल के निर्माण पूर्ण होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 84 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इन हॉस्टल में 50-50 आवासीय क्षमता होगी। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा युवा आवास पूर्व से ही संचालित हैं। इनके अलावा अन्य 28 जिलों में हॉस्टल शुरू होने से 33 जिलों के युवाओं को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

## राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक - 2023 पारित

विधान सभा में 21 जुलाई, 2023 को राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक - 2023 को पारित कर दिया। केंद्र सरकार ने 10 अगस्त, 2020 को ईज ऑफ इर्इंग बिजनेस के तहत एक पत्र लिखकर कानून की समीक्षा करते हुए इसमें गैर-अपराधीकरण के प्रावधान समाहित करने के निर्देश प्रदान किए थे। इसकी अनुपालना में राजस्थान सिनेमा (विनियमन)

अधिनियम - 1952 को संशोधित करते हुए राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक - 2023 विधेयक लाया गया है।

## राजस्थान राज्य अवंति बाई लोधी बोर्ड का गठन

राज्य सरकार प्रदेश में पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में लोधी (लोधा) समाज की स्थिति का सर्वेक्षण करने, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव देने के लिए राजस्थान राज्य अवंति बाई लोधी बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 गैर सरकारी सदस्य होंगे। साथ ही, उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आयुक्त/निदेशक/शासन सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक स्तर के अधिकारी बोर्ड में सचिव का कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अथवा उनका प्रतिनिधि बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बोर्ड के लिए प्रशासनिक विभाग होगा। इस बोर्ड के गठन का उद्देश्य लोधी (लोधा) समाज के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करना, वर्तमान में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विभिन्न विभागों से समन्वय कर सुझाव देना, समाज के शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन तथा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देना है। यह बोर्ड समाज के परंपरागत व्यवसायों को नवीन तकनीक से लाभदायक स्थिति में लाने के सुझाव भी देगा।

## राजकीय महाविद्यालयों में मिलेगी कैम्पस प्लेसमेंट सुविधा

प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोट ने इस योजना हेतु 9.18 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही, राजकीय महाविद्यालयों में कैम्पस प्लेसमेंट सुविधा योजना की क्रियान्विति हेतु दिशा-निर्देशों के प्रारूप का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार, प्रथम चरण में 100 राजकीय महाविद्यालयों में कैम्पस प्लेसमेंट योजना प्रारंभ की जाएगी जिसके तहत महाविद्यालयों में कम से कम वर्ष में दो बार कैम्पस प्लेसमेंट आयोजित किए जाएंगे। कैम्पस प्लेसमेंट से पूर्व विद्यार्थियों को प्री प्लेसमेंट के माध्यम से सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ ही उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सुगमता होगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न विशेषज्ञ संस्थानों जैसे भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आईआईआरएस), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एनसीएल) पुणे, राष्ट्रीय जैव विज्ञान केंद्र बेंगलूर एवं सेबी के साथ समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों का कौशल संवर्द्धन किया जाएगा।



## बीकाजी सोलंकी, संत ईशरदास एवं रामस्नेही संप्रदाय के संतों का बनेगा पैनोरमा

प्रदेश में बीकाजी सोलंकी, संत ईशरदास एवं रामस्नेही सम्प्रदाय के संतों के पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पैनोरमा के लिए 10 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। ये पैनोरमा भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होंगे। श्री गहलोत की स्वीकृति से पाली के देसूरी में बीकाजी सोलंकी एवं बाड़मेर के जालीपा में ईशरदास का पैनोरमा बनेगा। इनमें 3-3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही, भीलवाड़ा के शाहपुरा में 4 करोड़ रुपए की लागत से रामस्नेही संप्रदाय के संतों के पैनोरमा का निर्माण भी होगा। इनके निर्माण कार्य पर्यटन विकास कोष से कराए जाएंगे।

## राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का हुआ गठन

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड जोगी, योगी, नाथ जाति वर्ग की समस्याओं को चिन्हित कर प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बोर्ड गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड द्वारा समाज के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करने, वर्तमान में संचालित योजनाओं के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय करने, रोजगार को बढ़ावा देने, समाज के शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन, समाज के परम्परागत व्यवसाय को वर्तमान तौर-तरीकों से आगे बढ़ाने के संबंध में सुझाव दिए जाएंगे। बोर्ड द्वारा समाज की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर तथा मठों के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार, समाज से संबंधित लेख, ग्रंथ, साहित्य आदि पर शोध, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने सहित अन्य सुझाव भी राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे। बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्य (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य) होंगे।

## जयपुर और झुंझुनू के खेतड़ी हाउस विरासतों का होगा संरक्षण

राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ प्राचीन विरासतों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर और झुंझुनू स्थित खेतड़ी के प्राचीन भवनों में विकास कार्यों के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत की स्वीकृति से जयपुर के खेतड़ी हाउस और झुंझुनू के मोती महल और अमरहॉल (खेतड़ी) में जीर्णोद्धार के कार्य होंगे। इनमें 2.05 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह राशि पर्यटन विकास कोष से स्वीकृत की गई है।



## राज्य सरकार का वेबमाईवे सॉफ्टवेयर इस वर्ष के टेक्नोलॉजी सभा अवॉर्ड्स के लिए चयनित

राज्य सरकार के वेबमाईवे टूल को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवॉर्ड्स-2023 के लिए चयनित किया गया है। वेबमाईवे को यह पुरस्कार एन्टरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी में दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी सभा अवॉर्ड्स द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार के लिए सरकारी विभागों, एजेंसियों अथवा संस्थानों को दिया जाता है। वेबमाईवे (WabMyWay) फ्रेमवर्क राजकीय क्षेत्र में अपनी तरह का पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, जिससे किसी भी विभाग की डायनेमिक वेबसाइट बहुत कम समय में बनाई जा रही है। इसके माध्यम से विभाग की आवश्यकतानुसार मेन्यू, सबमेन्यू, डायनेमिक फॉर्म एवं वेबपेज बनाए जा सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर से निर्मित सभी वेबसाइट समरूप होती हैं एवं इसमें सूचनाओं का इंद्राज केवल एक बार किया जाता है एवं उसी सूचना को अलग-अलग पोर्टल पर आवश्यकतानुसार प्रदर्शित किया जा सकता है।

वर्तमान में कुल 7 तरह की वेबसाइट इस टूल से बनाई जा रही हैं, जैसे: जिलों की वेबसाइट, विभागीय वेबसाइट, सेक्टर पोर्टल, व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं के लिए पोर्टल, जनकल्याण पोर्टल, सर्विस पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन आदि। विभागों की वेबसाइट बनाने में होने वाले बड़े खर्च एवं समय को वेबमाईवे की मदद से आसानी से बहुत कम किया जा सकता है।

WabMyWay सॉफ्टवेयर को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 20 अगस्त, 2022 को लॉन्च किया गया था। वर्तमान में सभी 50 जिलों की वेबसाइट के अलावा कृषि, ऊर्जा, उद्योग, जल, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, चिकित्सा, आयोजना, कौशल, महिला एवं बाल विकास सेक्टर से संबंधित सभी पोर्टल डीआईपीआर पोर्टल, चिरंजीवी पोर्टल, महंगाई राहत कैंप पोर्टल, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना पोर्टल सहित लगभग 800 पोर्टल वेबमाईवे से बनाए गए हैं। स्वयं वेबमाईवे फ्रेमवर्क की वेबसाइट [webmyway.rajasthan.gov.in](http://webmyway.rajasthan.gov.in) का निर्माण भी इसी टूल द्वारा किया गया है।



## स्टाम्प ड्यूटी व अन्य शुल्कों के लिए राज-स्टाम्प सुविधा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दस्तावेजों पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी व अन्य शुल्कों के भुगतान के लिए ऑनलाइन 'राज-स्टाम्प' सुविधा शुरू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

## राजस्थान में संचालित प्रसव वॉच एप्लीकेशन को मिला नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवॉर्ड

नई दिल्ली में आयोजित नेशनल हेल्थ टेक इनोवेशन कॉन्क्लेव में राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के प्रसव वॉच एप्लीकेशन को चिकित्सा के क्षेत्र में अभिनव इनोवेशन के लिए नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवॉर्ड से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मातृ स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा राज्य की प्रमुख उच्च प्रसवभार वाले 360 मेडिकल इंस्टीट्यूट पर करवाए जा रहे संस्थागत प्रसवों की डिजिटलाइज्ड क्लिनिकल केयर और मॉनिटरिंग के लिए प्रसव वॉच एप्लीकेशन संचालित किया जा रहा है जिसके माध्यम से इन चिकित्सा संस्थानों पर हो रहे प्रसवों के लिए की गई क्लिनिकल केयर एवं प्रॉसिजर्स की ड्यूटी स्टाफ/डॉक्टर द्वारा रियल टाइम डेटा एन्ट्री प्रसव कक्ष एवं पीएनसी वार्ड में उपलब्ध करवाए गए टेबलेट पर की जाती है। इस एप्लीकेशन पर क्लिनिकल डेटा फीड करते समय ही सजेस्टिव मैसेज भी अलर्ट के रूप में संबंधित स्टाफ को रियल टाइम प्रदर्शित होते हैं जिसमें यह सम्मिलित होता है कि किस तरह की जटिलता होने की संभावना है एवं उसका निदान करने के लिए क्या संभावित कदम उठाये जाने हैं।

## खेल प्रशिक्षक के 100 नवीन पदों का होगा सृजन

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बच्चों एवं युवाओं को उच्चस्तरीय खेल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर खेल प्रशिक्षक ग्रेड-तृतीय के 100 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। प्रस्तावित पद मेजर ध्यानचंद योजना के तहत सभी ब्लॉक स्तर पर बनाए जा रहे स्टेडियम के लिए सृजित किए जाएंगे। श्री गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त होगा तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर खिलाड़ी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।

## नाथद्वारा में खुलेगा आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय

राजसमंद जिले के नाथद्वारा में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय खोला जाएगा। इस हेतु मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

ने 38.60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही, महाविद्यालय तथा चिकित्सालय के संचालन के लिए 125 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार, राजसमंद के नाथद्वारा में आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी महाविद्यालय एवं संबद्ध एकीकृत चिकित्सालय खोला जाएगा जिसके निर्माण हेतु 38.60 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इस महाविद्यालय के संचालन हेतु 125 नवीन पदों का सृजन किया।

## 15 जिलों के 2,588 गांव अभावग्रस्त घोषित

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान का भुगतान करने के लिए 15 जिलों के 2,588 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है।

ओलावृष्टि से रबी की फसलों में हुए नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए थे, जिसमें विभिन्न जिलों में 33 प्रतिशत से अधिक खराब होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसमें अजमेर का 1, अलवर के 42, बारां के 4, बाड़मेर के 1310, बीकानेर के 136, बूंदी के 6, भरतपुर के 393, धौलपुर के 29, श्रीगंगानगर के 6, हनुमानगढ़ के 56, जालोर के 292, झालावाड़ के 96, कोटा के 9, नागौर के 98 तथा उदयपुर के 110 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। इस आधार पर मुख्यमंत्री ने इन किसानों के हित में संवेदनशील निर्णय करते हुए एसडीआरफ मानदंडों के अनुसार उन्हें कृषि आदान एवं अनुदान दिए जाने की स्वीकृति दी है।

## वंशावली संरक्षण एवं संवर्द्धन अकादमी का नाम अब वंश लेखक अकादमी

राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर वंशावली संरक्षण एवं संवर्द्धन अकादमी का नाम परिवर्तित कर वंश लेखक अकादमी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि 24 अगस्त, 2017 को वंशावली संरक्षण एवं संवर्द्धन अकादमी का गठन किया गया था।

## बाघिन टी-111 के तीन शावकों को दिए गए चिरंजीवी, चिरायु एवं अवनी नाम

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस (29 जुलाई) के अवसर पर रणथंभौर नेशनल पार्क की बाघिन टी-111 के 2 वर्ष के हो चुके तीन शावकों (2 बाघ एवं 1 बाघिन) का नामकरण करने का फैसला लिया है। इनके नाम क्रमशः चिरंजीवी, चिरायु एवं अवनी रखे गए हैं। वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता श्रीमती कृष्णा पूनिया के नाम पर बाघिन टी-19 का नामकरण कृष्णा किया गया था। इसी प्रकार अब पैरा ओलंपिक पदक विजेता सुश्री अवनी लेखरा के नाम पर शावक का नाम अवनी रखने का निर्णय लिया गया है। •





## Initiatives Setting Roadmap for Tribal Development in RAJASTHAN

**Deepak Chakravarty**  
Assistant Public Relation Officer

**R**ajasthan is well known for its rich heritage and diverse vibrant culture. It is also a home for various tribal communities. Some of the prominent tribes residing in the state include Bhil, Meena, Sahariya, Garasia, Kathodi, Dhanka, etc. The State Government has been sensitive towards tribal welfare and its development. Chief Minister Shri Ashok Gehlot is putting every step forward to ensure all-round development and upliftment of tribal communities residing in Rajasthan.

In endeavour to bring tribal communities of the state into the mainstream, the Chief Minister allocated the fund amounting to Rs. 1,000 crore exclusively for tribal Development in budget 2023-24. Out of which Rs. 900 crore have already been disbursed by the finance department towards the execution of various tribal welfare initiatives. The initiatives of the Rajasthan Government for the advancement of various schemes administered in the domain of education, health, irrigation, and employment in tribal areas are strengthening the social and economic condition of the tribal community and setting a roadmap for tribal development and their upliftment.

The construction, and expansion of basic facilities like Anganwadi centers, clean drinking water facilities, roads, electrification, drainages, community waste and sewage management facilities, culverts, schools, colleges, hostels, medical centers, etc. are pacing up their social, economic and educational advancement.

### Housing Land Allotment

Land allotment to 10,981 BPL tribal families deprived of basic amenities including proper housing is a

milestone step in the sustainable housing programme implemented for them by the State Government.

### Nourishing the Basic Physical Needs

The distribution of free 500 grams of food grains, 500 ml of edible oil, and 250 ml of pure ghee per head every month to more than 1.3 lacks tribal population from Sahariya, Khairwa, and Kathodi community is another notable step in fulfilling the basic physical needs of underprivileged tribes to lead a healthy life.

### Scheduled Tribes Post Matric Scholarship

In order to ensure the progress of tribal students the funds amounting to Rs.1,297 crores were disbursed under Scheduled Tribes Post Matric Scholarship Scheme. Setting up newly constructed 12 hostels and 14 residential schools is seen as a landmark achievement of this government in the domain of tribal well being.

### Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Yojana Scheme

These tribes are being benefitting free of cost from Rajasthan Government's Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Yojana ensuring free and easy access to advance healthcare facilities with enhanced medical cover of Rs. 25 lakhs to them.

### Two Hundred Days Essential Employment under MNREGA

The augmentation of 200 days of employment from the earlier 100 days under MNREGA is ensuring sustainable livelihood among the most backward tribes like Sahariya, Khairua, and Kathodi.

### Special Courts

The State Government established six special courts with a view to providing timely delivery of justice to the People of tribal communities. •



# आदिवासियों के समेकित विकास की पहल

**आ**दिवासियों  
को भारत भूमि

का मूलनिवासी माना जाता है।

राजस्थान में भी आदिवासी बहुतायत में हैं।

दक्षिणी राजस्थान के वागड़, मेवाड़ में भील जनजाति,

सिरोही क्षेत्र में गरासिया, बारां क्षेत्र में सहरिया व सवाईमाधोपुर,

करौली क्षेत्र में मीणा जनजाति निवासरत है। राजस्थान सरकार प्रदेश में

निवासरत आदिवासियों के समेकित विकास के लिए कृत-संकल्प है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार ने जनजाति

क्षेत्रीय विकास विभाग गठित किया है, जिसके माध्यम से आदिवासियों के

शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन के लिए विविध योजनाएं संचालित

की जा रही हैं। हाल में विश्व आदिवासी दिवस पर बांसवाड़ा जिले के मानगढ़

धाम में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आजादी की लड़ाई

में आदिवासियों के बलिदान के साक्षी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में

विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की है।

साथ ही, क्षेत्र के बेणेश्वर धाम पर पुल सहित अन्य कार्यों के लिए 135 करोड़

रुपए की लागत से कार्य शुरू हो गए हैं। किसानों और आमजन के लिए बहु

उपयोगी 2 हजार 500 करोड़ रुपए की अपर हाईलेवल कैनाल का निर्माण

कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने मानगढ़ क्षेत्र स्थित भैरवजी मंदिर पर 37

करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण की भी घोषणा की। राज्य सरकार ने

टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत 2 हजार बाहरी शिक्षकों के तबादला आदेश भी जारी

कर दिए हैं, ताकि स्थानीय शिक्षकों को अवसर मिल सकें। मुख्यमंत्री ने

छात्रावासों की संख्या में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है।

## शैक्षिक सुविधाओं में विस्तार

राजस्थान सरकार ने जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाओं में

तेजी से विस्तार किया है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से कुल

427 आश्रम छात्रावासों एवं 53 आवासीय विद्यालयों/ईएमआरएस का

संचालन किया जा रहा है। इन छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में वर्तमान में



**डॉ. कमलेश शर्मा**  
संयुक्त निदेशक, जनसंपर्क

जनजाति वर्ग के 40 हजार से अधिक विद्यार्थियों को निशुल्क आवास, भोजन व कोचिंग आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वहीं हाल में राज्य सरकार ने इन छात्रावासों व आवासीय विद्यालयों की क्षमता दोगुनी करने की घोषणा भी की है। इससे जनजाति वर्ग के बच्चों को लाभ मिल सकेगा। सरकार ने गत 4 वर्षों में लगभग 4 लाख 37 हजार जनजाति छात्र/छात्राओं को विभिन्न विभागीय शैक्षिक प्रोत्साहन योजनाओं में लाभान्वित किया गया है। वहीं गत 4 वर्षों में 12 नवीन आश्रम छात्रावास तथा 14 नवीन आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए हैं। वर्ष 2023-24 में 16 अन्य स्थानों पर आश्रम छात्रावास तथा 7 स्थानों पर आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। अनुसूचित क्षेत्र में 550 छात्र क्षमता के 10 कॉलेज छात्रावासों का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 8 बहुउद्देशीय छात्रावासों (878 बालिकाओं की क्षमता) का संचालन किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के छात्रावासों हेतु पृथक से विभागीय कैडर बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है तथा भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 8 लाख रुपये निर्धारित की गई है। सहरिया क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को यूनिफॉर्म आदि क्रय करने हेतु राशि बढ़ाकर कक्षा 1 से 5 तक 1,000 रुपए एवं कक्षा 6 से 12 तक 2,500 रुपए की गई। जनजाति छात्र/छात्राओं को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी



परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत यूपीएससी, आरपीएससी एवं राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की कोचिंग कराई जा रही है। इसी योजना में उदयपुर में 200 जनजाति छात्राओं को नीट की आवासीय कोचिंग प्रदान की जा रही है। जनजाति समुदाय के 79 अभ्यर्थियों को पीएचडी हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की गई। वर्ष 2021-22 में अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कराई गई। रीट कोचिंग का कार्य उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जिला मुख्यालय पर करवाया गया है। इस योजनान्तर्गत 348 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। जनजाति प्रतिभा सम्मान योजना तहत प्रतिभावान अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रतिभाशाली तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित विद्यार्थियों को गत चार वर्षों में कुल 533 विद्यार्थियों को नकद प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया गया।

### आदिवासी बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास

शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं ई-कंटेंटलर्निंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा 140 जनजाति आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित कर लगभग 20 हजार विद्यार्थियों को रियल टाइम लॉगिन, रिकॉर्डेड लेक्चर, एनिमेटेड वीडियो आदि के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा, ई-लाइब्रेरी एवं ई-लर्निंग हेतु 358 आश्रम छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों एवं खेल छात्रावासों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। विभाग द्वारा संचालित समस्त जनजाति छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों, खेल छात्रावासों एवं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु एचएसएमएस पोर्टल लागू किया गया है। एजु ट्राइब एप के माध्यम से सतत मूल्यांकन प्रक्रिया लागू कर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ओएमआर शीट स्कैन कर त्वरित परिणामों से अवगत कराया जा रहा है। विभागीय आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में आधुनिकीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं के विभिन्न कार्य करवाए जाने हेतु वर्ष 2023-24 में बजट घोषणा की गई। घोषणा अनुसार 482 छात्रावासों के आधारभूत सुविधाओं के कार्य हेतु 33 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भिजवाए गए। कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक अनुसूचित जनजाति के 3,096 बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है एवं 1,031 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है।

### कला एवं संस्कृति के संरक्षण-संवर्द्धन की कवायद

राज्य सरकार जनजातीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए भी सतत प्रयासरत है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से सितंबर 2022 में कोटडा एवं उदयपुर में तीन दिवसीय आदि महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों के लगभग 400 कलाकारों ने प्रस्तुतियां दीं। इस महोत्सव में 7 राज्यों से आए हुए 150



कलाकारों ने प्रस्तुतियां दीं। इस महोत्सव को मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने पर्यटन विभाग के वार्षिक कैलेंडर में शामिल करने की सहमति दे दी है। अब प्रति वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आदि महोत्सव मनाया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव भी उदयपुर में प्रस्तावित किया गया है। वहीं मई, 2022 में भुवनेश्वर ओडिशा में हुए नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल में टीएडी विभाग के माध्यम से प्रतापगढ़ जिले के 17 सदस्यीय जनजाति सांस्कृतिक दल ने प्रस्तुतियां देकर राजस्थान की छाप छोड़ी। सितंबर, 2022 में भील जनजाति के प्रमुख नृत्य गवरी को देशी विदेशी पर्यटकों से परिचित कराने के उद्देश्य से उदयपुर शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर गवरी नृत्य नाटिकाओं की प्रस्तुतियां करवाई गईं।

### मां-बाड़ी केंद्रों से दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की ज्योत

राज्य सरकार आदिवासी अंचल में शैक्षिक उन्नयन के लिए सतत प्रयत्नशील है। दूरस्थ क्षेत्रों में जहां विद्यालय नहीं हैं, वहां मां बाड़ी केंद्रों के माध्यम से शिक्षा की ज्योत जल रही है। अनुसूचित क्षेत्र, माड़ा क्षेत्र तथा सहरिया क्षेत्र के लगभग 85,000 बालक/बालिकाओं को 2,834 मां-बाड़ी केंद्रों में कक्षा पहली से चौथी तक की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है तथा 375 भवन रहित मां-बाड़ी केंद्रों के भवनों का निर्माण कराया गया। वर्ष 2023-24 में भी मुख्यमंत्री द्वारा नवीन 250 नवीन मां-बाड़ी केंद्र प्रारंभ करने की बजट घोषणा की गई है, जिसमें से 167 प्रारंभ कर दी गई है।

### सौगातों से सुधर रहा जीवन स्तर

राज्य सरकार आदिवासी समाज के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के लिए लगातार काम कर रही है। जोधपुर मुख्यालय पर 30 करोड़ रुपए की लागत से 480 विद्यार्थी क्षमता का आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन



है। जोधपुर मुख्यालय पर ही 12 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से 50 विद्यार्थी क्षमता का जनजाति कन्या छात्रावास एवं 50 की क्षमता का ही जनजाति कन्या बहु-उद्देश्यीय छात्रावास तथा जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ) के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 107.11 करोड़ रुपए की लागत से 18 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एवं 4 राज्य आवासीय विद्यालयों में लगभग 3 हजार छात्र-छात्राओं की क्षमता वृद्धि कर उच्च गुणवत्ता के शैक्षणिक अवसरों को उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2023-24 में 7 नवीन जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं 16 नवीन जनजाति छात्रावासों का निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है, जिस पर लगभग 150 करोड़ रुपए व्यय होंगे। 69.69 करोड़ रुपए की लागत से जनजाति वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को उच्च श्रेणी के छात्रावास उपलब्ध कराने हेतु 15 जर्जर जनजाति छात्रावासों का पुनर्निर्माण एवं 24 नवीन आश्रम छात्रावास निर्मित करवाए जा रहे हैं। इससे लगभग 2,500 बालक/बालिकाओं को उच्च गुणवत्ता के रहवास की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। करौली जिले में 3.50 करोड़ रुपए की लागत से 100 की क्षमता का कॉलेज छात्रावास निर्मित किया गया है। 15.06 करोड़ रुपए की लागत से 300 की क्षमता के 3 बहुउद्देश्यीय छात्रावास एवं 6.92 करोड़ रुपए की लागत से 100 छात्राओं की क्षमता के 2 खेल छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। 27.98 करोड़ रुपए की लागत से 232 छात्रावासों में सुविधा बढ़ाने हेतु सोलर पनघट एवं आरसीसी टैंक के निर्माण कार्य करवाए गए। 17.76 करोड़ रुपए की लागत से उदयपुर जिला मुख्यालय पर जनजाति बालिका हेतु 168 छात्रा क्षमता का सेंटर फॉर एक्सीलेंस छात्रावास लगभग पूर्णता पर है। वर्तमान शिक्षण संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु 26.86 करोड़ रुपए की लागत से 132 राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है।

### पेयजल और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

जनजाति वर्ग के आबादी क्षेत्र में पेयजल सुविधा हेतु 11.68 करोड़ रुपए की लागत से हैंडपंप, सोलर पनघट, विद्युत पनघट, पंप और टैंक आदि के 639 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। 82.68 करोड़ रुपए की लागत से नवीन एवं पुनरुद्धार सोलर ऊर्जा आधारित सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना के 159 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है। इससे लगभग एरिया 5,893.87 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी एवं 8,308 कृषक लाभान्वित होंगे। इसके अलावा वर्ष 2023-24 हेतु भी सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं से 85 हजार किसानों को लाभान्वित करने की घोषणा की गई है। 76.48 करोड़ रुपए की लागत से एनिकट निर्माण एवं नहर सुदृढीकरण के 93 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इससे वर्तमान में इस क्षेत्र के सिंचित रकबे में लगभग 3 हजार हेक्टेयर की वृद्धि होगी। जनजाति क्षेत्रों की आबादियों को सुगम आवागमन हेतु 89.96 करोड़ रुपए की लागत से सर्वरुतु संपर्क सड़क, ग्रेवल सड़क, सीसी सड़क, इंटरलॉकिंग कार्य, रिटेनिंग वॉल आदि के 504 कार्य स्वीकृत किए गए।

### सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण

राज्य सरकार जनजाति क्षेत्र में सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए भी संकल्पित है। इसके लिए विभिन्न प्रकल्प किए जा रहे हैं। 0.97 करोड़ रुपए की लागत से घोटिया अंबा एवं समाई माता विकास कार्य, 4.93 करोड़ रुपए की लागत से वागड़ सांस्कृतिक केंद्र, 2 करोड़ रुपए की लागत से लीलूड़ी बड़ली शहीद स्मारक, 0.87 करोड़ रुपए की लागत से बेणेश्वर धाम की बाउण्ड्रीवॉल कार्य एवं 1.46 करोड़ रुपए की लागत से राणा पूजा स्मारक में संपर्क सड़क के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। राज्य के विशेष रूप से कमजोर (सहरिया) समूह के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परंपराओं एवं वेशभूषा को संरक्षित करने एवं आमजन को इन परंपराओं को अवगत कराने के लिए जिला बारां मुख्यालय पर एक सहरिया संग्रहालय निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, 2021 के अवसर पर अपनी महत्वाकांक्षी योजना "जनजाति भागीदारी योजना" प्रारंभ की गई। योजना के तहत अब तक 41.41 करोड़ रुपए की लागत से 347 कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इसके अलावा 34.70 करोड़ रुपए की लागत के 381 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

### खेलों को बढ़ावा

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में 13 खेल अकादमियों का संचालन कर वर्तमान में 900 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर नवीन मल्टीपरपज इंडोर खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण कर स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए प्रारंभ कर दिया गया है। जनजाति छात्र/छात्राओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी प्रशिक्षण हेतु उदयपुर में हॉकी अकादमी प्रारंभ कर अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक द्वारा 40 बालक एवं 30 बालिकाओं को कुल 70 जनजाति छात्र/छात्राओं को एस्ट्रो टर्फ खेल मैदान, खेलगांव पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ईएमआरएस खेलकूद प्रतियोगिता में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्रा राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुए। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित 115 छात्र-छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता, हैदराबाद में भाग लिया। इसमें 14 छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय स्तर की ईएमआरएस खेलकूद प्रतियोगिता 2022-23 आंध्र प्रदेश में आयोजित हुई जिसमें राज्य के 118 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें 14 छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्थान प्राप्त किया एवं 14 एवं 19 वर्ष से कम छात्र वर्ग तीरंदाजी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। राष्ट्रीय साहित्य एवं सांस्कृतिक ईएमआरएस प्रतियोगिता 2022-23 बेंगलुरु में आयोजित हुई जिसमें राज्य के 62 प्रतिभागियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर पर कुल 4 पुरस्कार प्राप्त हुए। जून-जुलाई 2023 उदयपुर में जनजाति खेल प्रतिभाओं को 40 दिवसीय उच्च स्तरीय आवासीय खेल प्रशिक्षण आयोजित किया गया।



## 50 हजार से अधिक वनाधिकार दावों का निस्तारण

आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे जारी करने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने वनाधिकार अधिनियम पारित किया था। इसी के तहत राज्य सरकार ने वनाधिकार दावों के निस्तारण में पूर्ण संवेदनशीलता दिखाई। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत 48 हजार 524 व्यक्तिगत वनाधिकार दावे एवं 2 हजार 259 सामुदायिक वनाधिकार दावे स्वीकृत कर वन अधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं। वनाधिकार अधिनियमों के अंतर्गत सामुदायिक वनाधिकार पट्टों के विकास कार्य हेतु नवीन सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना लागू की गई है। जनजाति क्षेत्रों में अधिकाधिक सामुदायिक वन अधिकार पट्टे उपलब्ध कराने के लिए 1 मार्च से 30 जून, 2023 तक विशेष अभियान चलाया गया। वर्ष 2023-24 में वनाधिकार तथा पेसा अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को सशक्त करने की घोषणा की गई है।

## कृषि एवं पशुपालन में भी राहत

जनजातीय कृषकों को वर्ष 2020-21 में 5 लाख 90 हजार व वर्ष 2022-23 में 7 लाख 97 हजार (कुल 13.87 लाख) निःशुल्क संकर मक्का बीज मिनिफिट वितरित किए गए। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट बी के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 750 व वर्ष 2021-22 में 1 हजार 303 कुल 2 हजार 53 सोलर पंप जनजातीय कृषकों को अतिरिक्त अनुदान के साथ उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2022-23 के दौरान जनजातीय कृषकों को कुल 44 हजार 975 निःशुल्क हाइब्रिड सब्जी बीज मिनिफिट प्रदर्शन का वितरण किया गया। इसमें रबी एवं जायद 2022-23 के लिए अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में उच्च गुणवत्ता के संकर सब्जी बीज उपलब्ध कराए गए। 8 हजार 444 वनाधिकार

पट्टा लाभार्थियों को विभिन्न पशुपालन विभाग की गतिविधियों में लाभान्वित किया गया। जनजातीय पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए पशुपालन विभाग के माध्यम से पशुओं हेतु सॉर्टेड सीमन की व्यवस्था की गई है, जिससे लगभग 9,000 पशु पालक परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020-21 में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से जुड़े हुए जनजाति समुदाय के 5,986 दुग्ध उत्पादकों को पशु आहार उपलब्ध कराते हुए लाभान्वित किया गया। राज्य के 49 हजार जनजाति परिवारों को संगृहीत लघु वन उपजों का वैल्यू एडिशन कर मार्केटिंग के बेहतर अवसर सृजित करने के उद्देश्य से 162 वनधन केंद्रों का गठन किया गया है।

## जनजाति विकास कोष

राज्य सरकार ने जनजाति अंचल के समुचित विकास के लिए वर्ष 2021-22 में जनजाति विकास कोष प्रारंभ किया है। वर्ष 2023-24 में कोष की राशि को 500 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। वर्ष 2022-23 के कुल बजट प्रावधान में राशि 1218.10 करोड़ रुपए का संशोधित प्रावधान कर 1177.17 करोड़ (96.82 प्रतिशत) रुपय व्यय किए गए। वर्ष 2023-24 में 1033.14 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। जनजाति उपयोजना प्रवाह के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 24 हजार 030.74 करोड़ रुपए का संशोधित प्रावधान किया जाकर इसके विरुद्ध 21,039.80 करोड़ रुपए (87.55 प्रतिशत) व्यय किए गए। वर्ष 2023-24 में 26 हजार 931.73 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021-22 में राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि विधेयक 2022 पारित कर इसके तहत सशक्त समितियों एवं राज्य अनुसूचित जनजाति विकास परिषद का गठन किया गया। •



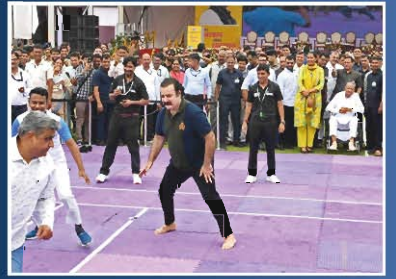


# खेलेगा राजस्थान जीतेगा राजस्थान

## देश के सबसे बड़े एवं निराले खेल महाकुंभ का आगाज

**भा**रत में प्राचीन समय से ही कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं। कबड्डी और खो-खो जैसे खेलों का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। चतुरंगा एक प्राचीन बोर्ड गेम था, जिसमें विभिन्न संशोधन हुए क्योंकि यह भारत से यूरोप की ओर प्रसारित हुआ और आधुनिक शतरंज का खेल बन गया। पारंपरिक भारतीय खेल विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते थे और इनका भारतीय इतिहास से घनिष्ठ संबंध था। ब्रिटिश राज के समय, भारतीयों ने अपने पारंपरिक खेलों के बजाय क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल जैसे ब्रिटिश खेलों को खेलने पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। एक उल्लेखनीय पारंपरिक भारतीय खेल पोलो था, जिसकी शुरुआत मणिपुर से मानी जाती है, जिसे अंग्रेजों ने एक आधिकारिक खेल के रूप में संहिताबद्ध करने और समर्थन देने में मदद की। स्वतंत्रता के बाद के भारत में, कबड्डी सबसे लोकप्रिय पारंपरिक खेल है, जिसमें सबसे अधिक दर्शक संख्या और सबसे अधिक कॅरियर के अवसर हैं। प्रो-कबड्डी लीग के निर्माण से इसके विकास को गति मिली है। राजस्थान में प्राचीनकाल से ही खेल-कूद की समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की वर्तमान खेल नीति श्रेष्ठतम है। खेल-कूदों में प्रदेश ने कई नवाचार किए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल भी उनमें से एक है।

**डॉ. गोरधन लाल शर्मा**  
राजस्थान प्रशासनिक सेवा



### राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023

देश का सबसे बड़ा खेल इवेंट राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 प्रदेश में 5 अगस्त से 18 सितंबर तक आयोजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 5 अगस्त को इन निराले खेलों का शुभारंभ किया गया। प्रदेश की सभी 11 हजार 252 ग्राम पंचायतों एवं 538 नगरीय निकाय समूहों में एक साथ राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल शुरू हुए। इन खेलों में रिकॉर्ड 58 लाख 51 हजार खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया है, जिनमें 24 लाख 46 हजार महिलाएं हैं। इन खेलों में विजेता खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

राजीव गांधी ग्रामीण-शहरी ओलंपिक-2023 का आगाज मशाल प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया। राजस्थान के इस खेल महाकुंभ का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जनता को यह संदेश दिया गया कि ये खेल सेहत अच्छी करने और खुशहाली बढ़ाने का अवसर हैं। हम सब प्रदेशवासी मिलकर प्रदेश के हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने वाले इस आयोजन में शामिल हों और एक उत्सव की तरह इन खेलों को सेलिब्रेट करें। राज्य के प्रत्येक जिले की ग्राम पंचायत और शहरी वार्डों में एक साथ हजारों खिलाड़ियों का मैदान में प्रतिभा दिखाना गौरवशाली पल है। सभी ने मिलकर देश के सामने एक खेल इतिहास रचा है। खेल प्रोत्साहन की दिशा में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल-





छाया : किशोर कुमार

## युवा और खेलों का विजन 2030

राजस्थान ने इस बार का बजट युवाओं को समर्पित किया था। इसमें युवा केंद्रित योजनाएं लागू की गईं। युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे योजनाओं का अध्ययन करें और अधिकाधिक लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में 500 होनहार विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा, 100 जॉब फेयर

2023 का आयोजन नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। यह खेल अब हर वर्ष आयोजित कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को खेल मशाल सौंपकर प्रज्वलित कराई। साथ ही, खिलाड़ियों को खेल भावना और ईमानदारी से खेलने की शपथ भी दिलाई। देश की इस सबसे बड़ी खेल शपथ का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया कि प्रतिभाओं को मंच और सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें कमी नहीं रखी जाएगी। देश में हर कोई हमारे खेल आयोजनों की चर्चा कर रहा है। हमारे खेल मॉडल और पिछले ग्रामीण ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन की चर्चा और सराहना इंपाल में आयोजित खेल मंत्रियों के सम्मेलन में भी की गई। कई राज्यों ने हमारे खेल मॉडल को अपनाया है।

राज्य सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी, नौकरियों में आरक्षण, पुरस्कार विजेता राशि में कई गुना बढ़ोतरी, खेल मैदानों के विकास सहित कई प्रयास किए गए हैं। अब देश के अन्य राज्यों में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल और राज्य की खेल नीतियों की चर्चा होना राजस्थान की खेल के प्रति दूर दृष्टि और सफलता को दर्शाता है।

का आयोजन सहित कई प्रावधान किए गए जा रहे हैं। राजस्थान में युवा और खेलों का विजन 2030 है। हम उस समय तक चहुंमुखी विकास के साथ देश के अग्रणी राज्यों में खड़े होंगे। इसके लिए युवाओं से आह्वान किया जाता है कि वे अपनी ऊर्जा को सही और सकारात्मक दिशा में लगाकर देश और प्रदेश को उन्नति की ओर अग्रसर करें।

## खेल और खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास

राज्य सरकार की खेल प्रोत्साहन सोच और कार्यक्रमों से प्रदेश में खेलों का इतिहास ही बदल गया है। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी और खेल कोटे के तहत करीब 1 हजार 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इससे युवाओं में खेलों के प्रति विश्वास बढ़ा है। खेल प्रोत्साहन का ही नतीजा है कि इस वर्ष खेलो इंडिया में राजस्थान चौथे स्थान पर रहा। राज्य सरकार द्वारा खेल और खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा रहा है, जो मैदान में खिलाड़ियों के उत्साह और उज्वल भविष्य को दर्शा रहा है।

## राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के विभिन्न स्तर

ग्राम पंचायत स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं नगर निकायों में 5 अगस्त, 2023 से 10 अगस्त, 2023 तक, ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं 17 अगस्त, 2023 से 22 अगस्त, 2023 तक, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं 1 सितंबर, 2023 से 6 सितंबर, 2023 तक एवं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं 15 सितंबर, 2023 से 18 सितंबर, 2023 तक आयोजित हो रही हैं। •

### ग्रामीण ओलंपिक की खेल स्पर्धाएं

राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक 2023 में कुल सात खेल स्पर्धाओं को शामिल किया गया है:

1. कबड्डी (बालक/बालिका वर्ग)
2. शूटिंग बॉल (बालक वर्ग)
3. टेनिस बॉल क्रिकेट (बालक/बालिका वर्ग)
4. खो-खो (बालिका वर्ग)
5. वॉलीबॉल (बालक/बालिका वर्ग)
6. फुटबॉल (बालक/बालिका वर्ग)
7. रस्साकशी (बालिका वर्ग)

### शहरी ओलंपिक की खेल स्पर्धाएं

1. कबड्डी (बालक/बालिका वर्ग)
2. टेनिस बॉल क्रिकेट (बालक/बालिका वर्ग)
3. खो-खो (बालिका वर्ग)
4. वॉलीबॉल (बालक/बालिका वर्ग)
5. एथलेटिक्स (100 मी., 200 मी. एवं 400 मी.)
6. फुटबॉल (बालक वर्ग)
7. बास्केटबॉल (बालक/बालिका वर्ग)





## सद्भावना दिवस

पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती

देश और युवाओं के लिए समर्पित रहे

# श्री राजीव गांधी

गोविंद चतुर्वेदी  
वरिष्ठ पत्रकार

**श्री** राजीव गांधी भारत के छोटे प्रधानमंत्री थे। वे वर्ष 1984 से 1989 तक इस पद पर रहे। प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, वे राजनीति में आना भी नहीं चाहते थे। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया गांधी भी नहीं चाहती थीं कि वे राजनीति में आएँ। प्रधानमंत्री निवास में रहते हुए भी दोनों, राजनीति से कोसों दूर रहकर सामान्य नागरिक जैसा जीवन जी रहे थे लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। समय ने न केवल श्री राजीव गांधी अपितु श्रीमती सोनिया गांधी को भी राजनीति में ला खड़ा किया। दोनों के राजनीति में आने की परिस्थितियाँ एक जैसी थीं। श्री राजीव गांधी को अपनी माता श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी को श्री राजीव गांधी की नृशंस हत्या के दुख भरे वातावरण की वजह से राजनीति में आना पड़ा। दोनों राजनीति में आए तो दोनों ने ही अपनी राजनीतिक, प्रशासनिक और मानवीय दूरदृष्टि तथा संवेदनशीलता एवं जनहितकारी नीतियों से राष्ट्रहित में शानदार प्रदर्शन किया। श्री राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने।

श्री राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ। श्री राजीव गांधी शांत और धीर-गंभीर स्वभाव के अंतर्मुखी व्यक्ति थे। देश-विदेश में अपनी पढ़ाई कर श्री राजीव ने इंडियन एयरलाइंस में कॉमर्शियल पायलट बनना पसंद किया। वर्ष 1980 की 23 जून को एक विमान हादसे में श्री संजय गांधी का निधन हो गया। शोक के इस माहौल में श्री राजीव गांधी पर अपनी माँ और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सहायता के लिए राजनीति में आने का दबाव बना। 1980 में अनिच्छा से वे राजनीति में आए। 1984 में वे देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के पद पर बैठते समय उनकी उम्र महज 40 वर्ष थी। इस उम्र में उनका प्रधानमंत्री बनना तब देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा का



विषय था। उनका व्यक्तित्व सम्मोहक और करिश्माई था। वर्ष 1984 के दिसंबर में हुए आम चुनावों में (लोकसभा की 541 में से 411) उनके नेतृत्व में जितना समर्थन मिला, वह उसके पहले और उसके बाद आज तक देश में किसी दल को नहीं मिला। श्री राजीव गांधी ने अपने काम और निर्णयों से इस जनादेश को सिद्ध भी किया। पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी परिपक्व राजनेता थे लेकिन श्री राजीव गांधी ने राजनीति में नये होते हुए भी क्रांतिकारी कार्य किये। उन्होंने अपनी प्रतिभा का बहुआयामी प्रदर्शन किया। एक भावुक, भले और विश्वासी इंसान के रूप में उन्होंने सब पर भरोसा किया।

### कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत

उनके प्रधानमंत्रित्व काल में हुए ऐतिहासिक कार्यों की सूची बहुत लंबी है लेकिन जो काम उन्होंने पीढ़ियों के लिए किया, वह था- देश में कंप्यूटर क्रांति का सपना और उसकी शुरुआत। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की बात करते हुए उन्होंने देश को इक्कीसवीं सदी में ले जाने की बात की। इस कंप्यूटर क्रांति ने तबसे अब तक देश में न केवल पुणे, बेंगलुरु जैसे दर्जनों तकनीकी शहर खड़े कर दिए बल्कि देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार भी दिया। आज अगर हम



भारत को विश्वगुरु बनाने की बातें कर रहे हैं तो उसमें श्री राजीव गांधी का बड़ा योगदान है।

### युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता

एक नौजवान प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के युवाओं को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। उनके लिए जो कर सकते थे, वह किया। यह श्री राजीव गांधी ही थे जिन्होंने युवाओं पर भरोसा कर उन्हें 18 वर्ष का होने पर मताधिकार देकर देश का भाग्य तय करने का गौरव दिया। श्री राजीव गांधी ही 1986 में नई शिक्षा नीति लेकर आए। ग्रामीण गरीबों के लिए, मुफ्त एवं स्तरीय शिक्षा देने के लिए जगह-जगह जवाहर नवोदय विद्यालय खोले।

### पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा

देश में लोकतंत्र की धुरी पंचायती राज की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी तो यह श्री राजीव गांधी ही थे जिन्होंने शहरी निकायों के साथ इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। हर पांच वर्ष में उनके चुनाव की संवैधानिक गारंटी दी।

### दूरसंचार क्रांति

आज जब हम सेकेंड्स में विश्व में कहीं भी बैठे अपने प्रियजन से बात कर लेते हैं तब शायद ही किसी को इस बात पर भरोसा हो कि 35 वर्ष पहले तक इसी भारत में, विदेशों की तो बात बहुत दूर की है, एक ही राज्य के दो शहरों में बात भी करने में कई-कई दिन लग जाते थे। वे श्री राजीव गांधी ही थे जिन्होंने पहले पीसीओ और फिर घर-घर फोन पहुंचाने वाली दूरसंचार क्रांति लाए।

### विदेश नीति

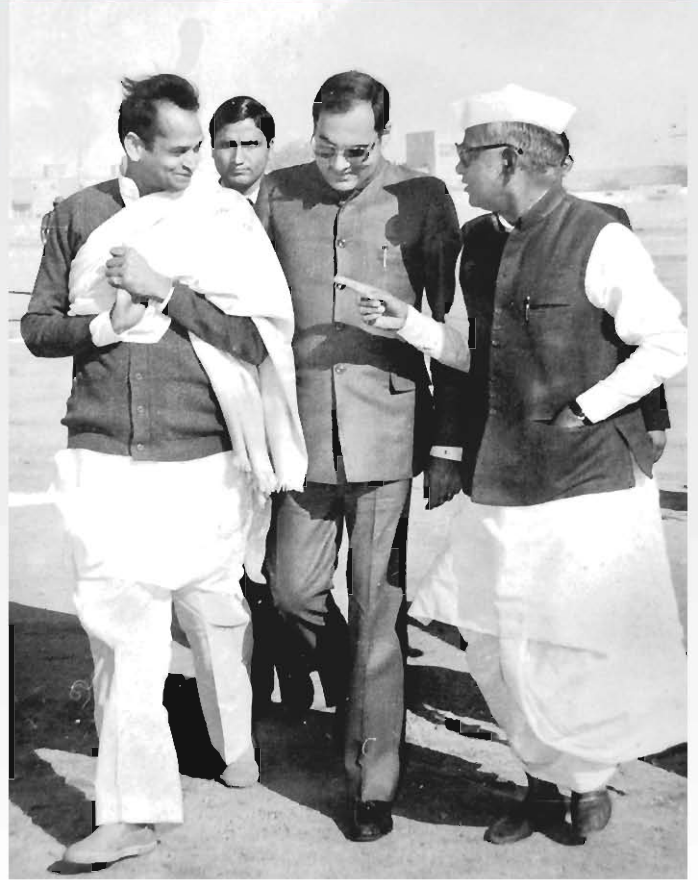
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने सेशेल्स और मालदीव जैसे देशों में भारतीय सैनिक भेजकर वहां लोकतांत्रिक सत्ताओं को बचाया। श्रीलंका से शांति समझौता किया और वहां भी शांति सेना भेजी। यह दुर्योग ही था कि श्रीलंका विवाद के चलते ही वर्ष 1991 में उन पर एक प्राणघातक हमला हुआ जिसमें उनकी जान चली गई।

### राष्ट्रहित सर्वोच्च

राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो उन्होंने पंजाब, असम और मिजोरम में शांति और सद्भाव की बहाली की। उन्होंने इन तीनों ही समझौतों में, दल हित के बजाय वहां शांति सद्भाव की बहाली के साथ राष्ट्रहित को सर्वोच्च रखा। समझौतों के बाद तीनों राज्यों में चुनाव कराए। सेना के आधुनिकीकरण की नींव भी उन्हीं के शासन में रखी गई। राजनीति में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जगह देना उनका सपना था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो पहला कानून बनाया वह दलबदल को रोकने का कानून ही था। देश में उपभोक्ता संरक्षण आयोग के गठन से लेकर आर्थिक उदारिकरण तक के कई नवाचारों को उन्होंने शुरू किया। अरुणाचल को राज्य का दर्जा दिया।

### राजस्थान से विशेष लगाव

पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी की तरह उनका भी



राजस्थान से विशेष लगाव था। शायद इसका एक कारण उनके परिवार का राजस्थान की खेतड़ी से गहरा रिश्ता रहना था। पंडित नेहरू ने यहीं नागौर से देश में पंचायती राज की अलख जगाई। श्री राजीव गांधी की भी संभवतः पहली राजनीतिक यात्रा फरवरी, 1982 में राजस्थान के बीकानेर जिले में हुए पंचायतीराज सम्मलेन से हुई। देश का प्रधानमंत्री बनने के पहले उन्होंने राज्य के भरतपुर, जोधपुर आदि अनेक जिलों की यात्रा कर ली थी।

राजस्थान से उनका गहरा लगाव वर्ष 1986-87 में पड़े सदी के भीषणतम अकाल के दौरान दिखा जब वे सांसद श्री अशोक गहलोत के साथ राज्य के अकालग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर आए। लगभग हर दूसरे साल पड़ने वाले अकाल का राजस्थानी जनता अपने जीवट से ही मुकाबला करती थी। श्री राजीव गांधी ने स्वयं जीप चलाकर श्री अशोक गहलोत के साथ राज्य के अकालग्रस्त 8 जिलों का दौरा किया और त्रिकाल यानी अनाज, चारा और पानी की कमी से पार पाने के लिए उस समय राज्य को 850 करोड़ रुपए की मदद भी दी। इससे पहले श्री अशोक गहलोत के आग्रह पर उन्होंने पश्चिमी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी बनी राजस्थान नहर (बाद में नामकरण इंदिरा गांधी नहर हुआ) से जोधपुर लिफ्ट योजना के सपने को भी मूर्त रूप देने की घोषणा की। इस योजना ने पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर ही बदल दी। वहां के अकाल को सुकाल में बदल दिया है। अब वहां पेयजल की कमी नहीं के बराबर है। श्री राजीव गांधी को देश, लोकतंत्र एवं युवाओं की मजबूती के लिए किये गये कार्यों के लिए सदैव याद रखेगा। •



# भाई-बहन का पर्व रक्षाबंधन

गीता यादव  
वरिष्ठ पत्रकार



भगवान को बांधी जाती है, जबकि चूड़ा राखी भाभियों की चूड़ियों में बांधी जाती है। जोधपुर में इस दिन केवल राखी ही नहीं बांधी जाती, बल्कि दोपहर के समय गोबर, मिट्टी के लेप से घर को साफ भी किया जाता है। विशेष सुगंधित सामग्री के साथ स्नान भी किया जाता है। इसके बाद गणेश, दुर्गा, अरुंधती और सप्त ऋषियों की विशेष पूजा की जाती है। पूजन के समय रेशमी डोरे की राखी बनाकर उसे कच्चे दूध में धोकर शुद्ध किया जाता है। फिर मंत्रोच्चारण के साथ उसे देवताओं की मूर्तियों को बांधा जाता है।

**र**क्षाबंधन भारत के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन शब्द का संस्कृत में अनुवाद 'सुरक्षा की गांठ' होता है। बहनें अपने भाई की कलाई पर रंगीन धागा बांधती हैं, माथे पर कुमकुम तिलक लगाती हैं, आरती करती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती हैं। उनके लंबे जीवन की प्रार्थना करती हैं। बदले में भाई-बहन को उपहार देता है। आजीवन रक्षा का वचन देता है। हालांकि इस त्योहार से जुड़ी रस्में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन उन सभी में धागा बांधना प्रमुखता से शामिल है। रक्षाबंधन की उत्पत्ति का पता प्राचीनकाल से लगाया जा सकता है। इस त्योहार का संदर्भ 326 ईसा पूर्व की किंवदंतियों में पाया जाता है। शास्त्रों में भी रक्षाबंधन के कई वृत्तांत हैं।

**यम और यमुना :** पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले राखी यमुना ने अपने भाई यम को बांधी थी, जो मृत्यु के राजा थे। इसलिए उन्हें अनंतकाल का आर्शीवाद मिला और तभी से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। कृष्ण और द्रौपदी की कथा के मुताबिक एक बार भगवान कृष्ण की अंगुली सुदर्शन चक्र से कट गई थी। तब द्रौपदी ने, अपनी साड़ी फाड़कर उस चीर को कृष्ण की अंगुली पर बांधा था। महाभारत में जब कौरवों ने उनके सम्मान को हानि पहुंचानी चाही, तब कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। ये कहानियां रक्षाबंधन से जुड़े समृद्ध सांस्कृतिक महत्व और विविध आख्यानों को उजागर करती हैं और जैविक संबंधों से परे मौजूद प्रेम और सुरक्षा के गहरे बंधन को प्रदर्शित करती हैं।

## राजस्थानी संस्कृति में रक्षाबंधन उत्सव

राजस्थान में राखी का त्योहार कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है। इस दिन यहां रामराखी, चूड़ाराखी और लुंबा बांधने की परंपरा है। रामराखी

## तरह—तरह की रस्में

**सून मांडना :** सून या शगुन मांडना रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने की वास्तविक रस्म से पहले होती है। सून प्रतीकों की शुभ तस्वीरें हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये हमें सभी बुरी ऊर्जाओं से बचाती हैं। यह परंपरा राजस्थान में किसी भी त्योहार, खासकर रक्षाबंधन से पहले की है। सूनियां या चित्र कई प्रकार के होते हैं।

**सून जिमाना :** इस रस्म के दौरान दीवारों पर उकेरे गए सून को रोली, चावल, लाल पवित्र धागा और पानी के साथ गुड़ या कोई मिठाई अर्पित की जाती है।

**राजस्थानी भोजन, संगीत और गीत :** राजस्थान में समृद्ध खाद्य संस्कृति है। रक्षाबंधन पर मूंग की दाल का हलवा, मालपुआ, चूरमा, लड्डू, बालूशाही, बादाम का हलवा, गुजिया, कलाकंद, मावा कचौरी, मोहन थाल, बेसन की बर्फी का आनंद लिया जाता है। राजस्थान में लोकगीतों की भी अनूठी संस्कृति है। इस दिन परिवार वाले मिलकर राजस्थानी भूमि के विशेष लोक-गीत गाते हैं।

**राज्य सरकार का महिलाओं को खास तोहफा :** राखी के त्योहार पर राजस्थान में महिलाओं और बालिकाओं को राजस्थान रोडवेज और जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की सभी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलती है। इस बार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रक्षाबंधन से पहले प्रदेश की महिलाओं को, एक और खास उपहार दिया है। इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहत, महिला मुखियाओं को स्मार्ट फोन वितरित किए जा रहे हैं। महिला लाभार्थियों को स्मार्ट फोन एवं सिम मय डेटा कनेक्टिविटी वितरण किया जा रहा है। लाभार्थी शिविरों में महिलाएं अपने पसंद के स्मार्ट फोन चुन रही हैं। •



# प्राचीनतम कालक्या माता मन्दिर (बिन्दायका देवी)

ग्राम - बिन्दायका तह सांगानेर, जिला - जयपुर

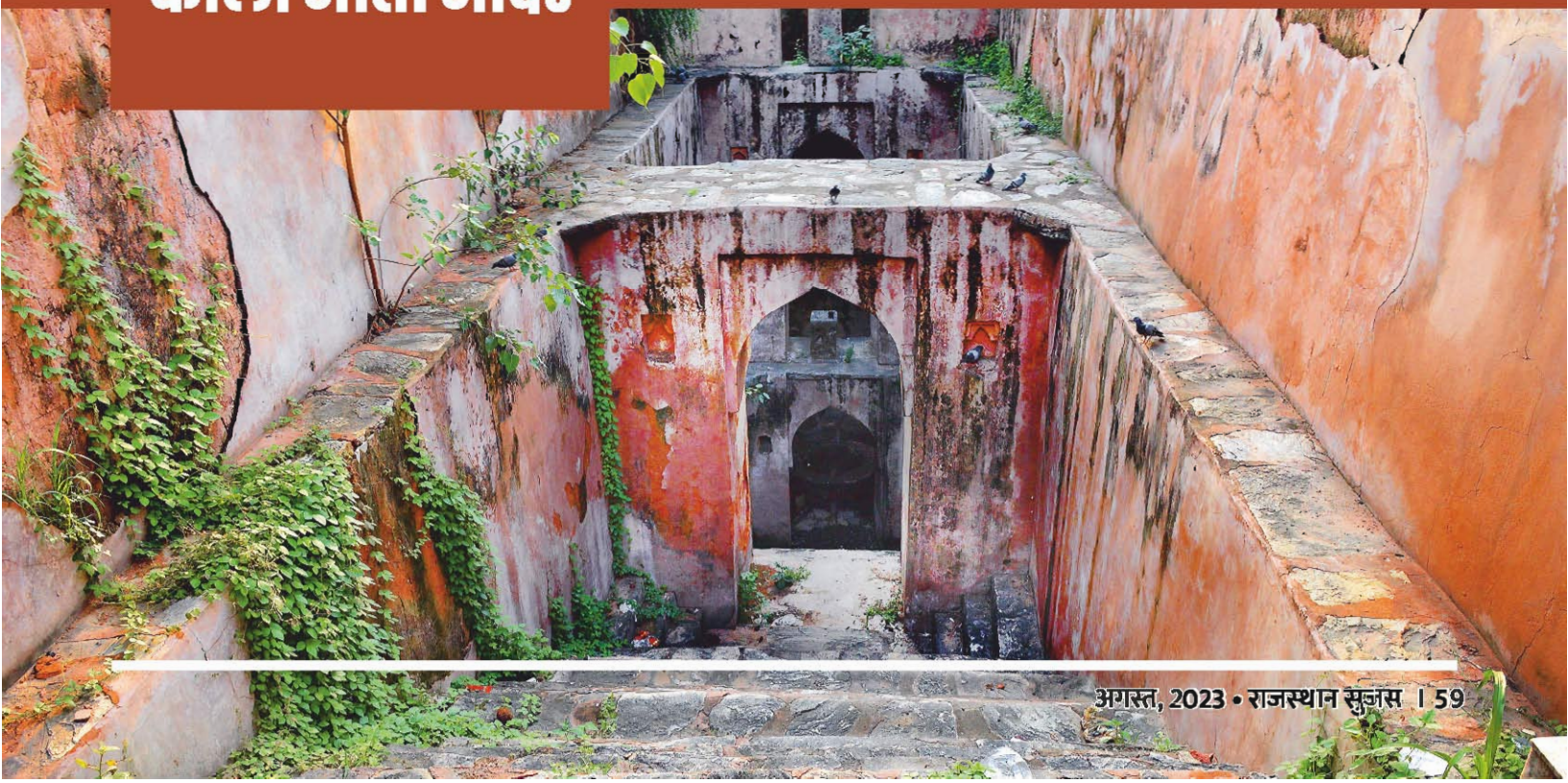
का माता  
का माता  
का माता  
का माता  
का माता



विभिन्न प्रकार की वनस्पति और वन्य जीवों के आवास जयपुर के झालाना जंगल में स्थित काली माता का मंदिर अरावली पर्वत शृंखलाओं से घिरा हुआ है। तकरीबन 1100 वर्ष पुराना यह मंदिर बिन्दायका गांव में था। इस मंदिर में मां काली व दुर्गा की दुर्लभ मूर्तियां हैं। मंदिर के पास ही 1100 वर्ष पुरानी ही एक बावड़ी भी है जो तत्कालीन बिन्दायका गांव को पेयजल आपूर्ति करती थी।

आलेख और छाया: पिंगी फुलवारिया

## झालाना का काली माता मंदिर





तस्वीर बदलाव की



तब



अब



राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम और अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी  
<https://jankalyan.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।

@DIPRRajasthan

